आज का विचार

चरित्र और कपड़े कितने भी चमकदार क्यों न हो, देखने वाला इनमें केवल दाग ही देखता है।

दैनिक
सिटी दर्पण
आईना सच का

सिटी दर्पण-राष्ट्रीय दैनिक हिंदी समाचार पत्र की अधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए स्कैन करें।

चंडीगढ़ । शनिवार, 9 मई, 2026 वर्ष 24, अंक 111, मूल्यः 3 रुपए, पृष्ठ 8 RNI Regn No.: CHAHIN/2003/09265 Established 2003 www.citydarpan.com

वतन की खातिर सबसे ज्यादा जानें कुर्बान करने वाले पंजाबियों पर देश विरोधी होने का ठप्पा लगा रही है भाजपा: मान

पंजाब के भाईचारे की मजबूत डोरियों को तोड़ने की साजिशें रच रही हैं सांप्रदायिक पार्टियां, नापाक मंसूबे सफल नहीं होने दूंगा: मुख्यमंत्री

सिटी दर्पण संवाददाता
बठिंडा

चार दिवसीय ह्यशुक्राना यात्राह्ल के आज तीसरे दिन मालवा क्षेत्र पहुंचकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भारतीय जनता पार्टी और सांप्रदायिक ताकतों पर प्रहार करते हुए कहा कि भगवा पार्टी पंजाबियों पर देश विरोधी होने का ठप्पा लगाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा वोटों के लिए पंजाब की सदियों पुरानी भाईचारे की मजबूत डोरियों को तोड़ने की गहरी साजिश रच रही है ।मुख्यमंत्री ने आज बठिंडा से यात्रा की शुरूआत की और श्री दमदमा साहिब में माथा टेका। विभिन्न स्थानों पर लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि पश्चिम बंगाल में शुरू की गई डर और बंटवारे की राजनीति अब पंजाब में लागू करने की साजिश रची जा रही है, जहां सांप्रदायिक ताकतें समाज के ध्रुवीकरण और सत्ता पर कब्जा करने के लिए भाईचारों को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं।

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि देश की आजादी और एकता के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां देने वाले पंजाबी ऐसी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देंगे।इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बेअदबी के मामलों में शामिल लोगों, जिनमें सरपरस्त भी शामिल हैं को अब नए कानून के तहत सख्त सजाएं भुगतनी पड़ेंगी, जिसमें उम्रकैद और 50 लाख रुपए तक का जुमार्ना शामिल है। तलवंडी साबो, बठिंडा शहर और कोटशमीर में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाबियों को राज्य की शांति, भाईचारे और सद्भावना के लिए घातक फूट डालो ताकतों के खिलाफ एकजुट होने आह्वान किया।

उन्होंने जोर देकर कहा कि सांप्रदायिक राजनीति को पंजाब की सदियों पुरानी भाईचारे की एकता में फूट डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पंजाब पंजाबियों का है का नारा लगाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, जो लोग भाईचारे की साझ को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वे पंजाब के दुश्मन हैं। भाजपा ने महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल में बंटवारे की राजनीति के जरिए सत्ता हासिल की है, लेकिन पंजाब में ऐसी साजिशें कभी सफल नहीं होंगी क्योंकि यहां के लोग हर त्योहार साझे तौर पर मनाते हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, सांप्रदायिक पार्टियां पंजाब के भाईचारे को तोड़ने की साजिश रच रही हैं और उनके घिनौने एजेंडे को सफल नहीं होने देना चाहिए। पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद वहां हालात बद से बदतर हो गए और लोगों के घरों में आग लगाई जा रही है। जब भाजपा ने पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई, हर तरफ डर का माहौल पैदा हो गया। अब पंजाब के लिए भी यही साजिश रची जा रही है।

उन्होंने कहा, पंजाबियों ने आजादी के संघर्ष में देश के लिए अनगिनत कुर्बानियां दी हैं और उन्हें देशभक्ति के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। 1947 के विभाजन का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उस दुखांत के दौरान पंजाब ने सबसे ज्यादा दुख झेले और लगभग 10 लाख पंजाबियों ने अपनी जानें गंवाईं, जबकि अब पंजाब की देशभक्ति पर सवाल उठाने वालों ने देश के लिए ऐसी कोई कुर्बानियां नहीं दीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ भाजपा नेता उन पर देशद्रोह के आरोप लगा रहे हैं, जबकि वे यह भूल रहे हैं कि पंजाबियों ने देश के लिए 90 प्रतिशत कुर्बानियां दी हैं और अब उन्हें गद्दार कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, देश के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां देने वाले पंजाबियों को अब भाजपा द्वारा देश विरोधी करार दिया जा रहा है। विरोधी नेताओं पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि सुनील जाखड़ जैसे नेताओं को अंतरजातीय मेल-मिलाप सहन नहीं हो रहा क्योंकि वे एक आम परिवार के बेटे को राज्य का मुख्यमंत्री बनकर ईमानदारी से पंजाब की सेवा करते नहीं देख पा रहे। कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने दोनों पार्टियों को लुटेरे बताया, जिन्होंने आम लोगों की भलाई को नजरअंदाज करते हुए दशकों तक पंजाब की दौलत लूटी। उन्होंने कहा, विरोधी पार्टियां पंजाब को लूटने का एक और मौका मांग रही हैं, लेकिन लोग अब इन्हें सत्ता में नहीं बल्कि जेल भेजेंगे। उन्होंने कहा कि शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल सत्ता में वापसी के सपने देख रहे हैं, लेकिन पंजाब के समझदार लोग उन लोगों को दोबारा कभी वोट नहीं देंगे, जिन्होंने बार-बार राज्य के साथ धोखा किया है।

सद्भाव यात्रा में राहुल गांधी बोले- भाजपा लोकतंत्र और किसानों पर हमला कर रही

गुरुग्राम की सद्भावना यात्रा में केंद्र सरकार पर जमकर बरसे विपक्ष के नेता

एजेंसी (हि.स.)
गुरुग्राम

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार शाम गुरुग्राम में सद्भाव यात्रा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर लोकतंत्र, संविधान और किसानों के अधिकारों पर हमला करने का आरोप लगाया।

इससे पूर्व राहुल गांधी खांडसा मंडी से लेकर एसडी स्कूल चौक तक सद्भाव यात्रा में शामिल हुए। पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह की ओर से यह यात्रा निकाली जा रही है। इसके बाद आयोजित जनसभा में राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा ने देश में चुनाव चोरी करने का सिस्टम बना लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में लाखों मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए और नए नाम जोड़े गए। चुनाव आयोग भी भाजपा के दबाव में काम कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा नेताओं को लगता है कि उनका शासन कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन अब देश की जनता सच्चाई समझ चुकी है। देश के लोग समझ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार देश की संपत्तियों को चुनिंदा उद्योगपतियों के हाथों बेचने का काम कर रही है ।राहुल गांधी ने उद्योगपति गौतम अडानी का नाम लेकर कहा कि एयरपोर्ट, पावर प्लांट, इंफ्रास्ट्रक्चर और यहां तक कि निकोबार द्वीपों तक को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश की जनता समझ रही है कि भाजपा सरकार अडानी-अंबानी मॉडल पर काम कर रही है, जहां कुछ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए नीतियां बनाई जा रही हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी कंपनी का नाम मोडानी होनी चाहिए। क्योंकि यह कंपनी बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी को हराएगी, फिर देखना हम क्या कार्रवाई करते हैं। इन्होंने लोकतंत्र खत्म किया है, हम इस बात को भूलने वाले नहीं। उन्होंने कहा कि छोटे उद्योग लगातार बंद हो रहे हैं और चीन का सामान भारत के बाजारों में बेचा जा रहा है।

राहुल गांधी ने एक बार फिर से एपस्टिन फाइल का जिक्र करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के अनेक सबूत अमेरिका में हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति कभी भी उनकी सरकार गिराने की धमकी दे देते हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति और अमेरिका के साथ हुई कथित डील पर भी सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि यह समझौता भारत के हितों के खिलाफ है और अमेरिका के दबाव में किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कृषि क्षेत्र को अमेरिकी किसानों के लिए खोल दिया गया है, जिससे भारत के छोटे किसान बर्बाद हो जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका के किसानों के पास हजारों एकड़ जमीन होती है, जबकि भारत में छोटे और सीमांत किसान खेती करते हैं। ऐसे में अमेरिकी कृषि उत्पाद भारतीय बाजार में आने से किसानों पर भारी असर पड़ेगा। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने अमेरिका से हर साल साढ़े नौ लाख करोड़ रुपये का सामान खरीदने की बात कही है, जिससे भारत की फैक्ट्रियां बंद होने का खतरा पैदा होगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि तेल खरीद को लेकर भी भारत की स्वतंत्र नीति कमजोर की गई है।

राहुल गांधी ने यह भी कहा कि देश का महत्वपूर्ण डेटा भी सुरक्षित नहीं है। अस्पतालों और अन्य संस्थानों से जुड़ा डेटा अमेरिका को सौंपा जा रहा है। इस पूरी डील से भारत को कोई लाभ नहीं मिला, बल्कि केवल अमेरिका को फायदा हुआ। राहुल गांधी ने अमेरिका में चर्चित एपस्टीन फाइल का जिक्र करते हुए कहा कि उसमें कई बड़े लोगों की जानकारी मौजूद है।

योगी सरकार में सख्त कानून व्यवस्था से प्रदेश में फिरौती के लिए अपहरण की एक भी घटना नहीं

सपा सरकार में हर दिन होते थे 19 दंगे और 33 अपहरण

एजेंसी (हि.स.)
लखनऊ

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की क्राइम इन इंडिया–2024 की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में फिरौती के लिए अपहरण की एक भी घटना नहीं हुई। जबकि सपा सरकार में वर्ष 2012 से 2017 के बीच की आई एनसीआरबी की रिपोर्ट में प्रतिदिन 19 दंगे होते थे, उसी उत्तर प्रदेश में पिछले नौ वर्षों में एक भी दंगा नहीं हुआ। इस अवधि में कुछ अराजक तत्वों ने जरूर दंगा भड़काने की कोशिश की, लेकिन योगी सरकार में सख्त कानून व्यवस्था ने दंगाइयों के मंसूबों पर पानी फेर दिया।

एनसीआरबी की वर्ष 2024 रिपोर्ट के अनुसार फिरौती के लिए अपहरण के मामले में उत्तर प्रदेश की अपराध दर (क्राइम रेट) शून्य दर्ज की गई है। देश के अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश इस मामले में सबसे बेहतर स्थिति में दिखाई देता है। रिपोर्ट के अनुसार नगालैंड में यह अपराध दर 0.7, मणिपुर में 0.6, अरुणाचल प्रदेश में 0.3 और मेघालय में 0.2 दर्ज की गई, जबकि उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा शून्य रहा। रिपोर्ट यह भी बताती है कि वर्ष 2023 में भी यूपी में इस श्रेणी में क्राइम रेट शून्य था।

यह बदलाव प्रदेश सरकार की अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति, सक्रिय पुलिसिंग और संगठित अपराधों पर लगातार कार्रवाई से संभव हुआ है। पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट, माफिया की संपत्तियों की जब्ती और अपराधियों की आर्थिक कमर तोड़ने जैसे सख्त कदमों का असर धरातल पर दिखाई दे रहा है।

सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश में पिछले नौ वर्षों में दंगे की एक भी घटना नहीं हुई। कुछ अराजक तत्वों ने दंगा भड़काने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन पुलिस ने उने सख्ती से निपटा। एनसीआरबी की 2024 रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में बलवा की अपराध दर 1.1 दर्ज की गई, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह दर 2.2 रही। यहां यूपी में बलवा की अपराध दर 1.1 दर्ज होने का आधार वही मामले हैं, जिनमें दंगा भड़काने की कोशिशों को योगी सरकार ने समय रहते विफल कर दिया और अराजक तत्वों के खिलाफ दंगा भड़काने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सार्वजनिक मंचों से कहते हैं, ह्यनो कर्फ्यू-नो दंगा, यूपी में सब चंगा।ह्य एनसीआरबी रिपोर्ट में मणिपुर में बलवा की अपराध दर 8.4, महाराष्ट्र में 6.4, कर्नाटक में 5.4, हरियाणा में 5.3 और हिमाचल प्रदेश में 4.7 दर्ज की गई है।

आगे कहा, उत्तर प्रदेश में एक समय ऐसा था जब दंगे, अपहरण और फिरौती जैसी घटनाएं आम चर्चा का विषय बन चुकी थीं। विशेष रूप से वर्ष 2012 से 2017 के बीच सपा सरकार के दौरान प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठते रहे।

मनोहर लाल ने आईआईटी रुड़की में रेगुलेटरी सेंटर का किया उद्घाटन

एजेंसी (हि.स.)
हरिद्वार

केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आईआईटी रुड़की में ह्यसेंटर फॉर रेगुलेटरी अफेयर्सह्ल का उद्घाटन किया। यह केंद्र फोरम ऑफ रेगुलेटर्स और आईआईटी रुड़की की संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य देश के विद्युत क्षेत्र की नियामकीय व्यवस्था को और अधिक मजबूत, पारदर्शी एवं भविष्य के अनुरूप बनाना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बढ़ती बिजली मांग, नवीकरणीय ऊर्जा के तेजी से विस्तार, डिजिटल तकनीकों के बढ़ते उपयोग और ऊर्जा बाजारों में हो रहे बदलावों को देखते हुए मजबूत नियामकीय ढांचे की आवश्यकता पहले से अधिक बढ़ गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह केंद्र रेगुलेटरी सैंडबॉक्सिंग और डिमांड फ्लेक्सिबिलिटी जैसे विषयों पर महत्वपूर्ण शोध और नीति निर्माण में सहयोग करेगा। उन्होंने बताया कि यह देश में इस प्रकार का दूसरा केंद्र है। इससे पहले आईआईटी दिल्ली में भी केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग और ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड के सहयोग से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा चुका है। कार्यक्रम में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग एवं फोरम ऑफ रेगुलेटर्स के अध्यक्ष जिष्णु बरुआ ने कहा कि यह केंद्र देश में नियामकीय क्षमता निर्माण का प्रमुख संस्थान बनेगा और उच्च गुणवत्ता वाले शोध एवं ज्ञान संसाधनों के माध्यम से भारत की ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व क्षमता को मजबूत करेगा। आईआईटी रुड़की के निदेशक के.के. पंत ने कहा कि यह केंद्र अकादमिक जगत, नीति निमार्ताओं, उद्योग और नियामकों को एक साझा मंच प्रदान करेगा, जिससे ऊर्जा संक्रमण और अवसंरचना प्रशासन से जुड़ी चुनौतियों के समाधान में मदद मिलेगी।

भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्वर, ड्रोन निर्माण में निवेश की संभावनाएं तलाश रहा गूगल : अश्वनी वैष्णव

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को कहा कि इंटरनेट क्षेत्र की दिग्गज कंपनी गूगूल भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्वर और ड्रोन निर्माण के क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं तलाश रही है। वैष्णव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर गूगल के अधिकारियों के साथ अपनी मुलाकात की जानकारी साझा करते हुए कहा कि कंपनी भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के क्षेत्रों में भी अवसरों का आकलन कर रही है।

वैष्णव ने कहा, गूगल भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्वर तथा ड्रोन के निर्माण के क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं तलाश रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह पहल देश में उभरते एआई इकोसिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब इसी वर्ष अप्रैल में गूगल ने विशाखापत्तनम में अपने 15 अरब डॉलर के एआई हब की आधारशिला रखी थी।

सरकार पहले से ही सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और एआई आधारित तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए कई नीतिगत कदम उठा रही है। गूगल की संभावित निवेश योजनाओं को इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

नायब सैनी ने पंजाब सरकार को घेरा, बोले- आज पंजाब के हालात पश्चिम बंगाल से भी बुरे

भूपेंद्र शर्मा
चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज अलग-अलग क्षेत्रों में हरियाणा व पंजाब सरकार से संबंधित तथ्यों और आंकड़ों की तुलना करते हुए पंजाब सरकार को फेल सरकार बताया। उन्होंने कहा कि पंजाब के हालात तो आज पश्चिम बंगाल से भी बुरे हो गए हैं। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी शुक्रवार को हरियाणा निवास में सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के खातों में लाभ राशि के सीधे हस्तांतरण उपरांत प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासनकाल में आम जनता पर अत्याचार होता था, लोगों को दिनदहाड़े मौत के घाट उतार दिया जाता था और पुलिस में एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी। कुछ ऐसे ही हालात आज पंजाब में हो गए हैं। पंजाब में नशा और कानून व्यवस्था सरकार के नियंत्रण से बाहर है। हाल ही में पंजाब में हुए बम ब्लास्ट के संबंध में पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं है जबकि वहां के डीजीपी के अनुसार इसके तार आईएसआई से जुड़े हो सकते हैं। पंजाब सरकार नशे व माइनिंग को नियंत्रित करने का झूठा दिखावा कर रही है।

उन्होंने कहा कि पहले पंजाब के लोग कांग्रेस के भ्रष्टाचार से तंग हो गए थे, लेकिन वर्तमान पंजाब सरकार तो भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस से भी चार कदम आगे निकल गई है। आज पंजाब के लोग इलाज के लिए तड़प रहे हैं, आम आदमी प्रताड़ित हो रहा है। पंजाब के लोग बदलाव चाहते हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर आने वाले विधानसभा चुनाव में पंजाब में भाजपा की सरकार बनाने का मन बना चुके हैं। पंजाब में भाजपा की सरकार बनने के बाद वहां भी वही योजनाएं लागू की जाएंगी जो हरियाणा में लागू की गई हैं। उनके पंजाब दौरों पर विपक्ष द्वारा उठाई जा रही आपत्ति के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के लोग उन्हें प्यार से अपने कार्यक्रमों में बुलाते हैं तो इससे विपक्ष के पेट में दर्द क्यों होता है।

विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के खातों में लाभ राशि के सीधे हस्तांतरण उपरांत प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने 55 साल के शासन के दौरान कांग्रेस ने देश को कमजोर, आम आदमी को परेशान और भ्रष्टाचार के सहारे अपने आप को मजबूत करने का काम किया है। कांग्रेस के पास न नीति है न काम करने की नीयत है और जब जनता इन्हें सिंहासन से उतारती है तो ये कहते हैं कि वोट चोरी हो गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हमारी सरकार को घुसपैठियों की सरकार कहते हुए जरा भी शर्म नहीं आती है जबकि सच्चाई यह है कि देश में जितने भी घुसपैठिए आए हैं वह सब कांग्रेस सरकार के समय आए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री श्री अमित शाह की दूरदर्शी सोच व रणनीति से घुसपैठियों को देश से बाहर का रास्ता दिखाया है और भारत को विश्व के एक मजबूत देश के रूप में स्थापित किया है। राहुल गांधी सरेआम संविधान का अपमान करने से भी नहीं चूकते हैं। कांग्रेस और आम आदमी सहित इंडिया गठबंधन के नेता रात को इकट्ठे बैठकर योजना बनाते हैं और दिन में मोदी जी को गाली देते हैं। उत्तर प्रदेश व राजस्थान के गत विधानसभा चुनावों में हरियाणा कांग्रेस ने भाजपा को हराने के लिए पैसा खर्च करके डमी उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन जनता ने इंडिया गठबंधन को असली आइना दिखा दिया। इन विपक्षी दलों का यही हाल अब पंजाब में भी होने वाला है। इंडिया गठबंधन के नेता लोकतंत्र का सम्मान नहीं करते और हार जाने के बावजूद कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं हैं। आम आदमी पार्टी द्वारा काफी पहले की गई घोषणा के बावजूद आज तक वहां महिलाओं को आर्थिक लाभ नहीं दिया गया। हरियाणा के वर्तमान बजट में महिलाओं के लिए 6500 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान करने के बाद पंजाब सरकार ने लोकदिखावा करते हुए आनन-फानन में विधानसभा में महिलाओं के लिए घोषणा कर दी जबकि अभी तक एक महिला को भी लाभ नहीं मिला है। इस मामले में पंजाब सरकार सिर पर आए चुनाव को देखकर केवल राजनीति कर रही है। इसके विपरीत हरियाणा में महिलाओं को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रतिमाह 2100 रुपये दिए जा रहे हैं जिसकी 7वीं किश्त आज महिलाओं के खातों में भिजवा दी गई है। हरियाणा सरकार ने न केवल इस बार के बजट में इस योजना की राशि को 5000 करोड़ से बढ़ाकर 6500 करोड़ कर दिया है बल्कि पात्र परिवार की सालाना आय की शर्त को 1 लाख से बढ़ाकर 1.80 लाख किया।

सीएम अब्दुल्ला ने भाजपा पर 'ब्लैकमेल की राजनीति' करने का लगाया आरोप

राज्य के दर्जे के मुद्दे को लेकर उमर अब्दुल्ला ने भाजपा पर तीखा हमला किया

- कहा, विपक्ष के नेता जम्मू-कश्मीर के मंत्री पद पर बैठने के लिए बेचैन

एजेंसी (हि.स.)

श्रीनगर

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को भाजपा पर राज्य के दर्जे के मुद्दे पर 'ब्लैकमेल की राजनीति' करने का आरोप लगाया और कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार में देरी केंद्र शासित प्रदेश के दर्जे से जुड़ी है न कि सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर किसी डर के कारण।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता की टिप्पणी का जवाब देते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि 'नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई एकनाथ शिंदे नहीं है' और जोर देकर कहा कि पार्टी के सभी विधायक एकजुट हैं। अब्दुल्ला ने यहां पत्रकारों से कहा, यह स्पष्ट है कि विपक्ष के नेता जम्मू-कश्मीर के मंत्री पद पर बैठने के लिए बेचैन हैं। परिसीमन को लेकर चल रही बहस का जिक्र करते हुए

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि जम्मू-कश्मीर में यह प्रक्रिया 'केवल भाजपा और उसके मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए' की गई थी। उन्होंने कहा, 'हमने उनके परिसीमन का कष्ट सहा है और हम परिसीमन के बारे में जानते हैं। यह केवल भाजपा और भाजपा के मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया था।' अब्दुल्ला ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार राजनीतिक अस्थिरता के कारण नहीं रुका है बल्कि इसलिए रुका है क्योंकि जम्मू-कश्मीर को अभी तक राज्य का दर्जा नहीं मिला है। राज्य का दर्जा न मिलने के कारण मंत्रिमंडल विस्तार रुका हुआ है। डर के कारण मंत्रिमंडल विस्तार नहीं रुका है। मुख्यमंत्री ने जम्मू-कश्मीर में चुनी हुई सरकार के कामकाज में बाधा डालने का आरोप भाजपा पर लगाया। उन्होंने कहा कि पक्षपात दल के नेता साहब अपने बयानों से यह साबित करते हैं कि जब तक भाजपा यहां सरकार नहीं बना लेती तब तक वे हमें ठीक से काम नहीं करने देंगे और जम्मू-कश्मीर को राज्य नहीं बनाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि जम्मू-कश्मीर के लोगों को राज्य के नाम पर धमकाया जा रहा है और कहा कि पिछले चुनाव में भाजपा को वोट देने वालों को याद रखना चाहिए कि पार्टी 'ब्लैकमेल की राजनीति' कर रही है।

टीवीके नेता विजय को सरकार बनाने से रोकने का कोई औचित्य नहीं : उमर

श्रीनगर। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को कहा कि तमिलनाडु के राज्यपाल के पास टीवीके नेता विजय को सरकार बनाने से रोकने का कोई औचित्य नहीं है और उन्हें विधानसभा में बहुमत साबित करने का अवसर दिया जाना चाहिए। अब्दुल्ला ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के कई फैसलों के मद्देनजर तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लगाने का कोई औचित्य नहीं है, जिनमें सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने और फिर सदन में अपना बहुमत साबित करने पर जोर दिया गया है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखें, तो राष्ट्रपति शासन नहीं होना चाहिए। ऐसे कई मामले हैं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि चुनाव के बाद सबसे बड़ी पार्टी को (सरकार गठन के लिए) आमंत्रित किया जाना चाहिए और उन्हें विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने का मौका दिया जाना चाहिए। अब्दुल्ला ने तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति के बारे में पूछे जाने पर यहां पत्रकारों से कहा कि ऐसा तब हुआ जब (पूर्व प्रधानमंत्री) वाजपेयी ने 13 दिनों के लिए सरकार बनाई। भारत के राष्ट्रपति ने उनके बहुमत का इंतजार नहीं किया। भारत के राष्ट्रपति ने उन्हें आमंत्रित किया सरकार 13 दिनों तक चली लेकिन जब वाजपेयी के पास बहुमत नहीं था, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया इसलिए अगर हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखें, तो तमिलनाडु के पास इस प्रक्रिया को रोकने का कोई औचित्य नहीं है। अब्दुल्ला ने कहा कि विजय को सरकार बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए और फिर उन्हें अपना बहुमत साबित करने का अवसर दिया जाना चाहिए और अगर वे साबित कर देते हैं, तो वे बने रहेंगे लेकिन अगर नहीं तो उन्हें इस्तीफा देना होगा।

कांग्रेस ने झूठी गारंटियों से कर्मचारियों को ठगा: सांसद प्रो. सिकंदर कुमार

- कहा, एनपीएस को मिल रहा ओपीएस से ज्यादा डीए

एजेंसी (हि.स.)

शिमला

हिमाचल प्रदेश में महंगाई भत्ते (डीए) को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। राज्यसभा सांसद प्रो. सिकंदर कुमार ने कांग्रेस सरकार पर कर्मचारियों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने से पहले ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) बहाल करने का वादा किया था, लेकिन अब उसी योजना को चुनने वाले कर्मचारी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।

प्रो. सिकंदर कुमार ने प्रदेश सरकार द्वारा जारी उस अधिसूचना पर सवाल उठाए हैं, जिसके तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत आने वाले कर्मचारियों को केंद्र सरकार की दरों के अनुसार महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से प्रदेश के हजारों ओपीएस कर्मचारियों में निराशा और असंतोष पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव के

दौरान ओपीएस बहाली को अपनी बड़ी गारंटी के रूप में पेश किया था। सरकार के भरोसे पर बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने ओपीएस को चुना, जबकि कुछ कर्मचारी एनपीएस में ही बने रहे। लेकिन अब स्थिति यह बन गई है कि एनपीएस कर्मचारियों को केंद्र सरकार की दरों के हिसाब से करीब 60 प्रतिशत डीए मिल रहा है, जबकि ओपीएस कर्मचारियों को राज्य सरकार की दरों के अनुसार केवल 45 प्रतिशत डीए दिया जा रहा है। सिकंदर कुमार ने कहा कि समान पद, समान काम और समान जिम्मेदारियों के बावजूद कर्मचारियों के बीच इस तरह का अंतर पूरी तरह भेदभावपूर्ण है। उनके मुताबिक सरकार अपनी अधिसूचना में खुद यह स्वीकार कर रही है कि एनपीएस कर्मचारियों को भविष्य की पेंशन से जुड़े लाभों में नुकसान हो रहा था, इसलिए उन्हें केंद्र सरकार की दरों पर डीए देने का फैसला लिया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि यही तर्क सही है तो ओपीएस चुनने वाले कर्मचारियों को कम डीए देकर आर्थिक नुकसान पहुंचाना कैसे उचित माना जा सकता है।

उन्होंने कहा कि ओपीएस को कर्मचारियों के हित में बताते हुए लागू किया गया था, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि ओपीएस चुनने वाले कर्मचारी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की यह नीति कर्मचारियों के बीच असमानता पैदा कर रही है और इससे कर्मचारियों का मनोबल भी गिर रहा है।

राज्यसभा सांसद ने प्रदेश सरकार से मांग की कि ओपीएस और एनपीएस कर्मचारियों के बीच डीए को लेकर बनाए गए इस अंतर को तुरंत खत्म किया जाए और सभी कर्मचारियों को समान दर पर महंगाई भत्ता दिया जाए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा कर्मचारियों के हितों के साथ खड़ी रही है और आगे भी कर्मचारियों की आवाज मजबूती से उठाती रहेगी।

मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के लिए 73.92 लाख रुपये का अंशदान

एजेंसी (हि.स.)

शिमला

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू को मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने मशोबरा रिजॉर्ट लिमिटेड की ओर से मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के लिए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत आज यहां 73.92 लाख रुपये का चेक भेंट किया। मशोबरा रिजॉर्ट लिमिटेड एक सरकारी उपक्रम कंपनी है, जिसे वाइल्डफ्लावर हॉल के संचालन की जिम्मेदारी प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने अंशदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार के योगदान से समाज के वंचित और जरूरतमंद वर्गों की सहायता में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में सफल कानूनी लड़ाई के उपरांत राज्य सरकार ने मशोबरा रिजॉर्ट लिमिटेड को सशक्त किया है, जिसके परिणामस्वरूप यह एक लाभकारी संस्थान के रूप में सकारात्मक परिणाम दे रही है। लगभग 120 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक वाइल्डफ्लावर हॉल लग्जरी होटल संपत्ति लगभग तीन दशकों तक कानूनी विवादों में घिरी रही। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के हस्तक्षेप के बाद राज्य सरकार ने प्रभावी तरीके से मुकदमा लड़ने के लिए कानूनी विशेषज्ञों की सेवाएं लीं।

झेलम नदी में डूबने से तीन युवकों की मौत शव बरामद

बांदीपोरा। उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा के हाजिन इलाके में झेलम नदी में डूबने से शुक्रवार को तीन युवकों की मौत हो गई। यह घटना चंदेरगीर चौक क्षेत्र में हुई, जब तीनों युवक नदी के किनारे तंबू का सामान धो रहे थे। एक अधिकारी ने बताया कि घटना के बाद स्थानीय निवासियों और स्वयंसेवकों ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया। शुरूआती अभियान में दो शव बरामद किए गए, जबकि तीसरा शव बाद में मिला। मृतकों की पहचान आदिल अहमद डार (18) पुत्र बशीर अहमद डार, समीर अहमद डार (22) पुत्र मोहम्मद जमाल डार और सोहेल अहमद डार (22) पुत्र गुलाम नबी डार के रूप में हुई है। ये सभी चंदेरगीर हाजिन के निवासी थे। शवों को चिकित्सा-कानूनी औपचारिकताओं के लिए पास के अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया और आगे की जांच जारी है।

कांग्रेस का सिरमौर में रहेगा दबदबा, जिला परिषद में भी बनेगा अध्यक्ष : हर्षवर्धन चौहान

एजेंसी (हि.स.)

नाहन

उद्योग मंत्री ने जिला सिरमौर में कांग्रेस की मजबूती का दावा करते हुए कहा कि इस बार जिला परिषद की 17 सीटों पर कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी और जिला परिषद में कांग्रेस का ही अध्यक्ष बनेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पिछले तीन वर्षों के दौरान विकास के नए आयाम स्थापित किए गए हैं, जिसका लाभ सीधे तौर पर आम जनता तक पहुंचा है।

उद्योग मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता विकास और मुद्दों की राजनीति में विश्वास रखती है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि बंगाल चुनाव का हिमाचल प्रदेश के पंचायत चुनावों पर किसी भी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा। यहां के लोग स्थानीय मुद्दों और विकास कार्यों को देखकर मतदान करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा गांव-गांव तक विकास कार्य पहुंचाए गए

हैं, जिससे जनता सरकार के कार्यों से संतुष्ट है। उन्होंने कहा कि आज वार्ड नंबर 6 सतौन से कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी द्वारा नामांकन भरा गया है और उन्हें पूर्ण विश्वास है कि जनता का भरपूर समर्थन मिलेगा तथा जीत निश्चित होगी। उद्योग मंत्री ने प्रत्याशी की सराहना करते हुए कहा कि वह लंबे समय से समाजसेवा के कार्यों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपने निजी खर्चे से गांव की सड़कों के निर्माण में सहयोग किया है तथा जरूरतमंद और गरीब लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने का कार्य भी किया है।

ऐसे समाजसेवी व्यक्तियों को क्षेत्र की जनता दिल से समर्थन देती है और यही कारण है कि लोग उन्हें अपने बीच लोकप्रिय नेता के रूप में देखते हैं।

संक्षिप्त-समाचार

किश्तवाड़ में शुक्रवार सुबह भूकंप के झटके

किश्तवाड़। जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में शुक्रवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.5 मापी गई। भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल आए। जानकारी के अनुसार भूकंप आज सुबह 09:57:54 बजे आया। इसका केंद्र किश्तवाड़ क्षेत्र में जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप का अक्षांश 33.289 उत्तर और देशांतर 76.739 पूर्व दर्ज किया गया। फिलहाल भूकंप से किसी तरह के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है। हल्की तीव्रता होने के कारण झटके कुछ ही इलाकों में महसूस किए गए। स्थानीय लोगों में कुछ देर के लिए दहशत का माहौल रहा।

कठुआ जिले के लखनपुर में एक अभियान के दौरान तीन गैंगस्टर गिरफ्तार

कठुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कठुआ जिले के लखनपुर इलाके में एक अभियान के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा वांछित तीन गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन गिरफ्तारियों को विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय अंतरराज्यीय आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सफलता बताया है। अधिकारियों के अनुसार आरोपी काफी समय से फरार थे और आपराधिक मामलों के सिलसिले में दिल्ली पुलिस की निगरानी में थे। विशिष्ट सूचनाओं पर कार्रवाई करते हुए लखनपुर पुलिस ने एक अभियान चलाया और तीनों को गिरफ्तार करने में सफल रही। आरोपियों की पहचान तुरंत आधिकारिक तौर पर उजागर नहीं की गई है। अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति कथित तौर पर आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे और कई मामलों में जांच के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा वांछित थे। यह अभियान लखनपुर कॉरिडोर पर कड़ी निगरानी और जांच के बीच चलाया गया जो जम्मू और कश्मीर में प्रवेश का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपियों की गतिविधियों पर नजर रखने और उन्हें गिरफ्तार करने में जम्मू-कश्मीर पुलिस और दिल्ली पुलिस के बीच समन्वय ने अहम भूमिका निभाई। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने इस अभियान को बड़ी सफलता बताया और कहा कि यह संगठित अपराध और भगोड़े गिरोहों के खिलाफ कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच बढ़ते समन्वय को दर्शाता है। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद आरोपियों को संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि आगे की जांच जारी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि आरोपियों के अन्य आपराधिक गिरोहों से संबंध थे या उन्होंने जम्मू-कश्मीर का इस्तेमाल पारगमन या छिपने की जगह के रूप में किया था।

कुलगाम पुलिस ने कुंड में ड्रग तस्करों के कब्जे से 60 लाख की जमीन मुक्त कराई

कुलगाम। नशा मुक्ति अभियान जम्मू-कश्मीर के तहत एक बड़ी कार्रवाई में कुलगाम पुलिस ने राजस्व अधिकारियों के साथ समन्वय में दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के कुंड इलाके में कथित ड्रग तस्करों के अनधिकृत कब्जे से लगभग 60 लाख मूल्य की कहचराई भूमि को मुक्त कराया। अधिकारियों ने कहा कि संयुक्त अभियान पुलिस स्टेशन कुंड के अधिकार क्षेत्र में आने वाले गांव ओरियल में चलाया गया, जहां कुल 06 कनाल कहचराई भूमि को कब्जे से मुक्त कराया गया। विवरण के अनुसार सर्वे नंबर 182 मिन के तहत 01 कनाल भूमि कथित ड्रग तस्कर गुलाम नबी भट्ट, फतेह मोहम्मद भट के दामाद के अनधिकृत कब्जे में पाई गई थी। सर्वे नंबर 142 के तहत अन्य 03 कनाल भूमि ड्रग तस्कर गुलाम नबी भट पुत्र अब्दुल गनी भट के कथित अवैध कब्जे में थी। इसके अलावा सर्वे संख्या 142 मिन के तहत 02 कनाल भूमि भी ओरियल कुंड गांव के उन व्यक्तियों से बरामद की गई। पुलिस ने कहा कि मुक्त कराई गई जमीन का अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 60 लाख है।

अनंतनाग में सीआरपीएफ जवान ने अपनी सर्विस गन से गोली मारकर की आत्महत्या

श्रीनगर। कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक सीआरपीएफ जवान ने कथित तौर पर अपनी सर्विस गन से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि यह घटना गुरुवार रात को दक्षिण कश्मीर के कोकरनाग में घटी। हरियाणा के रेवाड़ी निवासी कांस्टेबल सतीश कुमार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की 164 बटालियन में तैनात थे। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज करके आगे की जांच शुरू कर दी है।

नगरोटा में क्लिनिक की आड़ में चल रहा था प्रतिबंधित दवाएं बेचने का धंधा

धर्मशाला। जिला कांगड़ा पुलिस द्वारा नशे एवं प्रतिबंधित दवाइयों के अवैध कारोबार के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत नगरोटा बगवां पुलिस थाना के तहत एक निजी क्लिनिक में छापेमारी के दौरान प्रतिबंधित दवाओं की बड़ी खेप पकड़ी गई है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई की है। एसपी कांगड़ा अशोक रत्न ने बताया कि पुलिस की टीम कछियारी में थी तो सूचना मिली कि 53 मील से योल मार्ग पर स्थित आशु स्किन एंड ऑर्थो क्लिनिक में भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां अवैध रूप से रखकर खुलेआम बेची जा रही हैं। सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए नियमानुसार दबिश दी गई। कार्रवाई के दौरान स्वतंत्र गवाहों एवं ड्रग इंस्पेक्टर की मौजूदगी में क्लिनिक की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान आरोपी अनिल कुमार पुत्र हरवंश लाल निवासी गांव व डाकघर बरहमपुर, तहसील व जिला गुरदासपुर, पंजाब, उम्र 43 वर्ष के कब्जे से भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां बरामद की गईं, जिनमें 300 कैप्सूल ट्रमाडोल, 900 टैबलेट क्लोनाजेपम तथा 68 टैबलेट अल्प्राजोलम की बरामद हुईं।

हिमाचल में चार दिन बरसात, येलो-ऑरेंज अलर्ट जारी

एजेंसी (हि.स.)

शिमला

हिमाचल प्रदेश में मई महीने में मौसम का बिल्कुल अलग मिजाज देखने को मिल रहा है। आमतौर पर इस समय मैदानों से लेकर पहाड़ों तक गर्मी बढ़ने लगती है, लेकिन इस बार पहाड़ी इलाकों में ठंड अभी भी बनी हुई है।

हिल स्टेशनों शिमला व मनाली सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लोग अब भी गर्म कपड़े पहनने को मजबूर हैं, जबकि निचले और मैदानी इलाकों में भी गर्मी का असर सामान्य से कम है। लगातार हो रही बारिश, बादल और ठंडी हवाओं ने मौसम को बदला हुआ बना दिया है। शुक्रवार को भी राजधानी शिमला समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहे और कई जगह हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार 9 और 10 मई को मौसम साफ रहने की संभावना है, लेकिन यह राहत केवल दो दिन की होगी। इसके बाद 11 मई से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। इससे प्रदेश में फिर मौसम बिगड़ जाएगा।

मौसम विभाग ने 11 से 14 मई तक पूरे हिमाचल में खराब मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। 11 मई को बारिश, आंधी और बिजली गिरने का येलो अलर्ट रहेगा। 12 मई को मौसम सबसे ज्यादा खराब रहने की चेतावनी दी गई है और इस दिन कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 13 और 14 मई को फिर से येलो अलर्ट रहेगा। 11 और 12 मई को लाहौल-स्पीति और किन्नौर को छोड़कर बाकी 10 जिलों में खराब मौसम का असर देखने को मिल सकता है। 12 मई को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में तेज बारिश, आंधी और ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है।

वहीं ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन और सिरमौर जिलों में येलो अलर्ट रहेगा।

जम्मू और कश्मीर में 11 से 13 मई तक बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना

श्रीनगर। श्रीनगर मौसम विज्ञान केंद्र ने जम्मू और कश्मीर में 10 मई तक सामान्यतः शुष्क मौसम का पूर्वानुमान लगाया है जबकि 11 से 13 मई तक बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। मौसम संबंधी सलाह के अनुसार 8 और 9 मई को क्षेत्र में सामान्यतः शुष्क मौसम रहने की उम्मीद है हालांकि कुछ स्थानों पर दोपहर बाद हल्की बारिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। 10 मई को शाम तक मौसम अधिकतर शुष्क रहने की संभावना है जिसके बाद शाम और रात के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 11 से 13 मई तक सामान्यतः बादल छाए रहने और जम्मू और कश्मीर के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने का पूर्वानुमान लगाया है। इस दौरान कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि, गरज और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। विभाग द्वारा जारी एक सलाह में कश्मीर और जम्मू दोनों डिवीजनों में 10 मई की शाम/रात से 13 मई तक कुछ स्थानों पर गरज, बिजली और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। किसानों को मौसम की संभावित स्थिति को देखते हुए 10 मई तक कृषि कार्य जारी रखने की सलाह दी गई है। विभाग ने आगे कहा कि अगले तीन दिनों में कई स्थानों पर दिन का तापमान धीरे-धीरे 2-3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना है जिसके बाद 13 मई तक इसमें 3-5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी।

अनुराग ठाकुर दोबारा निर्वाचित हुए संसदीय पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सदस्य

एजेंसी (हि.स.)

हमीरपुर

पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर लोकसभा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर को संसद की सार्वजनिक लेखा समिति (पब्लिक अकाउंट्स कमेटी) के लिए वर्ष 2026-27 हेतु पुनः सदस्य निर्वाचित किया गया है। यह समिति सरकार के वित्तीय व्यय की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कार्य करती है तथा मुख्य रूप से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्टों की समीक्षा करती है। समिति का प्रमुख दायित्व यह सुनिश्चित करना होता है कि सार्वजनिक धन का उपयोग कानूनी, पारदर्शी एवं प्रभावी तरीके से किया गया है। इसके अतिरिक्त समिति विनियोग खातों की जांच, वित्तीय अनियमितताओं की पड़ताल तथा अनावश्यक खर्चों की पहचान भी करती है। लोकसभा एवं राज्यसभा के कुल 22 सदस्यों वाली इस समिति की अध्यक्षता कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल करेंगे। अनुराग सिंह ठाकुर को इससे पहले भी वर्ष 2024-25 तथा 2025-26 के लिए इसी समिति का

सदस्य चुना जा चुका है। उनकी पुनर्नियुक्ति संसदीय कार्यों, नीतिगत विमर्श एवं विधायी निगरानी में उनकी सक्रिय भूमिका को दर्शाती है। अनुराग सिंह ठाकुर वर्तमान में तीन महत्वपूर्ण संयुक्त संसदीय समितियों (जेपीसी) के सदस्य भी हैं। इनमें वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक पर गठित जेपीसी-129 शामिल है, जिसकी अध्यक्षता पी. पी. चौधरी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भ्रष्टाचार निरोधक तीन विधेयकों पर गठित जेपीसी-130, जिसकी अध्यक्षता अपराजिता सारंगी कर रही हैं, तथा देश में उच्च शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान पर गठित जेपीसी के भी वह सदस्य हैं, जिसकी अध्यक्षता दग्गुबती पुरन्देश्वरी कर रही हैं।

इश्क बना जान का दुश्मन, प्यार की रंजिश में दोस्त ने ही उतारा मौत के घाट

एजेंसी (हि.स.)

कठुआ

कठुआ में दो भाइयों पर हुए सनसनीखेज हमले के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए इसे प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला बताया है। पुलिस के अनुसार इस वारदात में मुख्य आरोपी मृतक का करीबी दोस्त ही निकला। प्रेस वार्ता के दौरान एसएसपी मोहिता शर्मा ने बताया कि आरोपी पारस वर्मा उर्फ सुमित पुत्र सोमराज निवासी वार्ड 9 कठुआ ने अपने ही दोस्त नकुल सिंह और उसके भाई निखिल पर क्रिकेट बैट से हमला किया। हमले में नकुल सिंह की मौके पर ही मौत हो गई जबकि निखिल गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल निखिल को एम्स विजयपुर में भर्ती कराया गया है जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस जांच में सामने आया है कि दोनों युवक एक ही लड़की से प्रेम करते थे। इसी प्रेम-रंजिश के चलते आरोपी पारस वर्मा मृतक के घर पहुंचा और अचानक हमला कर दिया। इस दौरान जब निखिल ने अपने भाई को बचाने की कोशिश की तो आरोपी ने उस पर भी बेरहमी से वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने बताया कि वारदात के बाद गायब हुआ फोन भी बरामद कर लिया गया है। इस ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाने के लिए कठुआ पुलिस ने विशेष जांच दल का गठन किया था। लगातार जांच और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने महज 25 घंटे के भीतर इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की आगे की जांच जारी है।

प्रेसवार्ता कहा, मंडी नगर निगम के चुनाव पूरी मजबूती से लड़े जाएंगे

मंडी नगर निगम में कांग्रेस लहराएगी विजयी परचम : विक्रमादित्य

एजेंसी (हि.स.)

मंडी

लोकनिर्माण मंत्री एवं नगर निगम चुनाव में कांग्रेस के प्रभारी विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भाजपा की सरकार के चलते मंडी नगर निगम के पहले चुनाव में भाजपा का कब्जा रहा। नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर भाजपा के ही थे। इसके बावजूद भाजपा नगर निगम मंडी में अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाई।

शुक्रवार को मंडी के गांधी भवन में पत्रकारों से बात करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि क्या कारण है कि भाजपा को नगर निगम चुनाव में ग्यारह नए चेहरे उतारने पड़े हैं। उन्होंने कहा कि यह अपने आप में इस चीज को दर्शाता है कि उनकी कार गुजरी के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जो पिछले पांच साल में रहे उनकी वजह से उनको अपने ही चेहतों के टिकट को काटकर नए चेहरों को उतरना पड़ा। अब एक बार फिर नगर निकाय के चुनाव प्रदेश के अंदर चल रहे हैं। पार्टी

के द्वारा जो जिम्मेदारी और दायित्व दिया गया है, उसका निर्वहन करने के लिए हम आप सबके बीच में यहां पर उपस्थित हैं। मंडी नगर निगम के चुनाव पूरी मजबूती से लड़े जाएंगे। विक्रमादित्य ने कहा कि पार्टी नेतृत्व के दिशा निर्देशों के साथ मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय नेताओं से विचार-विमर्श करने के बाद पार्टी के प्रत्याशियों का चयन किया गया। उन्होंने कहा कि शिक्षित, समाज सेवी और जनता से जुड़े हुए कैंडिडेट्स को चुनाव में उतारने का प्रयास कांग्रेस पार्टी का रहा है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हमने अच्छे उम्मीदवार मंडी नगर निगम के चुनाव में उतरे हैं। सबने अपने नामांकन दर्ज कर दिए हैं आगामी समय में चुनाव प्रचार गति पकड़ेगा तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और पार्टी की प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल और अन्य नेता चुनाव प्रचार में आएंगे। हम एक साफ विजन के साथ इस चुनाव को लड़ना चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि जो हमारे प्रत्याशी हैं उनके साथ बात करके मंडी शहर के लिए रोड मैप बनाया गया है। शहरी विकास मंत्रालय का दायित्व होने के साथ-साथ मंडी संसदीय क्षेत्र का चुनाव भी लड़ा था। हमने उसे समय भी यह बात कही थी कि मंडी के लिए हम बड़े प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं, चुनाव में हार जीत चली रहती है।

उन्होंने कहा कि हाल ही में शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलकर हिमाचल के लिए न चेलेंज फंड के माध्यम से 1200 करोड़ रुपए स्वीकृत करवाएं हैं। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री के साथ बैठकर उसपर चर्चा कर रूपरेखा तैयार की है। उसी से मंडी नगर निगम के लिए 180 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट स्वीकृत करवाने में सफल हुए हैं।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इस बार मंडी में इतिहास रचा जाएगा। मंडी नगर निगम मंडी में कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विजन डाक्यूमेंट में मंडी की इंदिरामार्किट की सीवरेज और ड्रेनेज की समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

दैनिक सिटी दर्पण आईना सच का

न्वोन्मेषक: स्व. कृष्णा शर्मा
स्व. गीता शर्मा

संस्थापक: स्व. सतपॉल शर्मा

स्वामी, प्रकाशक मुद्रक एवं संपादक भूपिंद्र शर्मा द्वारा इंप्रेशन्ज प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, प्लॉट नं. 22, ग्राउंड फ्लोर, फेस-2, इंडस्ट्रियल एरिया, पंचकूला-134113 (हरियाणा) पर मुद्रित एवं 801/1, सेक्टर 40ए, चंडीगढ़ से प्रकाशित-160036

सभी विवादों का केंद्र न्यायालय चंडीगढ़ होगा।

स्थानीय कार्यालय
801/1, सेक्टर-40ए, चंडीगढ़।

संपर्क: 7888450261
Email: citydarpan1@gmail.com

निपुण वाटिका के माध्यम से लर्निंग को रुचिकर और आसान बनाया गया है: महीपाल ढांडा

शिक्षा मंत्री ने रोहतक के गांव खरावड़ स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में निपुण वाटिका का किया उद्घाटन

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा ने कहा कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चें मेधावी एवं प्रतिभाशाली हैं। अध्यापक वर्ग इन बच्चों को अपनी मेहनत से सही दिशा देने का कार्य कर रहा है।जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने निपुण वाटिका के माध्यम से लर्निंग कार्य को रूचिकर व आसान बना दिया है।विद्यार्थी खेल-खेल में रूचि लेकर सीख रहे हैं।मंत्री रोहतक जिला के गांव खरावड़ स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में स्थापित की गई निपुण वाटिका का विधिवत उद्घाटन करने के उपरांत विद्यार्थियों के साथ संवाद कर रहे थे।

शिक्षा मंत्री ने जिला में शुरू की गई निपुण वाटिका व सुपर-40 की पहलों के लिए उपायुक्त सचिन गुप्ता, अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार व शिक्षा विभाग के अधिकारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि अधिकारियों ने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है। शिक्षा ने निपुण वाटिका का निरीक्षण करते हुए लर्निंग को रूचिकर और आसान बनाने के लिए किए गए प्रबंधों का गहनता से अवलोकन किया। उन्होंने विद्यार्थियों के साथ संवाद कर उनकी पढ़ाई, गतिविधियों और रुचियों के बारे में जानकारी ली। निपुण वाटिका में समूह बनाना, पहाड़े, त्रिभुज, वर्ग, आयत, बढ़ता व घटता क्रम, ऊंचाई मापना, आकृतियां बनाना, सम व विषम संख्या को पहचानना, मात्राओं का ज्ञान, देश का मानचित्र, स्वर, व्यंजन, अक्षर ज्ञान आदि को डिजिटल रूप से पढ़ाया जा रहा है। इससे बच्चें रूचि लेकर इन गतिविधियों को सीख रहे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। निपुण भारत मिशन के माध्यम से बच्चों की बुनियादी शिक्षा को मजबूत बनाया जा रहा है ताकि प्रारंभिक स्तर से ही विद्यार्थियों में पढ़ने, लिखने और समझने की क्षमता विकसित हो सके। उन्होंने अध्यापकों से भी आह्वान किया कि वे बच्चों को रचनात्मक एवं व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करें ताकि विद्यार्थी शिक्षा के साथ-साथ नैतिक मूल्यों को भी आत्मसात कर सकें।

इस अवसर पर उपायुक्त सचिन गुप्ता, अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी मनजीत मलिक, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी दिलजीत सिंह व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।इस दौरान शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा ने प्रेस प्रतिनिधियों से संवाद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि देश के प्रतिभाशाली बच्चों की क्षमता को बचपन से ही सही दिशा और उचित वातावरण देकर निखारा जाए। इसी उद्देश्य के तहत प्रदेश में निपुण वाटिका और सुपर-40 जैसी अभिनव पहलें बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों को खेल-खेल में पढ़ाना, लिखना सिखाना और उनकी झिझक को दूर करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है।

टीबी मुक्त हरियाणा के लक्ष्य की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है प्रदेश : आरती सिंह राव

- 30 दिन की जांच में मिले 10,978 नए टीबी मरीज
- राज्य सरकार टीबी के पूर्ण उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि ह्यटीबी मुक्त हरियाणा के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। व्यापक जन-जागरूकता अभियान, आधुनिक तकनीक और सामुदायिक भागीदारी के चलते टीबी उन्मूलन को नई गति मिली है।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 24 मार्च 2026 (विश्व टीबी दिवस) से शुरू किए गए 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान (फेज-2) की 30 दिन की अंतरिम प्रगति रिपोर्ट जारी की गई है। इस अभियान के तहत अब तक 10,978 नए टीबी मरीजों की पहचान की जा चुकी है। यह सफलता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीकों और सक्रिय केस खोज रणनीति के कारण संभव हुई है।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अब राज्य की रणनीति केवल मरीजों के सामने आने का इंतजार करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में जाकर लक्षण रहित लोगों की भी जांच की जा रही है, ताकि छिपे हुए मामलों की समय रहते पहचान हो सके।

आरती सिंह राव ने बताया कि हरियाणा में तकनीक का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एआई-सक्षम हैंडहेल्ड एक्स-रे मशीनें दूरदराज क्षेत्रों में तुरंत जांच की सुविधा दे रही हैं।कफ अगेंस्ट टीबी ऐप खांसी की आवाज का विश्लेषण कर संभावित मरीजों की पहचान करने में मदद कर रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉ. आर.एस. ढिल्लों ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि इस अभियान की सफलता में जनभागीदारी की अहम भूमिका रही है। 65 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स को ह्यचलती-फिरती लैब के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों में भी जांच संभव हो पाई है।

साथ ही जनप्रतिनिधियों और पंचायत संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी से टीबी से जुड़ी सामाजिक भ्रांतियों को दूर करने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत टीबी जांच को सामान्य स्वास्थ्य जांच के साथ जोड़ा गया है, जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर और एनीमिया की जांच भी शामिल है, ताकि समग्र स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा जियोस्पेशियल तकनीक के माध्यम से 2,111 संवेदनशील गांवों और वार्डों की पहचान कर वहां विशेष अभियान चलाया जा रहा है।उन्होंने उक्त अभियान के तहत 24 मार्च से 5 मई 2026 तक की गई गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि इस अवधि में कुल 1620 शिविर आयोजित किए गए, जिनमें से 938 उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में लगाए गए। इसी प्रकार 1,81,221 लोगों की स्क्रीनिंग की गई , 49,953 एनएएटी टेस्ट किए गए ,10,978 नए टीबी मरीजों की पहचान की गई।

उन्होंने आगे बताया कि उक्त अवधि में 335 नए निक्षय मित्र पंजीकृत किए गए जबकि 8502 पोषण किट वितरित की गई हैं।उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार टीबी के पूर्ण उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है और हर मरीज तक उपचार व सहायता पहुंचाना सुनिश्चित किया जा रहा है।

हरियाणा के राज्यपाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की शिष्टाचार भेंट

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा के राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने आज अपनी धर्मपत्नी श्रीमती मित्रा घोष के साथ नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार भेंट की।

इस अवसर पर राज्यपाल ने राष्ट्रपति के साथ हरियाणा के समग्र विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की।बातचीत के दौरान महिला सशक्तिकरण, समावेशी विकास, शिक्षा, सामाजिक कल्याण तथा समाज के सभी वर्गों में महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित पहलों को और अधिक सुदृढ़ बनाने पर विशेष बल दिया गया। प्रो. असीम कुमार घोष ने राष्ट्रपति को हरियाणा में संचालित विभिन्न विकासात्मक पहलों एवं जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी भी दी। उन्होंने राज्य की प्रगति और जनहित के प्रति राष्ट्रपति द्वारा निरंतर दिए जा रहे मार्गदर्शन, प्रोत्साहन एवं सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया।

चौड़ी कतारों में गन्ना रोपण करने वाले किसानों को अब मिलेंगे 5000 रुपए : श्याम सिंह राणा

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि ‘गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन’ के अंतर्गत जो किसान अब 4 फुट की दूरी पर चौड़ी कतारों में गन्ना रोपण करेगा, उसको सरकार द्वारा 5 हजार रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पहले यह प्रोत्साहन राशि 3 हजार रुपए प्रति एकड़ दी जा रही थी। श्री राणा ने यह जानकारी आज यहां विभागीय बैठक की अध्यक्षता करने के बाद दी है।

उन्होंने कृषि एवं इससे जुड़े विभिन्न कार्यों एवं योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को उचित दिशा - निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा का किसान केवल अन्नदाता नहीं बल्कि राज्य की आर्थिक और सामाजिक स्थिरता का सशक्त आधार भी है ,इसलिए किसान को मजबूत करना वर्तमान सरकार की प्राथमिकताओं में शुमार है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने बताया कि पहले जो किसान 4 फुट की दूरी पर चौड़ी कतारों में गन्ना की रोपाई करता था तो सरकार द्वारा उसको प्रोत्साहन के तौर पर 3 हजार रुपए प्रति एकड़ दिए जाते थे , लेकिन मुख्यमंत्री ने इस बार के बजट में यह राशि बढाकर 5 हजार रुपए प्रति एकड़ करने की घोषणा की थी , इस घोषणा को अमलीजामा पहनाते हुए सरकार की ओर से इस संबंध में स्वीकृति दे दी गई है।

उन्होंने बताया कि उक्त प्रोत्साहन राशि को प्राप्त करने के लिए गन्ना उत्पादक किसानों को पोर्टल के माध्यम से 15 अक्तूबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक आवेदन किया जाएगा , इसके बाद फरवरी 2027 के अंत तक भौतिक सत्यापन उपरांत संबंधित किसान को प्रोत्साहन राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।

उन्होंने आगे बताया कि किसानों को एकल-आँख विधि से गन्ने की बिजाई करने पर प्रोत्साहन राशि भी बढ़ाकर 5 हजार रुपए प्रति एकड़ कर दी गई है , पहले यह राशि 3 हजार रुपए प्रति एकड़ थी। श्री श्याम सिंह राणा यह भी जानकारी दी कि प्रदेश की प्रत्येक सहकारी चीनी मिल अपने क्षेत्र के किसानों को शुगरकेन हार्वेस्टर मशीन उपलब्ध करवाएगी ताकि किसानों की फसल कटाई पर लागत कम हो सके।

उन्होंने यह भी बताया कि टिश्यू कल्चर के माध्यम से गन्ना की उत्पादकता में वृद्धि की जाएगी। इस विधि से तैयार हुई गन्ना की पौध को किसानों को मुफ़्त उपलब्ध करवाया जाएगा। करनाल सहकारी चीनी मिल द्वारा ये पौध तैयार की जाएगी।इस मिल से किसान अक्तूबर 2026 से लेकर दिसंबर 2026 तक पौध ले सकता है।

श्री राणा ने कहा कि ये सभी पहल राज्य में कृषि को आधुनिक बनाने, किसानों की आय बढ़ाने और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगी। इस अवसर बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विजयेंद्र कुमार , निदेशक श्री राजनारायण कौशिक के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

संक्षिप्त-समाचार

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 24 मई को, फरीदाबाद में 37, गुरुग्राम में 52 परीक्षा केंद्र

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने आगामी 24 मई को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा ली जाने वाली सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा-2026 के सुचारू संचालन के लिए सम्बन्धित जिलों में पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। परीक्षा के संचालन के लिए फरीदाबाद में 37 तथा गुरुग्राम में 52 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने आज परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों के पुलिस आयुक्त, उपायुक्त तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाओं, कानून-व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, सुरक्षा इंतजामों तथा परीक्षा के निष्पक्ष एवं सुचारू संचालन से संबंधित अन्य प्रबंधों की विस्तृत समीक्षा की। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परीक्षा केंद्रों पर पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं तथा सभी संबंधित विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाकर रखा जाए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, निर्बाध बिजली आपूर्ति, सुगम परिवहन सुविधाएं और प्रभावी भीड़ प्रबंधन के लिए समय रहते सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी दिशा-निदेर्शों का सख्ती से पालन करने के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि परीक्षा ड्यूटी पर तैनात सभी अधिकारी और कर्मचारी पूरी सतर्कता, ईमानदारी और पेशेवर तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन करें ताकि परीक्षा निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके।

कल्याणकारी कार्यों के लिए सभी संस्थाओं को होना होगा एकजुटः रमेश चौधरी

कुरुक्षेत्र। जिला रेडक्रॉस सचिव रमेश चौधरी ने कहा कि जिला रेड क्रॉस शाखा कुरुक्षेत्र द्वारा 8 मई को रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक हेनरी डुनानट का जन्म दिवस को विश्व रेडक्रॉस दिवस में मनाया गया। जिला रेड क्रॉस समिति कुरुक्षेत्र रेड क्रॉस भवन में आयोजित कार्यक्रम में सर्वप्रथम हेनरी ड्यूनेन्ट की फोटो पर माल्यार्पण करके पुष्प अर्पित किए गए। भारतीय रेड क्रॉस समिति हरियाणा राज्य शाखा चण्डीगढ़ के वाइस चेयरमैन अंकुश मिगलानी एवं महासचिव डॉक्टर सुनील कुमार वजिला रेडक्रॉस सोसायटी चेयरमैन एवं उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा के कुशल मार्गदर्शन में कार्य कर रही है। जिला प्रशिक्षण अधिकारी अंजू कश्यप द्वारा हेनरी ड्यूनेन्ट की जीवनी पर प्रकाश डाला गया। जिला रेडक्रॉस सचिव रमेश चौधरी ने कहा कि उपायुक्त एवं प्रधान जिला रेड क्रॉस शाखा विश्राम कुमार मीणा के नेतृत्व आज विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आज रैड दिवस के अवसर पर सबसे पहले जिला रेडक्रॉस द्वारा सचिव रमेश चौधरी द्वारा श्री राम कुष्ठ आश्रम में रह रहे परिवारों को फल पैकेट वितरित किए गए और केक काट कर सबको वितरित किया गया। इसी अवसर पर ब्लड सेंटर नागरिक हस्पताल में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। जिसमें 31 युवाओं ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। विश्व रैड क्रॉस डे के अवसर पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कुलपति सोमनाथ सचदेवा द्वारा 33 विद्यार्थियों को रैड क्रॉस मेरिट सर्टिफिकेट प्रदान किए गए तथा महामहिम राज्यपाल का संदेश सुनाया गया। सचिव रैड क्रॉस द्वारा भी प्रतिभागियों को रैड क्रॉस की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया। फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट कुरुक्षेत्र के स्टाफ व विद्यार्थियों के साथ भी वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया गया। इस अवसर पर सभी को महामहिम का संदेश भी दिखाया गया। इसके साथ ही रेडक्रॉस गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया गया। कार्यक्रम में युवाओं को नशा न करने की शपथ भी दिलवाई गई। इसके साथ ही प्रेरणा वृद्ध में रह रहे वृद्धजनों को फल पैकेट प्रदान कर उनका आशीर्वाद लिया। टीबी कॉर्डिनेटर एवं स्वयंसेवकों द्वारा स्लम एरिया में जाकर टीबी जागरूक कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर विभिन्न स्कूलों में नशा मुक्ति जागरूकता अभियान एवं फर्स्ट एड की जानकारी दी गई।

एचसीएस अधिकारियों की एपीआर दर्ज करने की समय-सीमा बढ़ी

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा सरकार ने हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के अधिकारियों की वर्ष 2025झ्र26 की वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (पीएआर) दर्ज करने समय-सीमा एक महीने के लिए बढ़ा दी है।

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी एक पत्र के अनुसार, अब एचसीएस अधिकारियों को 31 मई की बजाय 30 जून, 2026 तक अपना स्व-मूल्यांकन प्रस्तुत करना होगा। रिपोर्टिंग प्राधिकारी को 31 अगस्त तक मूल्यांकन पूरा करना होगा। रिव्यूइंग प्राधिकारी को 31अक्टूबर तक समीक्षा करनी होगी, जबकि स्वीकार करने वाले प्राधिकारी द्वारा 31 दिसंबर, 2026 तक रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा।

गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने सभी विभागों को एचसीएस (कार्यकारी शाखा) अधिकारियों की वर्ष 2025झ्र26 की वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट राज्य के इंट्रानेट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।एचसीएस अधिकारियों की एपीआर वेबसाइट पर ऑनलाइन दर्ज की जाएगी और इसे 31 दिसंबर, 2026 तक अंतिम रूप देना अनिवार्य होगा। सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों तथा बोर्डों और निगमों के प्रमुखों को इन निदेर्शों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। अधिकारी एचआरएमएस पोर्टल पर उपलब्ध अपने पेयी कोड और पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से पोर्टल पर लॉगिन कर सकेंगे। सत्यापन के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर पर वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) भेजा जाएगा।इसके अतिरिक्त डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) अथवा स्कैन किए गए हस्ताक्षर अपलोड कर भी प्रमाणीकरण किया जा सकेगा। 40 वर्ष से अधिक आयु के एचसीएस अधिकारियों के लिए स्वास्थ्य जांच अनिवार्य की गई है और स्व-मूल्यांकन के साथ मेडिकल रिपोर्ट का सारांश भी अपलोड करना होगा। कार्य निष्पादन का मूल्यांकन 1 से 10 के पैमाने पर संख्यात्मक ग्रेडिंग प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। इसमें कार्य निष्पादन, व्यक्तिगत गुणों तथा कार्यात्मक दक्षताओं को शामिल किया जाएगा। ऑनलाइन प्रणाली में यह व्यवस्था भी की गई है कि यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर संबंधित प्राधिकारी द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है तो रिपोर्ट स्वतः अगले स्तर पर अग्रेषित हो जाएगी, ताकि मूल्यांकन प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके।

हरियाणा में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध चिंताजनकः कुमारी सैलजा

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

सिरसा की सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, सीडब्ल्यूसी की सदस्य एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव कुमारी सैलजा ने एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जिस प्रकार हरियाणा महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में देश में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है, वह बेहद गंभीर और चिंताजनक स्थिति है।

सासंद कुमारी सैलजा ने कहा कि एनसीआरबी के आंकड़े साफ संकेत दे रहे हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था लगातार कमजोर हुई है। रिपोर्ट के अनुसार नाबालिग लड़कियों की तस्करी के मामलों में हरियाणा देश में सबसे आगे है और महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। यह स्थिति हरियाणा जैसे प्रगतिशील प्रदेश के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। कुमारी सैलजा ने कहा कि हरियाणा को विकास, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में देश के लिए उदाहरण बनना चाहिए था, लेकिन आज प्रदेश अपराध, भय और असुरक्षा की घटनाओं के कारण चर्चा में है। महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा को लेकर आम परिवारों में चिंता का माहौल है।सांसद ने कहा कि प्रदेश में बढ़ता नशा और बेरोजगारी भी अपराधों में वृद्धि का बड़ा कारण बन रहे हैं। युवाओं के सामने रोजगार के अवसर सीमित होते जा रहे हैं, जिसके कारण अपराध और गैंगवार जैसी घटनाओं में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। यह स्थिति समाज के लिए बेहद खतरनाक संकेत है।

कुमारी सैलजा ने प्रदेश सरकार से मांग की कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सख्त और ठोस कदम उठाए जाएं। साथ ही नशे के नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई की जाए तथा युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि केवल दावे और प्रचार से स्थिति नहीं सुधरेगी, सरकार को जमीन पर परिणाम देने होंगे। सांसद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश की महिलाओं, युवाओं और आम जनता की सुरक्षा एवं सम्मान के मुद्दे को मजबूती से उठाती रहेगी और सरकार को उसकी जिम्मेदारी का अहसास कराती रहेगी। सांसद ने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार देश में 2024 में लडकियों की तस्करी के 1659 केस हुए इनमें सबसे ज्यादा हरियाणा में दर्ज हुए। लोकसेवकों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार के मामले में हरियाणा देश में तीसरे स्थान पर है।अवैध हथियारों के मामले में हरयिाणा देश में पांचवें स्थान पर है। कुमारी सैलजा ने आज प्रातः केदारनाथ मंदिर में बाबा केदारनाथ जी के पावन दर्शन कर विधिवत पूजा-अर्चना की।

भव्य तरीके से आयोजित किया जाए सोमनाथ स्वाभिमान पर्वः सीपीएससीएम राजेश खुल्लर

- 11 मई को देशभर में मनाया जाएगा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व
- सभी जिला उपायुक्तों को वीसी के माध्यम से दिए दिशा निर्देश

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर ने शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन से प्रदेश के सभी जिलाउपायुक्तों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की।इस दौरान उन्होंने सभी को निर्देश दिए कि आगामी 11 मई को भव्य तरीके से सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाए।इसे लेकर जिलास्तर पर सभी तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएं। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर भारत की अजेय सभ्यता का प्रतीक है।विनाशकारी प्रहारों के बाद भी सोमनाथ मंदिर आज हमारे आत्म-सम्मान और साहस की मिसाल बनकर खड़ा है। 75 वर्ष पहले आधुनिक सोमनाथ मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ। 11 मई 2026 को पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वयं सोमनाथ मंदिर पहुंचेंगे।इस दिन देशभर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व भव्य रूप से मनाया जाएगा। इस दौरान कलश यात्रा, आध्यात्मिक आयोजन, भारत की विरासत परंपरा पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। सीपीएससीएम श्री राजेश खुल्लर ने सभी जिला उपायुक्तों को इस कार्यक्रम को भव्य तरीके से आयोजित करने के निर्देश दिए। सीपीएससीएम श्री राजेश खुल्लर ने कहा कि 11 मई को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सोमनाथ मंदिर से लाइव संबोधन रहेगा।यह लाइव टेलिकास्ट प्रत्येक जिले में आयोजित होने वाले जिलास्तरीय कार्यक्रम में दिखाया जाएगा। जिलास्तर पर कलश यात्रा का आयोजन होगा, जिसका समापन शिव मंदिर में जलाभिषेक से होगा। उन्होंने कहा कि जन प्रतिनिधियों को भी कार्यक्रम का निमंत्रण दिया जाए।

सुपवा की अभिव्यंजना को लेकर कला प्रेमियों में उत्साह, अब कल तक चलेगी प्रदर्शनी

सिटी दर्पण संवाददाता
रोहतक

दादा लख्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स (डीएलसीसुपवा) में फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स की ओर से आयोजित 11वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी अभिव्यंजना का शुक्रवार को छठा दिन रहा। कला प्रेमियों व छात्रों के बढ़ते उत्साह को देखते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने प्रदर्शनी की अवधि दो दिन और बढ़ा दी है। अब यह प्रदर्शनी 10 मई तक जारी रहेगी। शुक्रवार को पूर्व आईएएस अधिकारी व मोटिवेशनल स्पीकर विवेक अत्रे ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और छात्रों को मोटिवेट किया।

यूनिवर्सिटी पहुंचने पर फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स के कोऑर्डिनेटर विनय कुमार और स्टाफ सदस्यों ने विवेक अत्रे का स्वागत किया।इसके बाद उन्होंने फैकल्टी ऑफ डिजाइन की बिल्डिंग में लगी प्रदर्शनी का बारीकी से अवलोकन किया। छात्रों ने अपनी कलाकृतियों के पीछे की सोच और विषयवस्तु के बारे में विस्तार से जानकारी दी। विवेक अत्रे ने खुद भी चित्रों में रंग भरकर अपनी कलात्मक रुचि का परिचय दिया।बाद में एफटीवी डिपार्टमेंट के मिनी ऑडिटोरियम में आयोजित संवाद कार्यक्रम में यूनिवर्सिटी के कुलगुरु डॉ. अमित आर्य ने उनका स्वागत कर स्मृति चिन्ह भेंट किया। छात्रों को संबोधित करते हुए विवेक अत्रे ने कहा कि अभिव्यंजना में आकर उन्हें बेहद सकारात्मक अनुभव हुआ।यहां के छात्र बहुत प्रतिभाशाली, रचनात्मक व ऊर्जा से भरपूर हैं।उन्होंने कहा कि उन्होंने देश-विदेश की अनेक प्रतिष्ठित प्रदर्शनियां देखी हैं, लेकिन सुपवा की यह प्रदर्शनी किसी भी शीर्ष प्रदर्शनी से कम नहीं है। उन्होंने पोलैंड के प्रसिद्ध पियानिस्ट पादेरेव्स्की का उदाहरण देते हुए छात्रों को अपनी रचनात्मकता को निरंतर विकसित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि जीवन में दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलना आवश्यक है।सफलता केवल पैसे या प्रसिद्धि हासिल करने का नाम नहीं, बल्कि भीतर की संतुष्टि व आत्मिक शांति का अनुभव है।कई बार एक साधारण व्यक्ति भी वह खुशी व संतोष महसूस कर लेता है, जो बड़े से बड़ा अमीर व्यक्ति नहीं कर पाता। इसलिए इंसान को हमेशा अपने पास मौजूद चीजों के प्रति आभारी और संतुष्ट रहना चाहिए। जब व्यक्ति के भीतर संतोष, कृतज्ञता व सकारात्मक सोच होती है, तभी वह वास्तविक अर्थों में शीर्ष तक पहुंचता है।

विवेक अत्रे ने कहा कि कुलगुरु डॉ. अमित आर्य और स्टाफ सदस्यों से बातचीत के दौरान उन्हें महसूस हुआ कि सुपवा का पूरा परिवार रचनात्मकता व सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है।जब किसी संस्थान में छात्र, शिक्षक व नेतृत्व एकजुट होकर कार्य करते हैं और उनका विजन स्पष्ट होता है, तभी वह संस्थान इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस बनता है। उन्होंने विश्वास जताया कि सुपवा आने वाले समय में नई ऊंचाइयों को छुएगा।

जौहर, प्रकृति व भाईचारे की थीम पर बनीं अनोखी कलाकृतियां

प्रदर्शनी में छात्रों ने अपने हुनर को बेहद अनोखे अंदाज में प्रस्तुत किया है। पेड़ों की छाल, जूट व घास का उपयोग कर तैयार की गई कलाकृतियां विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इनमें रानी पद्मावती द्वारा चित्तौड़गढ़ में किए गए जौहर की ऐतिहासिक घटना को भी दशार्या गया है। छात्रों ने उस स्थान को कलात्मक रूप में उकेरा है, जहां रानी पद्मावती ने जौहर किया था। इसके अलावा टाइल के टुकड़ों से तैयार कलाकृतियों में आपसी भाईचारे, छात्र जीवन व प्रकृति के सौंदर्य को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स के कोऑर्डिनेटर विनय कुमार ने बताया कि प्रदर्शनी में प्रदर्शित प्रत्येक कलाकृति के पीछे एक कहानी छिपी हुई है। उसी कहानी और भावना को थीम बनाकर छात्रों ने अपने आर्टवर्क तैयार किए हैं।

सुबह 10 से शाम 6 बजे तक देख सकेंगे प्रदर्शनी

पहले इस प्रदर्शनी का समापन 8 मई को होना था, लेकिन लगातार बढ़ रही दर्शकों की संख्या व विभिन्न स्कूलों से पहुंच रहे छात्रों के उत्साह को देखते हुए इसकी अवधि बढ़ा दी गई है। यूनिवर्सिटी के कुलगुरु डॉ. अमित आर्य ने बताया कि अब लोग 10 मई तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक यूनिवर्सिटी परिसर में आकर प्रदर्शनी का आनंद ले सकते हैं। प्रदर्शनी के शाम के सत्र में आयोजित ओपन स्टेज कार्यक्रम भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। फैकल्टी ऑफ डिजाइन बिल्डिंग के कोर्टयार्ड में शाम साढ़े छह बजे से रात आठ बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें छात्र म्यूजिक, डांस, कविता पाठ और अभिनय से जुड़ी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। बुधवार शाम छात्रों ने हरियाणवी, पंजाबी व राजस्थानी लोकनृत्यों के साथ-साथ बॉलीवुड गीतों पर शानदार प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का खूब मनोरंजन किया।

संपादकीय

ह्यूमनॉइड रोबोट्स: एक नई सुबह या अनजान खतरे की दस्तक?

मानव जाति ने हमेशा से यह सपना देखा है कि एक दिन ऐसी मशीनें बनेंगी जो इंसानों की तरह सोच सकें, चल सकें और काम कर सकें। यह सपना अब धीरे-धीरे हकीकत बनता जा रहा है। ह्यूमनॉइड रोबोट्स, यानी मानव आकृति वाले रोबोट, अब केवल विज्ञान कथाओं की कल्पना नहीं रहे। ये अब हमारे कारखानों, अस्पतालों और यहाँ तक कि घरों में दस्तक देने लगे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनका आगमन उतनी तेजी से हो रहा है जितनी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। दुनिया के बड़े-बड़े तकनीकी विशेषज्ञ और वैज्ञानिक भी इस रफ़्तार को देखकर दंग रह गए हैं। पिछले कुछ वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने जो छलांग लगाई है, उसने रोबोटिक्स की दुनिया को भी पूरी तरह बदल दिया है। पहले रोबोट केवल एक निश्चित काम करने के लिए बनाए जाते थे, जैसे कि किसी कारखाने में एक ही पेंच कसना या किसी उत्पाद को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। लेकिन आज के ह्यूमनॉइड रोबोट इससे कहीं आगे निकल चुके हैं। ये रोबोट न केवल चल-फिर सकते हैं, बल्कि जटिल वातावरण में निर्णय भी ले सकते हैं। टेस्ला का ऑप्टिमस, बोस्टन डायनेमिक्स का एटलस और चीन की कई कंपनियों के रोबोट इस क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहे हैं। ये रोबोट अब सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, भारी सामान उठा सकते हैं और यहाँ तक कि इंसानों के साथ मिलकर काम भी कर सकते हैं। इस तकनीकी क्रांति के पीछे मुख्य कारण है कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का तेजी से विकास। आज के रोबोट अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। जिस तरह एक बच्चा बार-बार गिरकर चलना सीखता है, उसी तरह ये रोबोट भी अपने अनुभव से खुद को बेहतर बनाते रहते हैं। इसके अलावा सेंसर तकनीक, बैटरी क्षमता और कंप्यूटिंग शक्ति में भी अभूतपूर्व सुधार हुए हैं जिसने इन रोबोट्स को और अधिक कुशल और स्वायत्त बना दिया है। उद्योग जगत में इन रोबोट्स की संभावनाएं अपार हैं। जहाँ आज मजदूरों की कमी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, वहाँ ह्यूमनॉइड रोबोट एक समाधान के रूप में उभर रहे हैं। खतरनाक खदानों में, रासायनिक कारखानों में, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जहाँ इंसान का जाना जोखिम भरा होता है, वहाँ ये रोबोट बेझिझक काम कर सकते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी इनकी भूमिका क्रांतिकारी हो सकती है। बुजुर्गों की देखभाल, ऑपरेशन थिएटर में सहायता और दवाइयों का सटीक वितरण जैसे कार्यों में ये रोबोट इंसानी त्रुटियों को कम कर सकते हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष अन्वेषण में भी इनका उपयोग बेहद लाभदायक साबित हो सकता है जहाँ मनुष्य के लिए जाना असंभव या अत्यंत कठिन होता है। लेकिन इस तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है जिसे नजरअंदाज करना उचित नहीं होगा। सबसे बड़ा सवाल जो हर आम इंसान के मन में उठता है, वह यह है कि क्या ये रोबोट उनकी नौकरियाँ छीन लेंगे? यह चिंता बिल्कुल स्वाभाविक और वाजिब है। इतिहास गवाह है कि हर बड़ी तकनीकी क्रांति ने पुरानी नौकरियों को खत्म किया है। औद्योगिक क्रांति ने हथकरघा बुनकरों की रोजी-रोटी छीन ली थी, कंप्यूटर ने टाइपिस्टों की जरूरत खत्म कर दी। अब ह्यूमनॉइड रोबोट्स के आने से गोदाम कर्मचारी, असेंबली लाइन कामगार, डिलीवरी बॉय और यहाँ तक कि कुछ दफ्तरी काम करने वाले लोग भी खतरे में पड़ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्टें पहले से ही यह संकेत दे रही हैं कि आने वाले दशकों में करोड़ों नौकरियाँ स्वचालन की भेंट चढ़ सकती हैं। भारत जैसे देश के लिए यह विषय और भी संवेदनशील है। हमारे देश में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा अकुशल और अर्ध-कुशल मजदूरों का है जो विनिर्माण क्षेत्र, निर्माण कार्यों और सेवा उद्योग में काम करते हैं। यदि इन क्षेत्रों में रोबोट तेजी से घुसपैठ करें और सरकार तथा उद्योग इसके लिए पहले से तैयार न हों, तो बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का संकट खड़ा हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम अभी से अपनी शिक्षा व्यवस्था और कौशल विकास कार्यक्रमों को भविष्य की जरूरतों के हिसाब से ढालना शुरू करें। ऐसी शिक्षा जो बच्चों को रोबोट के साथ काम करना सिखाए, न कि उनसे प्रतिस्पर्धा करना। इसके अलावा नैतिक और सामाजिक प्रश्न भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। यदि कोई ह्यूमनॉइड रोबोट किसी दुर्घटना का कारण बने तो उसकी ज़िम्मेदारी किसकी होगी? निमार्ता कंपनी की, उसे खरीदने वाले की, या उसे चलाने वाले की? डेटा गोपनीयता भी एक गंभीर मुद्दा है क्योंकि ये रोबोट जहाँ भी काम करते हैं, वहाँ से जानकारी एकत्र करते हैं। इस जानकारी का दुरुपयोग रोका जाना चाहिए। साथ ही यह भी सोचना जरूरी है कि जैसे-जैसे ये रोबोट और अधिक बुद्धिमान होते जाएंगे, क्या मानव और मशीन के बीच की सीमा रेखा धुंधली नहीं होती जाएगी? सरकारों की भूमिका इस पूरे परिदृश्य में बेहद अहम है। दुनिया के कई देश पहले से ही रोबोटिक्स को लेकर नीतियाँ बना रहे हैं। यूरोपीय संघ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित नियम-कानून तैयार किए हैं। चीन और अमेरिका इस क्षेत्र में भारी निवेश कर रहे हैं। भारत को भी इस दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहिए। हमें एक ऐसी राष्ट्रीय नीति की जरूरत है जो एक तरफ तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करे और दूसरी तरफ आम नागरिकों के हितों की रक्षा भी करे। अंत में यह कहना उचित होगा कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स का आगमन न तो पूरी तरह वरदान है और न ही अभिशाप। यह एक ऐसा उपकरण है जिसका असर इस बात पर निर्भर करेगा कि हम इसे किस तरह अपनाते हैं और इसके दुष्प्रभावों से बचने के लिए कितने सजग रहते हैं। तकनीक का इतिहास यही बताता है कि जो समाज बदलाव के साथ कदम मिलाकर चलते हैं, वे आगे बढ़ते हैं और जो आँखें मूंद लेते हैं, वे पीछे रह जाते हैं। इसलिए जरूरत है एक संतुलित दृष्टिकोण की, जहाँ हम तकनीक को अपनाएं भी और उस पर नजर भी रखें। ह्यूमनॉइड रोबोट्स का युग आ चुका है, अब सवाल यह नहीं कि यह आएगा या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि हम इसके लिए कितने तैयार हैं।

तमिलनाडु: हिंदू बहुसंख्यक राज्य में भी द्रविड़ राजनीति क्यों पड़ती है भारी?

डॉ. प्रियंका सौरभ (हि.स)

भारत की राजनीति को अक्सर सरल समीकरण में समझने की कोशिश की जाती है- जहाँ हिंदू आबादी अधिक होगी, वहाँ भारतीय जनता पार्टी स्वतः मजबूत होगी। लेकिन तमिलनाडु इस धारणा को चुनौती देता है। तमिलनाडु में हिंदू आबादी लगभग 85 प्रतिशत से अधिक है। राज्य मंदिरों, परंपराओं और धार्मिक आस्थाओं के लिए प्रसिद्ध है, फिर भी भाजपा यहाँ अब तक वैसी राजनीतिक सफलता हासिल नहीं कर पाई जो उसे उत्तर और पश्चिम भारत के कई राज्यों में मिली। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों है? क्या तमिलनाडु की राजनीति धर्म से अलग किसी और आधार पर चलती है? या भाजपा राज्य की सामाजिक और सांस्कृतिक मानसिकता को अब तक पूरी तरह समझ नहीं पाई?

तमिलनाडु को समझने के लिए सबसे पहले उसके राजनीतिक इतिहास को समझना जरूरी है। यह राज्य केवल चुनावी राजनीति से नहीं बल्कि एक बड़े सामाजिक आंदोलन से प्रभावित रहा है। बीसवीं सदी में ई. वी. रामासामी यानी पेरियार के नेतृत्व में द्रविड़ आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणवादी वर्चस्व, जातिगत ऊँच-नीच और उत्तर भारतीय प्रभुत्व का विरोध था। पेरियार ने तर्कवाद, सामाजिक न्याय और क्षेत्रीय अस्मिता को राजनीति का केंद्र बनाया। बाद में इसी विचारधारा से डीएमके और एआईएडीएमके जैसी शक्तिशाली पार्टियाँ उभरीं।

यही वह बिंदु है जहाँ तमिलनाडु की राजनीति बाकी भारत से अलग हो जाती है। उत्तर भारत में जहाँ धार्मिक पहचान अक्सर चुनावी राजनीति का बड़ा आधार बनती है, वहीं तमिलनाडु में ह्लतमिल पहचानह्व अधिक महत्वपूर्ण रही। यहाँ भाषा, संस्कृति और क्षेत्रीय गर्व को राजनीति के केंद्र में रखा गया। लोगों के भीतर यह भावना गहरी रही कि दिल्ली की राजनीति तमिल समाज की विशिष्टता को पूरी तरह नहीं समझती। भाजपा को कई बार इसी कारण उत्तर भारतीय पार्टी के रूप में देखा गया।

तमिलनाडु में हिंदी विरोध का इतिहास भी भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बना। 1960 के दशक में जब हिंदी को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने की कोशिश हुई, तब तमिलनाडु में बड़े आंदोलन हुए। लोगों को लगा कि उनकी भाषा और संस्कृति पर खतरा है। यही आंदोलन द्रविड़ दलों को मजबूत बनाने का कारण बना। आज भी तमिल पहचान और भाषा का मुद्दा यहाँ बेहद संवेदनशील है। भाजपा भले हिंदी थोपने से इनकार करे लेकिन उसके राष्ट्रीय विमर्श को कई लोग हिंदी और उत्तर भारतीय संस्कृति के प्रभाव से जोड़कर देखते हैं।

यह कहना गलत होगा कि तमिलनाडु में हिंदू धर्म का प्रभाव नहीं है। राज्य में प्रसिद्ध मंदिरों की लंबी परंपरा है- मीनाक्षी अम्मन मंदिर, रामनाथस्वामी मंदिर और बृहदीश्वर मंदिर जैसे धार्मिक स्थल केवल पूजा के केंद्र नहीं बल्कि तमिल संस्कृति और गौरव का हिस्सा भी हैं। लेकिन तमिलनाडु में धार्मिक आस्था का अर्थ हमेशा राजनीतिक हिंदुत्व नहीं रहा। यहाँ लोग मंदिरों में गहरी श्रद्धा रखते हैं लेकिन वोट देते समय क्षेत्रीय हित, सामाजिक न्याय और स्थानीय नेतृत्व को प्राथमिकता देते हैं।

भाजपा की सबसे बड़ी चुनौती यह रही कि वह लंबे समय तक तमिलनाडु में मजबूत स्थानीय नेतृत्व तैयार नहीं कर पाई। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, गुजरात में नरेन्द्र मोदी और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान समय-समय पर भाजपा की क्षेत्रीय ताकत का चेहरा बने। लेकिन तमिलनाडु में दशकों तक पार्टी के पास ऐसा कोई जनाधार वाला नेता नहीं था जो आम तमिल मतदाता से भावनात्मक जुड़ाव बना सके। हाल के वर्षों में के. अन्नामलाई ने भाजपा को नई ऊर्जा दी है लेकिन अभी भी पार्टी का संगठन राज्य के ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में उतना मजबूत नहीं जितना द्रविड़ दलों का है।

तमिलनाडु की राजनीति में सामाजिक न्याय और आरक्षण का मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है। द्रविड़ आंदोलन ने पिछड़े वर्गों और गैर-ब्राह्मण समुदायों को राजनीतिक शक्ति दी। यही कारण है कि राज्य में सामाजिक न्याय की राजनीति बहुत गहराई से स्थापित हो चुकी है। भाजपा की छवि लंबे समय तक अलग रही है। हालांकि भाजपा ने अब पिछड़े वर्गों और दलित समुदायों तक पहुँच बढ़ाने की कोशिश की है लेकिन तमिलनाडु में द्रविड़ दलों की सामाजिक पकड़ अब भी ज्यादा मजबूत है।

इसके अलावा तमिलनाडु में कल्याणकारी राजनीति का मॉडल भी दूसरे दलों के लिए चुनौतीपूर्ण है। मुफ्त राशन, महिला सहायता योजनाएँ, छात्रवृत्तियाँ, स्वास्थ्य सेवाएँ और सब्सिडी जैसी योजनाओं ने द्रविड़ दलों को जनता से गहराई से जोड़े रखा। यहाँ मतदाता केवल वैचारिक मुद्दों पर नहीं, बल्कि रोजमर्रा की सुविधाओं और राज्य सरकार की योजनाओं के आधार पर भी वोट करते हैं। भाजपा का राष्ट्रीय विकास मॉडल लोगों को आकर्षित करता है लेकिन तमिलनाडु में स्थानीय कल्याणकारी राजनीति की पकड़ बहुत मजबूत है।

एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि तमिलनाडु में राजनीति का भावनात्मक केंद्र 'क्षेत्रीय स्वाभिमान' रहा है। यहाँ लोग खुद को पहले तमिल मानते हैं- हालाँकि इसका अर्थ अलगाववाद नहीं बल्कि सांस्कृतिक गर्व है। भाजपा का राष्ट्रवादी विमर्श कई बार इस क्षेत्रीय अस्मिता से टकराता दिखाई देता है। द्रविड़ दल इस भावना को लगातार मजबूत करते रहे हैं कि वे 'तमिल हितों' के असली रक्षक हैं।

यह भी सच है कि भाजपा पूरी तरह कमजोर नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में उसका वोट प्रतिशत बढ़ा है। शहरी क्षेत्रों, शिक्षित युवाओं और कुछ मध्यमवर्गीय समूहों में पार्टी ने अपनी उपस्थिति मजबूत की है। सोशल मीडिया और राष्ट्रवादी मुद्दों के माध्यम से भाजपा ने राज्य में नई राजनीतिक जगह बनाने की कोशिश की है। लेकिन वोट प्रतिशत बढ़ना और सत्ता तक पहुँचना दोनों अलग बातें हैं। तमिलनाडु में द्रविड़ दलों का संगठनात्मक नेटवर्क, बूथ स्तर की पकड़ और दशकों पुरानी राजनीतिक संस्कृति भाजपा के लिए बड़ी बाधा बनी हुई है।

इसके साथ ही गठबंधन की राजनीति भी एक महत्वपूर्ण कारण है। तमिलनाडु में चुनाव अक्सर बड़े गठबंधनों के आधार पर लड़े जाते हैं। द्रविड़ दलों ने समय-समय पर राष्ट्रीय पार्टियों को अपने साथ जोड़कर चुनावी समीकरण मजबूत किए। भाजपा कभी एआईएडीएमके के साथ रही लेकिन यह गठबंधन उसे व्यापक जनसमर्थन में तब्दील नहीं करा पाया। कई मतदाता भाजपा को सहयोगी पार्टी के रूप में स्वीकार करते हैं लेकिन मुख्य शक्ति के रूप में नहीं।

तमिलनाडु की राजनीति यह भी दिखाती है कि भारत केवल धार्मिक पहचान से नहीं चलता। यहाँ भाषा, संस्कृति, जातीय संरचना, सामाजिक न्याय और क्षेत्रीय भावनाएँ मिलकर राजनीति को आकार देती हैं। यही कारण है कि हिंदू बहुसंख्यक होने के बावजूद राज्य में भाजपा को वैसी सफलता नहीं मिली जैसी उत्तर भारत के कई राज्यों में मिली।

दरअसल, तमिलनाडु भारतीय लोकतंत्र का अलग अध्याय है। यहाँ मंदिर भी हैं, आस्था भी है, धार्मिक परंपराएँ भी हैं लेकिन राजनीति का केंद्र केवल धर्म नहीं है। यहाँ मतदाता अपनी क्षेत्रीय पहचान, सामाजिक अधिकारों और स्थानीय मुद्दों को भी उतनी ही गंभीरता से देखते हैं। भाजपा यदि तमिलनाडु में मजबूत होना चाहती है तो उसे केवल हिंदुत्व की राजनीति से आगे बढ़कर तमिल समाज की सांस्कृतिक संवेदनाओं, भाषा, सामाजिक न्याय और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को गहराई से समझना होगा।

(लेखिका, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

लूट का कारोबार बनते प्राइवेट स्कूल

डॉ. सत्यवान सौरभ (हि.स)

हर साल अप्रैल और मई का महीना आते ही देशभर के लाखों अभिभावकों के घरों में अदृश्य आर्थिक संकट शुरू हो जाता है। यह संकट किसी बीमारी, बेरोजगारी या प्राकृतिक आपदा का नहीं बल्कि बच्चों के नए शैक्षणिक सत्र का होता है। स्कूल खुलते ही फीस, किताबें, यूनिफॉर्म, कॉपियाँ, ट्रांसपोर्ट और अलग-अलग अनिवार्य खर्चों की लंबी सूची अभिभावकों के हाथ में थमा दी जाती है। सबसे बड़ा झटका किताबों के नाम पर लगता है। जिन किताबों की वास्तविक कीमत 50 या 100 रुपये होती है, वे स्कूल द्वारा तय दुकानों पर कई गुना ज्यादा दरों में बेची जाती है। छोटे बच्चों की किताबों का पूरा सेट 7 से 8 हजार रुपये तक पहुँच जाता है। मध्यमवर्गीय और गरीब परिवारों के लिए यह सीधी आर्थिक लूट से कम नहीं।

विडंबना यह है कि शिक्षा को अधिकार और सेवा कहा जाता है लेकिन निजी स्कूलों ने इसे खुले बाजार का व्यापार बना दिया है। आज शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान देना कम और मुनाफा कमाना ज्यादा दिखाई देता है। किताबों के नाम पर जो खेल चल रहा है, वह केवल अभिभावकों की जेब काटने का मामला नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था की नैतिक गिरावट का भी बड़ा उदाहरण है।

देश में एनसीईआरटी की किताबें उपलब्ध हैं, जो सस्ती भी हैं और राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त भी। सरकार स्वयं समय-समय पर एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को लागू करने की बात करती है। फिर सवाल यह उठता है कि आखिर निजी स्कूल इन किताबों से परहेज क्यों करते हैं? इसका उत्तर सीधा है- कमीशन और मुनाफा। अनेक निजी स्कूल निजी प्रकाशकों के साथ समझौता कर लेते हैं। स्कूल अपने छात्रों पर उन्हीं प्रकाशकों की किताबें थोपते हैं और बदले में मोटा कमीशन प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि हर साल नए संस्करण और नए पैटर्न के नाम पर किताबें बदली जाती हैं ताकि पुरानी किताबें किसी और बच्चे के काम न आ सकें।

यह केवल आर्थिक शोषण नहीं बल्कि योजनाबद्ध व्यवसायिक मॉडल है। स्कूल, प्रकाशक और कुछ बुक डिपो मिलकर ऐसा नेटवर्क बना चुके हैं जिसमें अभिभावक केवल ग्राहक बनकर रह गया है। उसे मजबूर किया जाता है कि वह किताबें केवल स्कूल द्वारा निर्धारित दुकान से खरीदे। यदि कोई अभिभावक बाहर से वही किताबें लेने की कोशिश करे तो या तो किताबें उपलब्ध नहीं होतीं या फिर स्कूल के शिक्षक बच्चों पर दबाव बनाते हैं कि सही किताबें वही हैं जो स्कूल ने बताई हैं।

स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि कई परिवार बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्ज लेने को मजबूर हैं। एक मजदूर, किसान, छोटा दुकानदार या नौकरीपेशा व्यक्ति जब दो या तीन बच्चों के स्कूल खर्च का हिसाब लगाता है तो उसकी आधी कमाई केवल शिक्षा पर चली जाती है। फीस अलग, किताबें अलग, यूनिफॉर्म अलग और गतिविधियों के नाम पर अलग वसूली। यह कैसी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें बच्चा स्कूल जाने से पहले ही परिवार पर आर्थिक बोझ बन जाता है?

सबसे दुखद बात यह है कि इस पूरे खेल में सरकार और प्रशासन अक्सर मूकदर्शक बने रहते हैं। हर साल शिकायतें होती हैं, मीडिया में खबरें आती हैं, कुछ अधिकारी बयान देते हैं लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं बदलता। शिक्षा विभाग के नियम स्पष्ट हैं कि स्कूल किसी विशेष दुकान से किताबें खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। लेकिन वास्तविकता यह है कि नियम कागजों तक सीमित हैं और निजी स्कूलों की मनमानी लगातार बढ़ती जा रही है।

असल समस्या यह है कि शिक्षा अब सेवा नहीं, ब्रांड बन चुकी है। बड़े-बड़े निजी स्कूल खुद को ह्लइंटरनेशनलह्व, ह्लवर्ल्ड क्लासह्व और ह्लस्मार्ट एजुकेशनह्व जैसे नामों से प्रचारित करते हैं। भव्य इमारतें, वातानुकूलित क्लास रूम व बसें और अंग्रेजी का आकर्षण दिखाकर अभिभावकों को प्रभावित किया जाता है। इस चमक-दमक के पीछे शिक्षा का असली उद्देश्य कहीं खो गया है। बच्चा कितना सीख रहा है, यह महत्वपूर्ण नहीं रह गया; महत्वपूर्ण यह हो गया है कि स्कूल कितनी कमाई कर रहा है।

विडंबना यह है कि जिन किताबों को महंगे दामों में बेचा जाता है, उनकी गुणवत्ता हमेशा बेहतर नहीं होती। कई निजी प्रकाशकों की किताबों में भाषा संबंधी गलतियाँ, अनावश्यक सामग्री और रटंत शिक्षा को बढ़ावा देने वाली सामग्री भरी होती है। दूसरी ओर एनसीईआरटी की किताबें विशेषज्ञों द्वारा तैयार की जाती हैं और उनकी कीमत बेहद कम होती है। इसके बावजूद निजी स्कूल उन्हें अपनाने से बचते हैं क्योंकि वहाँ से मोटा मुनाफा नहीं मिलता।

यह केवल किताबों तक सीमित समस्या नहीं है। यूनिफॉर्म का खेल भी कम खतरनाक नहीं। स्कूल हर साल यूनिफॉर्म का डिजाइन थोड़ा बदल देते हैं ताकि पुराने कपड़े दोबारा इस्तेमाल न हो सके। कुछ स्कूल केवल तय दुकानों से यूनिफॉर्म खरीदने का दबाव डालते हैं, जहाँ सामान्य कपड़े की कीमत कई गुना बढ़ा दी जाती है। जूते, बैग, बेल्ट, टाई और यहाँ तक कि कॉपियों तक पर स्कूलों की अनिवार्यता लागू होती है।

शिक्षा के इस बाजारीकरण ने सामाजिक असमानता को और गहरा कर दिया है। अमीर परिवार किसी तरह यह खर्च उठा लेते हैं लेकिन गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए यह भारी मानसिक तनाव का कारण बनता है। कई बार माता-पिता अपनी जरूरतें काटकर बच्चों की फीस भरते हैं। कोई माँ अपने गहने गिरवी रखती है, कोई पिता अतिरिक्त मजदूरी करता है, कोई परिवार कर्ज में डूब जाता है। लेकिन शिक्षा माफिया के लिए यह सब केवल बिजनेस है।

प्रश्न यह है कि क्या शिक्षा केवल अमीरों के लिए रह जाएगी? यदि यही स्थिति जारी रही तो भविष्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा गरीबों की पहुँच से पूरी तरह बाहर हो जाएगी। यह खतरनाक संकेत है। संविधान सभी बच्चों को समान शिक्षा का अधिकार देता है लेकिन निजी स्कूलों की मनमानी इस अधिकार को ीरे-धीरे खोखला कर रही है।

सरकार को अब केवल दिशा-निर्देश जारी करने से आगे बढ़ना होगा। सबसे पहले सभी स्कूलों में एनसीईआरटी किताबों को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। यदि अतिरिक्त सामग्री जरूरी हो तो उसकी कीमत और गुणवत्ता पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। स्कूलों और निजी प्रकाशकों के बीच होने वाले आर्थिक समझौतों की जांच होनी चाहिए। जो स्कूल अभिभावकों को किसी विशेष दुकान से किताबें खरीदने के लिए मजबूर करें, उन पर भारी जुमार्ना और मान्यता रद्द करने जैसी कार्रवाई होनी चाहिए।

इसके साथ ही जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग को नियमित निरीक्षण करने चाहिए। अभिभावकों की शिकायतों के लिए हेल्पलाइन और त्वरित कार्रवाई की व्यवस्था होनी चाहिए। अक्सर अभिभावक डर के कारण खुलकर शिकायत नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें डर रहता है कि कहीं स्कूल उनके बच्चे को मानसिक रूप से परेशान न करे। इसलिए सरकार को अभिभावकों की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करनी होगी।

समाज को भी इस मुद्दे पर जागरूक होना होगा। अभिभावकों को संगठित होकर अपनी आवाज उठानी होगी। जब तक लोग अलग-अलग डरते रहेंगे, तब तक स्कूलों की मनमानी चलती रहेगी। शिक्षा कोई लक्जरी वस्तु नहीं बल्कि मौलिक अधिकार है। इसे बाजार की वस्तु बनाना किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है।

आज जरूरत इस बात की है कि शिक्षा को फिर से सेवा बनाया जाए, व्यापार नहीं। स्कूलों का उद्देश्य बच्चों के भीतर ज्ञान, नैतिकता और सोच विकसित करना होना चाहिए, न कि अभिभावकों की जेब खाली करना। जिस देश में करोड़ों लोग आज भी गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रहे हों, वहाँ शिक्षा के नाम पर ऐसी लूट सामाजिक अपराध से कम नहीं। यह समझना होगा कि स्कूल ज्ञान के मंदिर हैं, बाजार नहीं। बच्चों की किताबें सीखने का माध्यम हैं, कमाई का साधन नहीं। जिस दिन शिक्षा व्यवस्था से लालच और कमीशन का यह खेल खत्म होगा, उसी दिन समाज सच मायनों में शिक्षित और संवेदनशील बन पाएगा।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

आज का राशिफल

मेष: आज परिवार के सदस्यों का भरपूर सहयोग और समर्थन मिलने की संभावना है। राजनीति और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों की प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। छोटे बच्चों के साथ मधुर व्यवहार बनाए रखें, इससे पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। *(सिटी दर्पण)*

वृषभ: आज आपका मन नई चीजों को समझने और शोधपूर्ण कार्यों में लगा रहेगा। आर्थिक मामलों में बजट का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होगा। समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा और लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे। *(सिटी दर्पण)*

मिथुन: अपने कार्यों के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण बनाए रखें। वैवाहिक जीवन में पारदर्शिता जरूरी रहेगी, इसलिए जीवनसाथी से कोई बात न छिपाएं। अत्यधिक आत्मविश्वास आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। प्रेम संबंधों में तनाव की स्थिति बन सकती है। *(सिटी दर्पण)*

कर्क: कार्यस्थल पर आपका प्रभाव और सम्मान बढ़ेगा। लंबे समय से मन में चल रही कोई इच्छा आज पूरी हो सकती है। वैवाहिक जीवन में चल रहा तनाव कम होगा और परिवार का माहौल सकारात्मक रहेगा। साझेदारी में नया व्यवसाय शुरू करने की योजना बन सकती है। *(सिटी दर्पण)*

सिंह: आज किसी सार्वजनिक कार्यक्रम या बैठक में आपको विशेष महत्व मिल सकता है। आर्थिक लेन-देन और उधार संबंधी मामलों में सावधानी बरतें। आप अपने काम करने के तरीके में सुधार लाने का प्रयास करेंगे। *(सिटी दर्पण)*

कन्या: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को मानसिक तनाव महसूस हो सकता है। बच्चों की गलत आदतों को नजरअंदाज न करें, समय रहते उन्हें सही मार्गदर्शन दें। बातचीत करते समय सरल और स्पष्ट शब्दों का प्रयोग करें, अन्यथा लोग आपकी बातों का गलत अर्थ निकाल सकते हैं। *(सिटी दर्पण)*

तुला: आज आप कार्यक्षेत्र की जटिल समस्याओं को सुलझाने में सफल रहेंगे। दिनभर भागदौड़ अधिक रह सकती है। रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी से जुड़े निवेश करते समय सावधानी बरतें। पुराने मित्रों से मुलाकात होने के योग बन रहे हैं, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। *(सिटी दर्पण)*

वृश्चिक: आज आपकी जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। सरकारी नौकरी करने वालों को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसका लाभ भविष्य में मिलेगा। मार्केटिंग और व्यापार से जुड़े लोगों को अच्छा मुनाफा होने के संकेत हैं। *(सिटी दर्पण)*

धनु: स्वार्थी और अवसरवादी लोगों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। झूठ बोलने से बचें, अन्यथा रिश्तों में दूरी बढ़ सकती है। परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। संतान से जुड़ी कोई चिंता मन में बनी रह सकती है। *(सिटी दर्पण)*

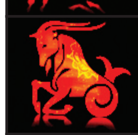

मकर: आज किसी रिश्तेदार की आर्थिक मदद करनी पड़ सकती है। अपने कार्यों का आनंद लेते हुए आप पूरे उत्साह से काम करेंगे। आपके व्यवहार की शालीनता लोगों को प्रभावित करेगी। विदेश यात्रा से जुड़े अवसर सामने आ सकते हैं। *(सिटी दर्पण)*

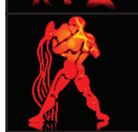

कुंभ: व्यवसाय का विस्तार करने में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। केवल दिखावे के कारण किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान न उठाएं। जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। परिस्थितियों पर क्रोध करने के बजाय धैर्य और समझदारी से काम लें। *(सिटी दर्पण)*

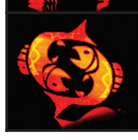

मीन: आज नई संपत्ति या निवेश से जुड़े फैसले आपके पक्ष में रह सकते हैं। विद्यार्थियों को मनचाही नौकरी मिलने के संकेत हैं। रोजगार के नए अवसर मिलने से उत्साह बढ़ेगा। प्रेम विवाह को लेकर परिवार की सहमति मिलने की संभावना है। *(सिटी दर्पण)*

भारतीय अस्मिता के प्रतीक: वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप

महेन्द्र तिवारी

भारतीय इतिहास की गौरवशाली परंपरा में महाराणा प्रताप का नाम एक ऐसे देदीप्यमान नक्षत्र के समान है जिसकी आभा शताब्दियों के पश्चात भी तनिक भी फीकी नहीं पड़ी है। उनका व्यक्तित्व साहस, त्याग, अद्वितीय स्वाभिमान और अटूट राष्ट्रभक्ति का एक ऐसा संगम है जो विश्व इतिहास में विरले ही देखने को मिलता है। राजस्थान की वीर प्रसूता भूमि पर अनेक योद्धाओं ने जन्म लिया, किंतु महाराणा प्रताप की विशिष्टता इस बात में निहित है कि उन्होंने उस समय की सबसे बड़ी वैश्विक शक्ति कहे जाने वाले मुगल साम्राज्य के सम्मुख सिर झुकाने के स्थान पर संघर्ष और अभावों से भरे जीवन को प्राथमिकता दी। उनका संपूर्ण जीवन केवल युद्धों का संकलन मात्र नहीं है, अपितु यह मनुष्य की उस अदम्य इच्छाशक्ति का प्रमाण है जो किसी भी भौतिक प्रलोभन या भय के आगे पराजित नहीं होती। मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के इस तेजस्वी राजा ने यह सिद्ध कर दिया कि स्वतंत्रता का मूल्य किसी भी सिंहासन या विलासिता से कहीं अधिक ऊंचा होता है।

महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के सुप्रसिद्ध कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। उनके पिता महाराणा उदयसिंह द्वितीय मेवाड़ के शासक थे और उनकी माता रानी जयवंता बाई एक अत्यंत धार्मिक और स्वाभिमानी महिला थीं। प्रताप के व्यक्तित्व निर्माण में उनकी माता का प्रभाव सर्वोपरि था जिन्होंने बचपन से ही उन्हें रामायण और महाभारत की वीर कथाएं सुनाकर धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए प्रेरित किया। कुंभलगढ़ की पहाड़ियों में प्रताप का बचपन व्यतीत हुआ जहाँ उन्होंने स्थानीय भील जनजाति के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए। यही भील आगे चलकर उनकी सेना की रीढ़ बने और उन्हें प्यार से कीका कहकर पुकारते थे। बचपन से ही प्रताप अस्त्र शस्त्र के संचालन, घुड़सवारी और युद्ध कौशल में निपुण होने लगे थे। उनकी कद काठी अत्यंत प्रभावशाली थी और उनके चेहरे पर एक ऐसा तेज था जो उनके भावी नायक होने की पुष्टि करता था।

जब प्रताप युवावस्था में पहुँचे तब भारत की राजनीतिक परिस्थितियाँ बड़ी तेजी से बदल रही थीं। मुगल सम्राट अकबर अपनी साम्राज्यवादी नीतियों के माध्यम से पूरे भारत को एक ध्वज के नीचे लाने का प्रयास कर रहा था। राजस्थान के अधिकांश शक्तिशाली राजपूत राजाओं ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी और उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे। किंतु मेवाड़ इस मार्ग में सबसे बड़ी बाधा था। चित्तौड़गढ़ पर 1568 में अकबर का भीषण आक्रमण हुआ जिसमें भारी रक्तपात हुआ और महाराणा उदयसिंह को सुरक्षित स्थानों की खोज में पहाड़ियों की ओर जाना पड़ा। इसी कठिन समय में 1572 में महाराणा उदयसिंह की मृत्यु के बाद प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। उस समय मेवाड़ के पास न तो पर्याप्त धन था, न विशाल सेना और न ही चित्तौड़गढ़ जैसा अभेद्य दुर्ग, क्योंकि वह मुगलों के अधिकार में था। इसके बावजूद प्रताप ने हार मानने के स्थान पर मेवाड़ को पुनः स्वतंत्र कराने की प्रतिज्ञा ली।

अकबर जानता था कि यदि मेवाड़ उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है तो पूरे भारत पर उसका निर्बाध शासन होगा। इसलिए उसने प्रताप को समझाने के लिए चार बार दूत भेजे। सबसे पहले जलाल खान को भेजा गया, उसके बाद आमेर के राजा मानसिंह, फिर राजा भगवंत दास और अंत में टोडरमल को भेजा गया। इन दूतों ने प्रताप को बड़े बड़े प्रलोभन दिए और युद्ध की विभीषिका से डराया, लेकिन प्रताप का उत्तर स्पष्ट था कि वे किसी भी स्थिति में मुगलों के दास बनकर जीवित रहने के स्थान पर स्वतंत्र रहकर मृत्यु को गले लगाना श्रेष्ठ समझते हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मेवाड़ की स्वतंत्रता का कोई सौदा नहीं हो सकता। यह निर्णय एक अत्यंत शक्तिशाली साम्राज्य के विरुद्ध सीधा संघर्ष मोल लेने जैसा था, जो किसी आत्मघाती कदम से कम नहीं जान पड़ता था, लेकिन प्रताप के लिए उनका आत्मसम्मान सर्वोपरि था।

परिणामस्वरूप 18 जून 1576 को वह ऐतिहासिक युद्ध हुआ जिसे हम हल्दीघाटी के युद्ध के नाम से जानते हैं। अरावली की संकरी पहाड़ियों में स्थित इस स्थान की मिट्टी हल्दी जैसी पीली होने के कारण इसे हल्दीघाटी कहा जाता है। एक ओर मुगल सेना थी जिसका नेतृत्व राजा मानसिंह कर रहे थे और उनके पास आधुनिक अस्त्र शस्त्र, हाथियों का विशाल दल और हजारों प्रशिक्षित सैनिक थे। दूसरी ओर महाराणा प्रताप की सेना थी जिसमें लगभग 20000 सैनिक थे जिनमें राजपूतों के साथ साथ हकीम खान सूरी के नेतृत्व में अफगान सैनिक और राणा पुंजा के नेतृत्व में भील धनुर्धारी सम्मिलित थे। युद्ध इतना भीषण था कि बनास नदी का जल सैनिकों के रक्त से लाल हो गया था। महाराणा प्रताप ने अपनी वीरता का ऐसा प्रदर्शन किया कि मुगल सेना के पैर उखड़ गए। उन्होंने अपने भाले के एक ही प्रहार से बहलोल खान को उसके घोड़े समेत दो टुकड़ों में चीर दिया था।

हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक भी अमर हो गया। चेतक की स्वामीभक्ति का उदाहरण आज भी जन जन की जुबान पर है। युद्ध के दौरान जब महाराणा प्रताप संकट में थे, तब गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद चेतक उन्हें रणक्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकाल ले गया। उसने अपने घायल पैरों के साथ एक चौड़े नाले को एक ही छलांग में पार कर लिया, जिसे मुगल सैनिक पार नहीं कर सके। अपने स्वामी की रक्षा करने के पश्चात चेतक ने प्राण त्याग दिए। चेतक की मृत्यु पर महाराणा प्रताप की आंखों में आंसू आ गए थे। इस युद्ध के बाद मुगलों को लगा था कि प्रताप की शक्ति समाप्त हो गई है, लेकिन यह तो उनके संघर्ष का केवल एक नया अध्याय था। हल्दीघाटी का युद्ध निर्णायक नहीं रहा क्योंकि अकबर न तो प्रताप को बंदी बना सका और न ही मेवाड़ को पूरी तरह जीत सका।

युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप का जीवन अत्यंत संघर्षपूर्ण रहा। उन्होंने अपने परिवार के साथ जंगलों और पहाड़ों में निवास किया। उस समय की कथाएं बताती हैं कि कई बार उनके बच्चों को घास की रोटियां खाकर दिन बिताने पड़े। एक बार जब एक जंगली बिल्ली ने उनके बच्चे के हाथ से घास की रोटी छीन ली और बच्चा रोने लगा, तो प्रताप का हृदय विचलित हुआ, लेकिन उन्होंने तुरंत स्वयं को संभाला और स्वतंत्रता के मार्ग से पीछे नहीं हटे। उन्होंने प्रण लिया था कि जब तक वे चित्तौड़ को मुक्त नहीं करा लेंगे, वे सोने चांदी के बर्तनों में भोजन नहीं करेंगे और कोमल शय्या पर नहीं सोएंगे। उन्होंने अपने महलों का त्याग कर दिया और घास के बिछौनों पर सोने लगे। उनके इस धैर्य और संकल्प ने संपूर्ण मेवाड़ की जनता में देशभक्ति का ज्वार पैदा कर दिया था।

कठिन समय में महाराणा प्रताप को उनके विश्वसनीय मंत्री और मित्र भामाशाह का सहयोग मिला। जब प्रताप के पास सेना को संगठित करने के लिए धन का अभाव था, तब भामाशाह ने अपनी जीवन भर की संपूर्ण संपत्ति महाराणा के चरणों में अर्पित कर दी। यह धनराशि इतनी अधिक थी कि इससे 25000 सैनिकों का खर्च 12 वर्षों तक उठाया जा सकता था। इस सहायता ने प्रताप के संघर्ष में नई जान फूंक दी। उन्होंने पुनः एक शक्तिशाली सेना का गठन किया और मुगलों के किलों पर आक्रमण करना प्रारंभ किया। प्रताप ने परंपरागत युद्ध पद्धति के स्थान पर छापामार युद्ध नीति अपनाई जिसे गुरिल्ला युद्ध कहा जाता है। पहाड़ियों के भूगोल से परिचित होने के कारण उनकी सेना अचानक मुगलों पर हमला करती और देखते ही देखते पहाड़ियों में ओझल हो जाती। मुगलों की विशाल सेना इस युद्ध पद्धति के आगे असहाय सिद्ध होने लगी।

1582 में दिवेर का युद्ध हुआ जो महाराणा प्रताप की एक बड़ी सामरिक विजय थी।

इस युद्ध में प्रताप ने मुगल चौकियों को ध्वस्त कर दिया और मुगलों के मनोबल को पूरी तरह तोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे मेवाड़ के अधिकांश क्षेत्रों को मुक्त करा लिया। उदयपुर, कुंभलगढ़ और गोगुंदा जैसे महत्वपूर्ण स्थान पुनः प्रताप के अधिकार में आ गए। मुगल सम्राट अकबर अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद प्रताप को झुका नहीं सका। अंततः अकबर ने भी मेवाड़ की ओर अभियान भेजना बंद कर दिया। महाराणा प्रताप ने अपनी नई राजधानी चावंड में स्थापित की जहाँ उन्होंने कला, साहित्य और कृषि को बढ़ावा दिया। उनके शासनकाल में प्रजा अत्यंत सुखी थी और लोग उन्हें अपना रक्षक मानते थे।

महाराणा प्रताप का अंत समय निकट आया जब 19 जनवरी 1597 को एक शिकार के दौरान उन्हें गहरी चोट लगी। 57 वर्ष की आयु में इस महान योद्धा ने अपनी अंतिम सांस ली। मृत्यु शय्या पर भी उन्हें केवल इस बात की चिंता थी कि कहीं उनके उत्तराधिकारी मुगलों के सामने झुक न जाएं। उनके पुत्र अमर सिंह और सामंतों ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वे मेवाड़ की स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे, तभी प्रताप की आत्मा को शांति मिली। कहा जाता है कि जब प्रताप की मृत्यु का समाचार अकबर को मिला, तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। अकबर ने स्वयं स्वीकार किया था कि प्रताप जैसा महान और अडिग शत्रु मिलना असंभव है। यह एक विजेता की ओर से अपने प्रतिद्वंद्वी को दी गई सबसे बड़ी श्रद्धांजलि थी।

आज भी महाराणा प्रताप का जीवन प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वे केवल एक क्षेत्रीय राजा नहीं थे, बल्कि भारतीय अस्मिता और अखंडता के प्रतीक थे। उन्होंने यह संदेश दिया कि यदि आपके पास दृढ़ संकल्प और अदम्य साहस है, तो संसाधनों का अभाव आपकी सफलता में बाधक नहीं बन सकता। उनकी जयंती और पुण्यतिथि पर आज भी राजस्थान की गलियों में वीरता के गीत गूँजते हैं। साहित्यकारों ने उनकी वीरता पर अनेक काव्य रचे हैं जो आज भी युवाओं के भीतर जोश भर देते हैं। महाराणा प्रताप का नाम लेते ही एक ऐसे वीर का चित्र सामने आता है जो अपनी मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्योछावर करने को तत्पर रहता है। उनका त्याग, संघर्ष और अटूट निष्ठा आने वाली पीढ़ियों को सदैव यह सिखाती रहेगी कि स्वतंत्रता की रक्षा के लिए किया गया संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता और इतिहास केवल उन्हीं को स्थान देता है जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं।

भगवंत मान सरकार ने दस्ती मंजूरियों को समाप्त करने और वित्तीय शासन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डिजिटल ई-सैंक्शन सिस्टम किया लॉन्च

मैनुअल और कागजी कार्यवाही वाली मंजूरी प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल वर्कफ्लो से बदली जाएगी: हरपाल सिंह चीमा

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

भगवंत मान सरकार ने आज यूनिफाइड सैंक्शन मैनेजमेंट सिस्टम (यू.एस.एम.एस.) की शुरूआत करके वित्तीय शासन में एक बड़ा मील का पत्थर स्थापित किया। मैनुअल मंजूरियों की प्रक्रिया को डिजिटाइज करने और इसे राज्य की भुगतान प्रणालियों के साथ निर्बाध रूप से जोड़ने के लिए वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने इस ई-सैंक्शन मॉड्यूल का औपचारिक उद्घाटन किया।यह रणनीतिक शुरू आत न केवल पुरानी दस्ती प्रक्रियाओं को सिर से लेकर अंत तक डिजिटल कार्यप्रणाली से बदलती है, बल्कि केंद्रीय दिशा-निर्देशों के भी अनुकूल है, जिससे राज्य के लिए बड़े वित्तीय प्रोत्साहनों के अवसर पैदा होंगे। यहां म्यूनिसिपल भवन ऑडिटोरियम में ई-सैंक्शन मॉड्यूल की शुरूआत के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, बेहतर वित्तीय प्रबंधन, पारदर्शिता और सिर से अंत तक डिजिटाइजेशन सुनिश्चित करने के लिए खजाना और लेखा विभाग ने एन.आई.सी. के सहयोग से प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय मंजूरियां ऑनलाइन जारी करने तथा उसके बाद बिल तैयार करने के लिए मंजूरी को ऑटोमैटिक आई.एफ.एम.एस. पर भेजने हेतु एक ई-सैंक्शन मॉड्यूल विकसित किया है।

ई-सैंक्शन मॉड्यूल के मुख्य लाभों का विवरण देते हुए वित्त मंत्री ने पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, मंजूरी प्रक्रिया के प्रत्येक चरण को उपयोगकर्ता के विवरण, समय और स्वीकृति श्रृंखला के साथ डिजिटल रूप में रिकॉर्ड किया जाता है, जिससे एक संपूर्ण ऑडिट ट्रेल बनती है और जवाबदेही में सुधार होता है।यह सिस्टम मंजूरी जारी करने से पहले बजट की उपलब्धता की पुष्टि करता है, जिससे विभागों को अतिरिक्त खर्च से बचने और बजट प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने में मदद मिलती है।

मंजूरियों के डिजिटाइजेशन के बारे में उन्होंने आगे कहा, ई-सैंक्शन मॉड्यूल को मैनुअल और कागजी कार्यवाही वाली प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल कार्यप्रणाली से बदलने के लिए पेश किया गया है, जिससे सरकारी वित्तीय प्रशासन में दक्षता और पारदर्शिता में सुधार होगा। यह मॉड्यूल सभी विभागों में मंजूरी आदेशों के प्रारूप और प्रक्रिया में एकरूपता लाता है, जिससे अनियमितताओं और प्रक्रियागत त्रुटियों में कमी आती है। आई.एफ.एम.एस. के साथ सिर से अंत तक एकीकरण के महत्वपूर्ण पहलू पर मंत्री ने भरोसा दिलाते हुए कहा, यह मॉड्यूल आई.एफ.एम.एस. के भीतर बजट, खजाना, बिल प्रोसेसिंग और भुगतान प्रणालियों के साथ मंजूरी आदेशों के निर्बाध एकीकरण को सुनिश्चित करता है, जिससे कार्य के दोहराव और मैनुअल हस्तक्षेप में कमी आती है। ऑटोमैटिक सत्यापन, हेड ऑफ अकाउंट, राशि, स्कीम मैपिंग और लाभार्थी विवरणों से संबंधित क्लेरिकल त्रुटियों को कम करता है।पोर्टल की रणनीतिक शुरूआत के बारे में पृष्ठभूमि बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा, इस मॉड्यूल को बी.एफ.ए.आई.आर. के अंतर्गत डी.एल.आई.-3 की अनुपालना करते हुए विकसित किया गया है।भारत सरकार ने पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एस.ए.एस.सी.आई.) 2026-27 हेतु नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनमें विभिन्न घटकों के अंतर्गत कई वित्तीय सुधारों की रूपरेखा दी गई है। इन दिशा-निर्देशों में डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रेजरी एंड अकाउंट्स के कार्यालय द्वारा ई-सैंक्शन मॉड्यूल को लागू करना शामिल है।

अपने संबोधन के समापन पर वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इस तकनीक के भविष्य के प्रभाव के बारे में अपना दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने जोर देते हुए कहा, सफल और पूर्ण रूप से लागू होने पर यह पहल वित्तीय, प्रशासनिक और तकनीकी मंजूरियों के डिजिटल निर्माण, स्वीकृति और निगरानी में निर्बाध सिर से अंत तक ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित करके राज्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने की उम्मीद है और इससे राज्य एस.ए.एस.सी.आई. दिशा-निर्देशों के तहत 50 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन के लिए भी पात्र बन जाएगा।

इस उद्घाटन समारोह में विश्व बैंक की टीम द्वारा मॉड्यूल की कार्यप्रणाली पर विशेषज्ञ व्याख्यान तथा एन.आई.सी. टीम द्वारा एक विस्तृत प्रस्तुति भी दी गई।

पंजाब भर में दो-दिवसीय मिल्क सैंपलिंग अभियान चलाया गया, स्वास्थ्य मंत्री ने मिलावटखोरों को दी चेतावनी

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा राज्य में सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देशों को पूरा करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के तहत फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन (एफ.डी.ए.) पंजाब ने राज्य में दूध के नमूने लेने के लिए दो-दिवसीय अभियान चलाया। यह अभियान बुधवार और वीरवार को चलाया गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह के निर्देशों और एफ.डी.ए. पंजाब के कमिश्नर कंवलप्रीत बराड़ की निगरानी में चलाया गया यह अभियान डेयरी सप्लाई चेन के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित था। डॉ. बलबीर सिंह ने बताया कि राज्य भर में तड़के नाके लगाए गए थे, जिनके तहत शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में डेयरी फार्मों, संग्रह केंद्रों, प्रोसेसिंग यूनिटों और खुदरा दुकानों से दूध के 200 नमूने लिए गए। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि एकत्र किए गए नमूनों को मिलावट, अशुद्धता और निर्धारित मानकों की पालना की जांच हेतु मान्यता प्राप्त स्टेट फूड लेबोरेटरी में भेजा गया है।उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा,यदि कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर (एफ.बी.ओ.) नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के प्रावधानों के अनुसार सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। सिंह ने लोगों से सतर्क रहने और खाद्य पदार्थों में मिलावट के किसी भी संदिग्ध मामले की रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को देकर इस मिशन में अपना योगदान देने की अपील की। सप्लाई चेन से मिलावटी दूध को खत्म करके जनस्वास्थ्य की रक्षा के प्रति पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने पंजाब के लोगों को भरोसा दिलाया कि यह सैंपलिंग अभियान एक सतत और मजबूत प्रवर्तन अभियान का हिस्सा है, जो आने वाले हफ्तों में ह्वसेहतमंद और रंगला पंजाबह्न सुनिश्चित करने के लिए जारी रहेगा।

चौकसी के प्रति विभाग की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कमिश्नर एफ.डी.ए. कंवलप्रीत बराड़ ने कहा कि फूड सेफ्टी अधिकारी न केवल कानून लागू कर रहे हैं बल्कि विक्रेताओं और डेयरी ऑपरेटरों को स्वच्छता, उचित संभाल और सही स्टोरेज प्रथाओं के बारे में भी जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि नागरिकों की भलाई को ध्यान में रखते हुए डेयरी सेक्टर में उच्च मानकों को बनाए रखना बेहद जरूरी है।उल्लेखनीय है कि पंजाब भर में फूड सेफ्टी प्रवर्तन को मजबूत करने के लिए आने वाले हफ्तों में विभाग के चल रहे अभियान के हिस्से के रूप में यह सैंपलिंग अभियान जारी रहेगा।

चुन्नी लाल सचदेवा डीएवी स्कूल जैतो में विश्व एथलेटिक्स दिवस उत्साह व उमंग से मनाया

सिटी दर्पण संवाददाता
जैतो

चुन्नीलाल सचदेवा डी.ए.वी. सेंटेनरी पब्लिक स्कूल जैतो में 'विश्व एथलेटिक्स दिवस' को बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया।इस अवसर पर नर्सरी से लेकर सातवीं कक्षा तक के लड़के-लड़कियों ने विभिन्न एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में भाग लिया। स्कूल ने दौड़, लंबी कूद और कई अन्य खेलों का आयोजन किया, जिनमें विद्यार्थियों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ हिस्सा लिया।कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट खेल भावना और अनुशासन का प्रदर्शन किया।

कार्यक्रम के अंत में, स्कूल की प्रधानाचार्या ज्योति शर्मा ने विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरित किए। उन्होंने सभी बच्चों को सम्मानित किया और भविष्य में भी एथलेटिक्स और अन्य खेल प्रतियोगिताओं में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया।उन्होंने कहा कि खेल बच्चों को स्वस्थ रहने में मदद करते हैं और उनके जीवन में योगदान देते हैं।

'आकाशवाणी राष्ट्र की सेवा में 90 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव मना रहा है

जालंधर। आकाशवाणी एक सार्वजनिक प्रसारक के रूप में राष्ट्र के प्रति अपनी सेवा के 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। आज ही के दिन, 8 जून 1936 को 'इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस' का नाम बदलकर 'ऑल इंडिया रेडियो' (एआईआर) किया गया था। यह ऐतिहासिक दिन देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में एक विशेष क्षण का प्रतीक है, जब एक ऐसी आवाज का जन्म हुआ जो आने वाली पीढ़ियों तक गूँजती रहेगी। 7 जून 1936 को, 'ऑल इंडिया रेडियो' की तत्कालीन आधिकारिक पत्रिका 'द इंडियन लिसनर' के मुखपृष्ठ ने दुनिया के सामने एआईआर की घोषणा की। आकाशवाणी का विनम्र दिल्ली केंद्र एक ऐसा केंद्र बन गया जहाँ आवाजों को पंख मिले और इतिहास को एक मंच प्राप्त हुआ। इन्हीं शांत दीवारों से वे गूँज पैदा हुई जिन्होंने एक ऐसे राष्ट्र को आकार दिया जो तब से कालातीत, आत्मिक और अविस्मरणीय बना हुआ है। आकाशवाणी के पंजाब क्लस्टर प्रमुख और उप महानिदेशक (इंजीनियरिंग), रंजीत मीणा ने कहा कि राष्ट्र की 9 दशकों की निर्बाध सेवा का उत्सव मनाने के लिए पंजाब में आकाशवाणी जालंधर और पटियाला केंद्र कल, 9 मई को एक 'वॉकाथॉन' का आयोजन कर रहे हैं। इसमें उद्घोषक, कलाकार और कर्मचारी सदस्य भाग ले रहे हैं। इस आयोजन को यादगार बनाने के लिए कई श्रोता भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद, आकाशवाणी का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसने आधिकारिक तौर पर ₹आकाशवाणी₹ नाम अपनाया। आज, आकाशवाणी 591 केंद्रों का संचालन करती है, जो भारत की 98 प्रतिशत जनसंख्या तक अपनी पहुंच बनाते हुए 23 भाषाओं और 146 बोलियों में प्रसारण करते हैं। ₹बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय₹ के अपने महान आदर्शों को आत्मसात करते हुए, आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग (एनएसडी) रेडियो प्रसारण के उच्चतम पेशेवर नैतिकता और मानकों का पालन करते हुए, इस विशाल देश के हर दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक निवासी को सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में 24 घंटे समाचार और विचार प्रदान करने का प्रयास करता है।

भगवंत मान सरकार की मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत कैशलेस इलाज से पंजाब में 5000 से अधिक दिल के मरीजों की जान बचाई गई

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

दिल का दौरा पड़ने की स्थिति में हर सेकंड कीमती होता है। कुछ मिनटों की देरी जीवन और मृत्यु के बीच अंतर पैदा कर सकती है। पंजाब में अब समय के साथ चल रही यह जंग लगातार जीती जा रही है, क्योंकि भगवंत मान सरकार की मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत तेज और कैशलेस एंजियोप्लास्टी सेवाएं मरीजों को जरूरत पड़ने पर समय पर यह आपातकालीन इलाज उपलब्ध करवा रही हैं। हार्ट अटैक केवल एक चिकित्सीय आपातकालीन स्थिति ही नहीं होता, बल्कि यह परिवारों पर आर्थिक बोझ भी डालता है। पहले इलाज के लिए पैसों का प्रबंध करने, जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी करने और अस्पताल से मंजूरी लेने में परिवारों का कीमती समय बर्बाद हो जाता था। अब यह स्थिति तेजी से बदल रही है। स्वास्थ्य कार्ड सिस्टम के तहत सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में पहुंचने वाले मरीजों की जांच और आपातकालीन एंजियोप्लास्टी की प्रक्रिया, इलाज से पहले भुगतान में होने वाली देरी के बिना, तेजी से पूरी की जा रही है। यह बदलाव विशेष रूप से गोल्डन ऑवर – अर्थात हार्ट अटैक के बाद के पहले 60 मिनट – के दौरान कीमती ज ानें बचाने में निर्णायक साबित हो रहा है। विश्व स्तर पर हृदय संबंधी बीमारियां मृत्यु का सबसे बड़ा कारण बनी हुई हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, हर साल लगभग 17.9 मिलियन लोगों की मौत हृदय रोगों के कारण होती है। इनमें बड़ी संख्या ऐसे मामलों की होती है, जहां इलाज में हुई देरी जानलेवा साबित होती है। पंजाब की स्वास्थ्य प्रणाली अब इस चुनौती से सक्रिय रूप से निपट रही है। राजभर के डॉक्टरों के अनुसार, दिल की बीमारियों के मामले अब केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि युवाओं में भी तेजी से बढ़ रहे हैं। आरामदायक जीवनशैली, तनाव, अस्वास्थ्यकर खानपान और डायबिटीज के बढ़ते मामले इसके मुख्य कारणों में शामिल हैं। हालांकि, इसके साथ-साथ हृदय संबंधी बीमारियों के आपातकालीन इलाज तक पहुंच भी पहले से बेहतर हुई है। स्टेट हेल्थ एजेंसी के अनुसार, पिछले कुछ महीनों के दौरान स्वास्थ्य योजना के तहत कुल 5,054 हृदय संबंधी सर्जरियां की गई हैं। इनमें 5,000 परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी (पीटीसीए) प्रक्रियाएं शामिल हैं, जिनमें डायग्नोस्टिक एंजियोग्राम भी शामिल हैं, जबकि 54 मामलों में पेरिफेरल एंजियोप्लास्टी की गई। इन इलाजों की कुल लागत लगभग 49.6 करोड़ रुपये रही, जिसमें पीटीसीए प्रक्रियाएं संख्या और कुल खर्च दोनों मामलों में सबसे अधिक रहीं। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि इस योजना का प्रभाव अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा, अब अधिक मरीज उन स्थितियों से भी बच रहे हैं, जिन्हें पहले लगभग जानलेवा माना जाता था। ऐसे नाजुक समय में स्वास्थ्य कार्ड सिस्टम के कारण इलाज की तेजी ही राज्य के लिए जीवनरक्षक बन रही है। अस्पतालों के कार्डियोलॉजी विभाग को तेजी से नई जरूरतों के अनुरूप ढाला जा रहा है। आपातकालीन प्रोटोकॉल इस प्रकार सुव्यवस्थित बनाए जा रहे हैं कि हार्ट अटैक के संभावित मरीजों की तुरंत जांच हो सके और प्रशासनिक कार्रवाई में फंसे बिना उन्हें आवश्यक इलाज उपलब्ध कराया जा सके। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और राजिंदरा अस्पताल, पटियाला के कार्डियोलॉजी विभाग के प्रमुख एवं एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. सौरभ शर्मा ने कहा, स्वास्थ्य कार्ड लोगों को समय पर इलाज दिलाने में मदद कर रहा है।

बड़ी कार्रवाई के दौरान धोखाधड़ी वाले डेबिट नोट और खाली ट्रांसपोर्ट दस्तावेज बरामद: हरपाल सिंह चीमा

पंजाब टैक्स विभाग ने फर्जी बिलिंग के रैकेट का पदार्फाश किया; लुधियाना फर्म का डायरेक्टर गिरफ्तार

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की आर्थिक अपराधों के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस नीति की पुष्टि करते हुए, वित्त, आबकारी एवं कर मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां स्टेट इंटेलिजेंस एंड प्रिवेंटिव यूनिट (सिप्पू) द्वारा हासिल की गई एक बड़ी सफलता की घोषणा की। कार्रवाई के विवरण साझा करते हुए वित्त मंत्री चीमा ने कहा, आज कर विभाग ने एक बेहद संगठित फर्जी बिलिंग नेटवर्क को सफलतापूर्वक ध्वस्त करते हुए मैसर्स एपीआई प्लास्टिक रिसाइक्लर्स प्राइवेट लिमिटेड, लुधियाना के डायरेक्टर एवं अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता परमजीत सिंह को 85.4 करोड़ रुपये के फर्जी लेन-देन पर गलत तरीके से फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने और 15.56 करोड़ रुपये का बड़ा जीएसटी घोटाला करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। जांच के बारे में विस्तार से बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा, आरोपी फर्म योजनाबद्ध और संगठित टैक्स चोरी में शामिल थी। उन्होंने बिना वास्तविक रूप से माल प्राप्त किए, कई राज्यों में गैर-मौजूद और धोखाधड़ी वाली फर्मों द्वारा जारी किए गए फर्जी चालानों (बिलों) के आधार पर फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया।

आगे खुलासा करते हुए आबकारी एवं कर मंत्री ने कहा, हमारी खुफिया टीमों ने यह भी पाया कि लेन-देन में शामिल कई सप्लायर फर्मों को संबंधित जीएसटी अधिकारियों द्वारा पहले ही स्वतः रद्द, निलंबित या गैर-कार्यशील घोषित किया जा चुका था। अब तक सामने आई कुल धोखाधड़ी 15.56 करोड़ रुपये की है और यह आंकड़ा आगे और बढ़ सकता है क्योंकि हमारी जांच अभी भी सख्ती से जारी है।

धोखाधड़ी के जटिल जाल का पदार्फाश करते हुए आबकारी एवं कर मंत्री ने कहा, मैं हमारे विभाग द्वारा ई-वे बिलों और फास्टैग टोल डेटा के किए गए विस्तृत विश्लेषण की सराहना करता हूं। इस विश्लेषण ने निर्णायक रूप से यह साबित कर दिया कि ट्रांसपोर्ट दस्तावेजों में दर्शाए गए वाहन माल की घोषित आवाजाही से बिल्कुल मेल न खाने वाले स्थानों पर पाए गए थे, जो यह साबित करता है कि वास्तव में कोई ढुलाई नहीं हुई थी। हमारी जांच में ऐसे 407 अत्यधिक संदिग्ध वाहन आवागमन का खुलासा हुआ है, जिनमें 2.65 करोड़ रुपये से अधिक का फर्जी आईटीसी शामिल है। आबकारी एवं कर मंत्री चीमा ने दस्तावेजों की जालसाजी की गंभीरता को उजागर करते हुए कहा, हमारी जांच में धोखाधड़ी वाले डेबिट नोटों को शामिल करने के एक नए तरीके का भी खुलासा हुआ है, जिसके जरिए लगभग 5.79 करोड़ रुपये का अतिरिक्त फर्जी आईटीसी तैयार किया गया था। इन डेबिट नोटों में बड़ी अनियमितताएं थीं, जिनमें टैक्स योग्य मूल्य और टैक्स की राशि को बराबर दर्शाया गया था। जीएसटी कानून के तहत यह असंभव है और यह स्पष्ट रूप से फर्जी आईटीसी पैदा करने के लिए रिकॉर्ड में खुली हेराफेरी को साबित करता है। इसके अलावा, पीजीएसटी/सीजीएसटी एक्ट की धारा 67 के तहत की गई तलाशी कार्रवाई के दौरान करदाता के ठिकाने से विभिन्न ट्रांसपोर्टरों की खाली गुड्स रसीद पुस्तिकाएं बरामद की गईं, जो आवाजाही का झूठा रिकॉर्ड तैयार करने के लिए ट्रांसपोर्ट दस्तावेजों की जालसाजी की ओर संकेत करती हैं।

टैक्स चोरों को सख्त संदेश देते हुए आबकारी एवं कर मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, जांच के दौरान एकत्र किए गए ठोस सबूतों के मद्देनजर आरोपी को आज, 8 मई 2026 को पंजाब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, 2017 की धाराओं 69 और 132(1)(_) के तहत गिरफ्तार किया गया है। चूंकि टैक्स चोरी की राशि 5 करोड़ रुपये से कहीं अधिक है, इसलिए यह अपराध गंभीर और गैर-जमानती है तथा इसके लिए जुर्माने के साथ पांच वर्ष तक की कैद की सजा हो सकती है। मैं फर्जी बिलिंग रैकेटों और जीएसटी धोखाधड़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए राज्य के टैक्स विभाग की प्रतिबद्धता को दृढ़ता से दोहराता हूं। राज्य के राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाले फर्जी आईटीसी तैयार करने और उसका इस्तेमाल करने में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

संक्षिप्त-समाचार

गैंगस्टरों ते वार का 108वां दिन: पंजाब पुलिस ने 548 स्थानों पर की छापेमारी; 261 गिरफ्तार

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के तहत शुरू की गई निर्णायक मुहिम गैंगस्टरों ते वार के 108वें दिन पंजाब पुलिस ने आज राज्यभर में गैंगस्टरों के साथियों के चिन्हित और मैप किए गए 548 ठिकानों पर छापेमारी की। उल्लेखनीय है कि गैंगस्टरों ते वार पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए निर्णायक जंग है, जिसकी शुरूआत 20 जनवरी, 2026 को पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव द्वारा की गई थी। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें राज्यभर में विशेष अभियान चला रही हैं। उन्होंने बताया कि 108वें दिन पुलिस टीमों ने पांच हथियारों समेत 261 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिससे इस मुहिम की शुरूआत से अब तक कुल गिरफ्तारियों की संख्या 27,621 हो गई है। इसके अलावा 126 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की गई है, जबकि 34 व्यक्तियों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। पुलिस टीमों ने कार्रवाई के दौरान चार भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से गुप्त रूप से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों के बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं तथा अपराध और आपराधिक गतिविधियों संबंधी सूचना भी दे सकते हैं।

वॉलमार्ट ने भारतीय कारोबारियों के लिए वैश्विक स्तर पर अवसर बढ़ाने के लिए ग्रोथ समिट 2026 का आयोजन किया

चंडीगढ़। वॉलमार्ट ने आज भारत मंडपम, नई दिल्ली में वॉलमार्ट ग्रोथ समिट के दूसरे संस्करण इंडिया 2026 का आयोजन किया। इस आयोजन के जरिए निर्यात के लिए तैयार उद्यमों, एमएसएमई, डिजिटल-फर्स्ट ब्रांड्स, डी2सी विक्रेताओं और सप्लाई चेन भागीदारों को एक मंच पर लाया गया है, ताकि वे देश और विदेश दोनों बाजारों में विकास के नए अवसरों को तलाश सकें। 1990 के दशक से अब तक वॉलमार्ट ने पूरे भारत में मजबूत सप्लायर साझेदारियां की हैं। इससे निर्यात के मामले में दीर्घकालिक क्षमता विकसित करने और वैश्विक स्तर पर विनिर्माण हब के रूप में भारत की उभरती छवि में योगदान मिला है। भारत से अब तक 40 अरब डॉलर से अधिक मूल्य के उत्पादों की सोर्सिंग करने और वॉलमार्ट वृद्धि कार्यक्रम के जरिए 1.15 लाख से अधिक उद्यमियों को सशक्त बनाने के बाद, इस समिट में भारत के निर्यात इकोसिस्टम को और मजबूत करने तथा अधिक से अधिक भारतीय व्यवसायों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने की वॉलमार्ट की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को प्रमुखता से रेखांकित किया गया। वॉलमार्ट एवं फ्लिपकार्ट के अधिकारियों ने ग्लोबल सप्लाई चेन में भारतीय कंपनियों की बढ़ती भूमिका पर जोर दिया। साथ ही स्थानीय साझेदारियां बढ़ाने और क्षमता निर्माण के प्रयासों को रेखांकित किया। जयपुर और कोयंबटूर में क्षेत्रीय ग्रोथ समिट आयोजनों के बाद यह शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। भारत सरकार के विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) और फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गनाजेशंस (एफआईईओ) के साथ मिलकर आयोजित इस कार्यक्रम से प्रमुख एमएसएमई क्लस्टर्स में पहुंच मजबूत करने में मदद मिली। आगामी वर्षों में ऐसे और शिखर सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा।

एसोचैम ने किया हेल्थ, ब्यूटी एवं वेलनेस संगोष्ठी 2026 के तीसरे संस्करण का आयोजन

चंडीगढ़। एसोचैम द्वारा हेल्थ ब्यूटी एंड वेलनेस सिम्पोजियम 2026 के तीसरे संस्करण का सफल आयोजन चंडीगढ़ में किया गया। इस संगोष्ठी में नीति निमार्ताओं, स्वास्थ्य विशेषज्ञों, वेलनेस लीडर्स, उद्यमियों एवं उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा भारत में स्वास्थ्य सेवाओं, वेलनेस, मेडिकल टूरिज्म, प्रिवेंटिव हेल्थकेयर एवं महिला सशक्तिकरण के भविष्य पर विस्तृत चर्चा की। कार्यक्रम में गुलाब चंद कटारिया , माननीय राज्यपाल पंजाब एवं प्रशासक, चंडीगढ़ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में टीबी मुक्त भारत एवं नशा मुक्त पंजाब जैसे अभियानों के माध्यम से स्वस्थ राष्ट्र निर्माण हेतु सामूहिक जिम्मेदारी निभाने की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय राज्यपाल के औपचारिक स्वागत के साथ हुआ। इसके पश्चात राष्ट्रीय गीत ह्ववंदे मातरम्ह्न एवं दीप प्रज्ज्वलन के साथ कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया गया। अपने उद्घाटन संबोधन में राकेश भल्ला , चेयरमैन, एसोचैम चंडीगढ़ यूटी डेवलपमेंट काउंसिल ने आर्थिक विकास, नवाचार एवं सामाजिक कल्याण में स्वास्थ्य एवं वेलनेस क्षेत्र की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डाला। हरमीत सिंह बुट्टर , को-चेयरमैन, एसोचैम चंडीगढ़ यूटी डेवलपमेंट काउंसिल ने अपने विषयगत संबोधन में भारत के वेलनेस इकोसिस्टम को मजबूत करने हेतु एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली एवं उद्योग तथा सरकार के संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया।

वीवो ने किया एक्स300 एफई का अनावरण

चंडीगढ़। अपने कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन्स की सफलता की कड़ी में एक नया अध्याय जोड़ते हुए, वीवो इंडिया ने वीवो एक्स300 एफई लॉन्च किया। स्टाइल और परफॉर्मेंस को महत्व देने वाली नई पीढ़ी के लिए डिजाइन किया गया यह फोन, फ्लैगशिप परफॉरमेंस, उन्नत स्तर की जाइस इमेजिंग और 16.04 सेमी फ्लैट स्क्रीन डिस्प्ले के साथ स्लीक और एक हाथ से इस्तेमाल करने में आसान है। आपके स्टाइल को और भी शानदार बनाने के साथ-साथ जबरदस्त इमेजिंग और परफॉर्मेंस के लिए डिजाइन किया गया, एक्स300 एफई ऐसा स्मार्टफोन अनुभव देता है जिसमें खूबसूरती और फ़्लैगशिप इनोवेशन का बेहतरीन मेल है यह जितना अनोखा है, उतना ही आधुनिक भी। वीवो एक्स300 एफई तीन शानदार रंगों में उपलब्ध है - अर्बन ऑलिव, लिलैक पर्पल और नॉयर ब्लैक; ये रंग प्रकृति और खूबसूरती से प्रेरित हैं, और हर रंग स्टाइल और सौंदर्य का अनोखा मेल है। वीवो एक्स300 एफई का अनावरण करते हुए, श्री विकास टागरा, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, प्रमुख- एक्स सीरीज, वीवो इंडिया ने कहा कि हमारे कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप पोर्टफोलियो को मिली शानदार प्रतिक्रिया ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि आज के उपभोक्ता ऐसे स्मार्टफोन की तलाश में हैं जो प्रीमियम प्रदर्शन के साथ-साथ ऐसे डिजाइन का मेल हो जो उनकी जीवनशैली में सहजता से फिट हो सके। फैशन एडिशन के साथ, हमने एक ऐसा स्मार्टफोन बनाया है जो न केवल बेहतरीन फंक्शनलिटी प्रदान करता है, बल्कि आधुनिक उपयोगकर्ताओं की पहचान, आकांक्षाओं और स्टाइल को भी दर्शाता है।

शांति प्रयासों के बीच तेहरान से लेकर होर्मुज तक तनाव, अमेरिका ने किया हवाई हमला

ईरान ने भी दिया जवाब, अमेरिकी हमलों ने दो ईरानी जहाजों को भी निशाना बनाया

एजेंसी (हि.स.)
तेहरान/वाशिंगटन

अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे शांति प्रयासों के बीच तेहरान से लेकर होर्मुज जलडमरूमध्य तक तनाव बढ़ गया है। ईरान की सेना ने कहा कि अमेरिकी सेना ने तटीय जलक्षेत्र में एक ईरानी तेल टैंकर और संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह बंदरगाह के पास दूसरे जहाज को निशाना बनाया। इसके अलावा दक्षिणी ईरान के बंदर खमीर, सिरिक और केशम द्वीप के नागरिक इलाकों में अमेरिका की वायुसेना ने हवाई हमला किया। ईरान का दावा है कि उसने दुश्मन को माकूल जवाब दिया।

अल जजीरा, इरना और सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) ने कहा कि उसने आत्मरक्षा के लिए यह कदम उठाया। ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य में उसके नौसैनिक बलों पर मिसाइलों, ड्रोन और तेज गति वाली नावों से हमला किया। इसलिए हमला करने के लिए जिम्मेदार ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी ठिकानों पर हुए हमलों को प्यार भरा थप्पड़ बताया है। उन्होंने कहा कि सैन्य विराम जारी है। यह प्रभावी है। उन्होंने पत्रकारों से कहाः ईरान ने हमसे पंगा लिया। हमने उन्हें उड़ा दिया। ट्रंप ने कहा कि युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान युद्ध खत्म करने के अमेरिकी प्रस्ताव पर विचार करने की बात तो कह रहा है पर वह होर्मुज जलडमरूमध्य के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर अपना नियंत्रण औपचारिक रूप से स्थापित करने की भी कोशिश कर रहा है।

शिपिंग इंटेलिजेंस फर्म 'लॉयड्स लिस्ट' का कहना है कि जलडमरूमध्य अब बंद हो गया है। ईरान का कहना है कि उसने हाल ही में एक नई एजेंसी बनाई है। वह यहां से गुजरने वाले जहाजों को मंजूरी देने का काम करेगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यह युद्ध जल्द ही खत्म हो जाएगा। इन कूटनीतिक प्रयासों के बीच, अंतरराष्ट्रीय मानक माने जाने वाले ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें गुरुवार को लगभग 100 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बनी रहीं। युद्ध शुरू होने से पहले यह कीमत 70 डॉलर प्रति बैरल थी।

तेहरान के साथ ताजा तनाव के बीच फ्लोरिडा के टैम्पा स्थित सेंट्रल कमांड ने बयान जारी किया है। बयान में कहा गया कि ताजा हवाई हमला आत्मरक्षा के लिए किया गया। विदेशमंत्री मार्को रूबियो ने पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिका आत्मरक्षा करने में पीछे नहीं हटेगा। बताया गया है कि तेहरान में रात को कई जगह धमाके सुने गए। एयर डिफेंस सिस्टम को चालू किया गया। इस दौरान ईरान की राजधानी में दो धमाके हुए। ईरान के दक्षिणी इलाके के मीनाब शहर में गवर्नर ने घर से बाहर आकर एक नौसैनिक अड्डे पर हुए हमलों की पुष्टि की। बंदर अब्बास शहर में भी ताबड़तोड़ धमाके हुए हैं। संयुक्त सैन्य मुख्यालय के अधिकारियों ने बंदर खमीर और सीरिक पर हुए अमेरिकी हमलों की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि अमेरिकी गोलीबारी से दो ईरानी जहाजों को भी निशाना बनाया गया है।

ट्रंप ने गुरुवार को सोशल ट्रुथ पर कहा कि ईरानी गोलीबारी के बीच अमेरिका के तीन जंगी जहाज होर्मुज से सफलतापूर्वक गुजर गए। जंगी जहाजों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा। अमेरिकी सेना ने ईरान की हमलावर तेज रफ़्तार नावें, मिसाइलें और ड्रोन नष्ट कर दिए। ट्रंप ने ईरानी नेतृत्व को पागल करार देते हुए चेतावनी दी कि अगर तेहरान जल्द किसी समझौते पर राजी नहीं हुआ, तो उसे और भी सख्त सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने कहा है कि इस्लामिक गणराज्य विदेशी दबाव के सामने नहीं झुकेगा।

यूक्रेन ने रूस में विजय दिवस समारोह से पहले की ड्रोन हमलों की बौछार

एजेंसी (हि.स.)
मॉस्को

रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ा युद्ध पांचवें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। पश्चिमी देशों का समर्थन प्राप्त यूक्रेन और रूस के बीच 24 फरवरी 2022 से शुरू यह युद्ध अब वैश्विक कूटनीतिक और आर्थिक तनाव का केंद्र बन गया है। रूस में नौ मई को विजय दिवस मनाया जाएगा। इसके लिए रूस ने एकतरफा सैन्य विराम की घोषणा की है। यह 8 मई आधी रात से प्रभावी होगा। यूक्रेन ने गुरुवार रात रूस पर ड्रोन हमलों की बौछार की है।

तास न्यूज एजेंसी और मॉस्को टाइम्स अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, रूस ने दावा किया है कि हमले के लिए दागे गए यूक्रेन के 347 ड्रोन को मार गिराया है। यूक्रेन ने 20 से ज्यादा रूसी क्षेत्रों को निशाना बनाने के मकसद से ड्रोन की बौछार की। इसे युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन के सबसे बड़े ड्रोन हमलों में से एक माना जा रहा है। इससे पहले मार्च में यूक्रेन ने 389 ड्रोन लॉन्च किए थे। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि मॉस्को समेत कई इलाकों में एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय करना पड़ा।

गुरुवार दिन में भी यूक्रेन ने कई और ड्रोन भेजे। यह मॉस्को की तरफ बढ़ रहे थे। इसका असर राजधानी के हवाई यातायात पर भी पड़ा। मॉस्को के तीन बड़े एयरपोर्ट शेरेमेत्येवो, डोमोडेडोवो और वनुकोवो से करीब 100 उड़ानें रद्द या देर से संचालित हुईं। महत्वपूर्ण है कि रूस के सैन्य विराम की घोषणा से पहले यूक्रेन ने भी मंगलवार आधी रात से हमले रोकने की बात कही थी। यूक्रेन का दावा है कि उसके दूसरे सबसे बड़े शहर खारकीव में रूसी ड्रोन हमले में तीन बच्चों समेत नौ लोग घायल हो गए। रूस ने रातभर में 102 ड्रोन दागे। उनमें से 92 को मार गिराया। रूस के सैन्य अधिकारियों ने कहा कि विजय दिवस समारोह शुरू होने से पहले सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। 9 मई को मॉस्को में मोबाइल इंटरनेट और मैसेजिंग सेवाएं भी बंद रहेंगी। इस बार परेड में टैंक, मिसाइल और भारी सैन्य उपकरण नहीं दिखेंगे। मंत्रालय ने इसकी वजह मौजूदा सुरक्षा स्थिति बताई है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि स्थिति जटिल है। बावजूद इसके विजय दिवस पर अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं। वहीं, रूस ने यूक्रेन को चेतावनी दी है कि अगर विजय दिवस समारोह में कोई बाधा डालने की कोशिश हुई तो कीव पर बड़े स्तर का जवाबी हमला किया जा सकता है। रूस के राष्ट्रपति सलाहकार यूरी उशाकोव ने कहा कि जवाबी कार्रवाई की संभावना को लेकर विशेष तैयारी की जा रही है। रूस के विदेश मंत्रालय ने कीव में मौजूद विदेशी दूतावासों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों को भी एहतियातन अपने कार्यालय खाली करने की सलाह दी है।

इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को यूक्रेन पर आरोप लगाया कि उसने सेंट पीटर्सबर्ग में आम नागरिकों की जगहों पर ड्रोन हमले करने के लिए लातवियाई हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया। यह आरोप तब लगाया गया, जब लातविया ने कहा कि रूस की तरफ से कई ड्रोन उसके इलाके में घुस आए।

पोखरा की फेवा झील में फंसे पांच भारतीय पर्यटकों को बचाया गया

एजेंसी (हि.स.)
काठमांडू

फोटोः हि.स.

नेपाल के पर्यटकीय स्थल पोखरा स्थित फेवा झील में आज सुबह अचानक आई तेज आंधी और ऊंची लहरों के कारण नाव में फंसे पांच भारतीय पर्यटकों को सशस्त्र पुलिस बल ने सुरक्षित बचा लिया।

पोखरा के पुम्दीभुम्दी स्थित लेकहाउस के पास फेवा झील में लकड़ी की नाव से सैर कर रहे भारतीय पर्यटक सुबह आई तेज आंधी की चपेट में आ गए थे। ये सभी पर्यटक फेवा झील के बीच में रहे मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे। बचाए गए लोगों में ललिता केम्बागी, यल्लेशा, प्रवीना काले, भास्कर यल्लेश काले और निलकांक्षा शामिल हैं। भारतीय पर्यटकों के संकट में होने की सूचना मिलते ही फेवा झील के वॉच एंड रेस्क्यू टावर से सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक देवेन्द्र केसी के नेतृत्व में तत्काल एक टीम रवाना की गई। सशस्त्र पुलिस की आपदा प्रबंधन टीम ने सभी को सुरक्षित रूप से झील से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया।

ट्यूनीशिया में पत्रकार जियेद हेनी को एक साल की जेल

ट्यूनिस। ट्यूनीशिया की एक अदालत ने चर्चित पत्रकार जियेद हेनी को न्यायपालिका की आलोचना करने के मामले में एक वर्ष की जेल की सजा सुनाई है। इस फैसले के बाद देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की आजादी को लेकर बहस तेज हो गई है। जियेद हेनी को पिछले महीने उस समय हिरासत में लिया गया था, जब उन्होंने एक लेख में न्यायपालिका के एक फैसले की आलोचना की थी। उनके वकील नफा लारी बी ने अदालत के फैसले को कठोर बताते हुए कहा कि यह ट्यूनीशिया में स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर बढ़ती पाबंदियों को और मजबूत करता है। सजा सुनाए जाने से एक दिन पहले हेनी ने जेल से अपने परिवार के माध्यम से एक पत्र जारी किया था। इसमें उन्होंने कहा कि वह इस मामले में किसी भी फैसले के खिलाफ अपील नहीं करेंगे क्योंकि वह इस मुकदमे को वैध नहीं मानते। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। मानवाधिकार संगठनों और पत्रकार संगठनों का कहना है कि राष्ट्रपति कैस सईद के सत्ता केंद्रीकरण के बाद देश में स्वतंत्र आवाजों पर दबाव लगातार बढ़ा है। वर्ष 2021 में राष्ट्रपति सईद ने निर्वाचित संसद को भंग कर दिया था और बाद में अध्यादेशों के जरिए शासन शुरू किया।

नेपाल में बस्तियां खाली कराए जाने का विरोध

- देश भर में भूमिहीनों का विरोध प्रदर्शन

एजेंसी (हि.स.)
काठमांडू

फोटोः हि.स.

नेपाल में बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के बस्तियां खाली कराए जाने के बाद देशभर के भूमिहीन लोग सड़क पर उतर आए हैं। काठमांडू की 16 बस्तियों से नौ दिनों में 15 हजार से अधिक लोग विस्थापित किये जा चुके हैं। सरकारी और सार्वजनिक जमीन पर बने अनधिकृत ढांचों को हटाने के लिए जारी 35 दिन की नोटिस के विरोध में लोग आंदोलन कर रहे हैं। काठमांडू से नौ दिन पहले शुरू हुआ बस्ती खाली कराने का अभियान अब पूरे देश में चलाने की तैयारी है।

बिना वैकल्पिक व्यवस्था के बस्तियां खाली कराए जाने के विरोध में भूमिहीन तथा अव्यवस्थित लोगों ने शुक्रवार को बुटवल में सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सरकार पहले वास्तविक भूमिहीन और अव्यवस्थित बसोबासियों की पहचान करे और पिछली सरकारों के दौरान भूमि आयोग की तय व्यवस्था के अनुसार उन्हें व्यवस्थित कर लालपुर्जा (मालिकाना प्रमाणपत्र) उपलब्ध कराए। भूमिहीन संघर्ष समिति के संयोजक खगेन्द्र पौडेल ने कहा कि सरकार ने बिना किसी तैयारी और विकल्प के डोजर चलाकर लोगों में आतंक फैलाया है। आज ही मकवानपुर जिले के हेटौंडा में भी संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा की मांग को लेकर सुकुमबासियों ने सड़क पर प्रदर्शन किया।

थाना भर्याङ से शुरू हुई रैली के प्रतिभागियों ने प्रमुख जिला अधिकारी और हेटौंडा के मेयर को ज्ञापन पत्र सौंपा। इसी तरह बर्दिया जिला मुख्यालय गुलरिया में भूमिहीन, मुक्त कमैया और अव्यवस्थित बसोबासियों ने प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि प्रदेश के वन मंत्रालय ने 15 दिन की नोटिस जारी कर लोगों को उजाड़ने की कोशिश की है। बर्दिया की आठों स्थानीय पालिकाओं के प्रमुखों ने बस्तियां खाली कराने संबंधी नोटिस का विरोध किया। इधर काठमांडू के माइतीघर मण्डला में भी भूमिहीन, अधिकारकर्मी और अन्य संगठनों ने अलग-अलग प्रदर्शन किए हैं। भूमिहीनों को को जबरन विस्थापित किए जाने के विरोध में काठमांडू में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार भूमिहीनों पर अमानवीय दमन कर श्वेत आतंक फैला रही है। आज ही रुपन्देही जिले के मोतिपुर क्षेत्र के निवासी भी सरकार द्वारा डोजर चलाकर आतंकित किए जाने के विरोध में सड़क पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि भूमिहीनों के पुनर्वास और कानूनी अधिकार सुनिश्चित किए बिना यदि बस्तियां खाली कराई गईं, तो वे प्रतिरोध करेंगे।

संक्षिप्त-समाचार

नेपाल सरकार ने विदेशों से 15 अवैतनिक महावाणिज्य दूत हटाने का फैसला लिया

काठमांडू। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के नेतृत्व वाली सरकार ने विदेशों में तैनात 15 मानद महावाणिज्यदूतों और मानद वाणिज्यदूतों को हटाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय शुक्रवार सुबह सिंहदरबार में हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक में लिया गया। कैबिनेट बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता सस्मित पोखरेल ने बताया कि विदेश मंत्रालय के प्रस्ताव पर विभिन्न देशों में कार्यरत 15 मानद कूटनीतिक प्रतिनिधियों को पदमुक्त करने का फैसला लिया गया है। इनमें जापान, जॉर्डन, मलेशिया, मंगोलिया, हांगकांग, पाकिस्तान, फिलीपींस, केन्या, जर्मनी, नीदरलैंड, नार्वे, स्पेन सहित कुछ अन्य यूरोपीय देश शामिल है। मंत्रिपरिषद् बैठक ने यह भी निर्णय लिया कि 11 मई को शाम 4 बजे होने वाले संघीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने के लिए राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल से अनुरोध किया जाएगा।

नेपाली सेना ने चीन सटे मुस्तांग में अभ्यास शुरू किया

काठमांडू। नेपाल की सेना ने चीन से सटे मुस्तांग जिले के जोमसोम में आज से दो दिवसीय हाई एल्टीट्यूड सर्च एंड रेस्क्यू अभ्यास शुरू किया है। सेना के अनुसार, इस प्रशिक्षण का उद्देश्य उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ऑक्सीजन की कमी, अत्यधिक ठंड और भौगोलिक दुर्गमता के कारण होने वाले जोखिम और दुर्घटनाओं को कम करना तथा कठिन भू-भाग में खोज और बचाव अभियान को सुदृढ़ बनाना है। इस अभ्यास में 55 से अधिक सेना के जवान भाग ले रहे हैं, जिनमें मुस्तांग, मनांग जिले के भैरवी दल गुल्म की चार टुकड़ियां, इन्द्र बक्स गण और मिलिट्री हाई स्कूल कैसांग के प्रशिक्षु शामिल हैं। इन्द्र बक्स गण के प्रमुख मेजर जनरल गौरव ध्वज खांड ने कहा कि इस अभ्यास का उद्देश्य उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बचाव अभियान चलाने के लिए नेपाली सेना की तकनीकी दक्षता और संचालन क्षमता को बढ़ाना है। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण में ग्लेशियर, पहाड़ी खाइयों और हिमस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में फंसे ट्रेकर्स और यात्रियों के बचाव के तौर तरीके शामिल हैं। आज प्रतिभागियों को गण मुख्यालय के पास एक विशाल चट्टानी पहाड़ी पर रस्सियों की मदद से मॉडल रॉक क्लाइम्बिंग अभ्यास कराया जाएगा। शनिवार को घरपझोंग स्थित मिलिट्री हाईस्कूल के पास लगभग 4,000 मीटर की ऊंचाई पर ग्लेशियर रेस्क्यू अभियान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल की 33वीं बटालियन और जिला प्रहरी कार्यालय, मुस्तांग के प्रतिनिधि भी आज के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित रहे।

मणिपुर के सेनापति -चुराचांदपुर जिले से भारी मात्रा में हथियार एवं गोला-बारूद

इंफाल। राज्य में लगातार सुरक्षा बलों एवं पुलिस की कार्रवाई जारी है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में जारी अभियानों में उग्रवादियों की गिरफ्तारी के साथ ही भारी मात्रा में हथियारों एवं गोला-बारूद के जखीरों की बरामदगी का सिलसिला जारी है। मणिपुर पुलिस मुख्यालय शुक्रवार को आधिकारिक बयान में बताया कि 07 मई को सुरक्षा बलों ने सेनापति जिले के सेनापति थानांतर्गत मारेमई-हेंगबुंग पहाड़ी इलाकों में अभियान चलाते हुए भारी मात्रा में हथियार एवं गोला-बारूद बरामद किया। बरामद सामग्रियों में दो प्वाइंट 22 बोर की राइफल मैगजीन के साथ, एक .303 बोर की राइफल मैगजीन के साथ, एक एमपी5 मैगजीन के साथ, एक एके-47 राइफल मैगजीन के साथ, चार स्थानीय तौर पर बनी बोल्ट एक्शन राइफलें, एक स्थानीय तौर पर बनी शॉटगन, तीन प्वाइंट 32 पिस्तौलें मैगजीन के साथ, दो प्वाइंट 22 बोर की पिस्तौलें मैगजीन के साथ, 79 अलग-अलग कैलिबर के ज़िंदा कारतूस और 13 अलग-अलग कैलिबर के खाली खोखे शामिल हैं। वहीं, अन्य एक अभियान में सुरक्षा बलों ने चुराचांदपुर जिले के चुराचांदपुर थानांतर्गत हेंगकापकोट इलाके से भी हथियार एवं विस्फोटक बरामद किये गये हैं। बरामद सामग्रियों में तीन सिंगल बैरल राइफलें, एक प्वाइंट 303 राइफल, एक पॉम्पी, चार रॉकेट के गोले, एक बेलनाकार आईईडी (500 ग्राम विस्फोटक), एक शंक्वाकार आईईडी (4 किलोग्राम), चार बुलेटप्रूफ जैकेटें, दो हेलमेट, सात एके-47 के खाली खोखे, चार 7.62 एमएम के खाली खोखे और एक रेडियो सेट चार्जर शामिल हैं। फिलहाल, इन दोनों अभियानों में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस इस संबंध आगे की कानूनी कार्रवाई जारी रखे हुए है।

पश्चिम बंगाल माध्यमिक परीक्षा परिणाम घोषित उत्तर दिनाजपुर के अभिरूप भद्र बने टॉपर

कोलकाता। पश्चिम बंगाल माध्यमिक परीक्षा 2026 का परिणाम शुक्रवार को पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा जारी कर दिया गया। इस वर्ष छात्रों की सफलता का प्रतिशत 86.83 फीसदी दर्ज किया गया है। इस वर्ष उत्तर दिनाजपुर जिले के छात्र अभिरूप भद्र ने 700 में 698 अंक हासिल कर पूरे राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया। उन्होंने 99.71 प्रतिशत अंक प्राप्त कर राज्य में टॉप किया। माध्यमिक परीक्षा की मेरिट सूची में इस बार कुल 131 छात्र-छात्राओं ने टॉप 10 में जगह बनाई है। राज्य के टॉप रैंकर्स में अभिरूप भद्र 698 अंकों के साथ पहले स्थान पर रहे। अरित्र दास ने 697 अंक हासिल कर दूसरा स्थान प्राप्त किया। सौम्य पाल 696 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे।

ईडी ने गेमिंग प्लेटफॉर्म गेम्सक्राफ्ट के तीन संस्थापकों को गिरफ्तार किया

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म गेम्सक्राफ्ट के तीन संस्थापकों को शुक्रवार को गिरफ्तार किया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ईडी ने दीपक सिंह, पृथ्वीराज सिंह और विकास तनेजा को धनशोधन निवारण अधिनियम 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया है। दीपक सिंह और पृथ्वीराज सिंह को दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया और उन्हें बेंगलुरु की अदालत में पेश करने के लिए ट्रांजिट रिमांड हासिल की गई है। विकास तनेजा को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया है और उन्हें अदालत में पेश किया गया है। ये गिरफ्तारी तब हुई जब केंद्रीय एजेंसी ने कथित धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित कई प्राथमिकियों का संज्ञान लेते हुए ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और अन्य संबंधित संस्थाओं के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया। ईडी ने एक दिन पहले गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर और कर्नाटक में 17 स्थानों पर छापेमारी भी की थी और कुछ दस्तावेज जब्त किए थे।

नेपाल के नए प्रधान न्यायाधीश की सिफारिश का विरोध

- कोर्ट की सुनवाई पर भी दिखा असर

एजेंसी (हि.स.)
काठमांडू

नेपाल के सर्वोच्च अदालत में वरीयता को दरकिनार करते हुए की गई प्रधान न्यायाधीश की सिफारिश का असर आज सुनवाई में दिखने को मिला है। आज हुई फुल कोर्ट बैठक के चलते दैनिक पेशी के सूची पूर्व निर्धारित समय से लगभग दो घंटे देर से सार्वजनिक हो पाई। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश को आज सुनवाई से अलग रखा गया, जबकि कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश ने खुद को पेशी से अलग कर लिया।

सर्वोच्च अदालत में शुक्रवार को 14 बेंच निर्धारित की गईं, लेकिन कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल और प्रधान न्यायाधीश पद के लिए सिफारिश किए गए न्यायाधीश डॉ. मनोज कुमार शर्मा किसी भी इजलास में शामिल नहीं हुए। इसी तरह, एक अन्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ भी आज की इजलास में मौजूद नहीं हैं। बाकी 15 न्यायाधीशों की इजलास का गठन किया गया है।

फोटोः हि.स.

संवैधानिक परिषद् ने गुरुवार को डॉ. शर्मा को प्रधान न्यायाधीश पद के लिए सिफारिश करने का निर्णय लिया था। कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश मल्ल वरिष्ठता क्रम में पहले स्थान पर थे, लेकिन इसके बावजूद संवैधानिक परिषद् ने चौथे क्रम के शर्मा को चुना। आज हुई फुल कोर्ट बैठक में न्यायाधीशों ने संवैधानिक परिषद् की सिफारिश को लेकर अपने विचार रखे। बैठक में शामिल हुए एक न्यायाधीश के अनुसार परिषद् की यह सिफारिश देश की न्यायपालिका के हित में नहीं है।

नेपाल में प्रधान न्यायाधीश के लिए मनोज शर्मा के नाम की सिफारिश के खिलाफ रिट दायर

काठमांडू। नेपाल के संवैधानिक परिषद द्वारा चौथे वरीयता क्रम के डॉ. मनोज कुमार शर्मा की सिफारिश प्रधान न्यायाधीश पद के लिए करने के निर्णय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में रिट दायर की गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी और अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल ने शुक्रवार कोउच्चतम न्यायालय में अलग-अलग रिट दायर की है। वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी ने बताया कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के विपरीत प्रधान न्यायाधीश की सिफारिश किए जाने के कारण रिट दायर की गई है। इसी तरह अधिवक्ता युवराज ढकाल ने भी उच्चतम न्यायालय में रिट दायर की है। उनका भी कहना है कि प्रधान न्यायाधीश पद के लिए डॉ. शर्मा की सिफारिश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत है।

विपक्षी दलों को प्रधान न्यायाधीश के पद पर मनोज शर्मा के नाम की सिफारिश पर आपत्ति

काठमांडू। नेपाल के विपक्षी दलों ने उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पद पर डॉ. मनोज शर्मा के नाम की सिफारिश का विरोध करते हुए आपत्ति जताई है। डॉ. शर्मा के नाम की सिफारिश गुरुवार को सिंह दरबार में हुई संवैधानिक परिषद की बैठक में की गई। वरीयता क्रम के डॉ. मनोज शर्मा चौथे स्थान पर हैं। बैठक में ही राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल और प्रमुख प्रतिपक्षी दल के नेता भीष्म राज अंगदेम्बे ने अपनी असहमति दर्ज कराई थी। अंगदेम्बे ने पत्रकार सम्मेलन में कहा, न्यायपालिका में परंपरा, मूल्यों और मान्यताओं को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री ने शर्मा के नाम का प्रस्ताव किया।

गुजरात के वडोदरा की शिक्षिका ने हाथ से लिखी 2000 पन्नों की हिंदी में रामायण

फोटोः हि.स.

एजेंसी (हि.स.)
वडोदरा

गुजरात के वडोदरा की शिक्षिका रेखाबेन ठक्कर ने भक्ति और आध्यात्मिकता का अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया है। रेखाबेन ने करीब 20 महीनों की मेहनत और अटूट श्रद्धा से हिंदी भाषा में 2000 पन्नों की हस्तलिखित रामायण तैयार की है। संगीत विषय में स्नातकोत्तर और अंग्रेजी शिक्षिका रेखाबेन ठक्कर कोरोना काल के दौरान टीवी पर प्रसारित रामायण से प्रेरित हुईं और

अपनी बचपन की यादों को ताजा होने के साथ उनके मन में कुछ विशेष और आध्यात्मिक करने का विचार आया। इसके बाद उन्होंने पूरी रामायण अपने हाथों से लिखने का संकल्प लिया। वडोदरा के हरणी-वारसिया रिंग रोड क्षेत्र में रहने वाली रेखाबेन ने इस कार्य के लिए वडोदरा सेंट्रल लाइब्रेरी से रामायण के विभिन्न संस्करणों का अध्ययन किया। इसके बाद लगातार 20 महीनों तक नियमित लेखन कर उन्होंने यह विशाल ग्रंथ तैयार कर अपने संकल्प को पूरा किया। रेखाबेन ने बताया कि हिंदी में रामायाण ग्रंथ के पूथा होने के बाद अब वह इस रामायण का गुजराती भाषा में अनुवाद भी कर रही हैं, ताकि राज्य के लोग भी अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ सकें।

बिहार में लीची की फसल को खतरा, कृषि मंत्रालय ने किया टास्क फोर्स का गठन

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

फोटोः हि.स.

बिहार में लीची की फसल पर मंडरा रहे लीची स्टिंग बग के खतरे को लेकर किसानों की चिंता बढ़ गई है। फसल को हो रहे भारी नुकसान का मामला अब केंद्र सरकार तक पहुंच गया है। इसको लेकर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टास्क फोर्स का गठन किया है जो लीची स्टिंग बग के प्रकोप का आकलन करेगी। मुजफ्फरपुर के राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के निदेशक को कार्यबल का अध्यक्ष बनाया गया है। इस कार्यबल में नौ सदस्य बनाए गए हैं जिसमें बिहार सरकार के उद्यान-सह-बिहार राज्य बागवानी मिशन के निदेशक, बिहार सरकार द्वारा नामित उनके प्रतिनिधि, कृषि विभाग के निदेशक, बिहार सरकार द्वारा नामित उनके प्रतिनिधि, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कीट वैज्ञानिक, समस्तिपुर द्वारा नामति उनके प्रतिनिधि, प्रधान वैज्ञानिक (कीट विज्ञान), बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर द्वारा नामित उनके प्रतिनिधि सदस्य, एकीकृत बागवानी विकास मिशन द्वारा नामित उनके प्रतिनिधि सदस्य, डॉ. जयपाल सिंह चौधरी (वैज्ञानिक) एवं अन्य नाम शामिल हैं। दरअसल, सात मई को शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में आईसीएआर - सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सबट्रॉपिकल हॉर्टीकल्चर लखनऊ में आयोजित कृषक संवाद कार्यक्रम के दौरान बिहार के लीची उत्पादक जिलों से आए किसानों ने इस समस्या को प्रमुखता से उठाया। किसानों ने बताया कि लीची स्टिंग बग के प्रकोप से फलों की गुणवत्ता खराब हो रही है और उत्पादन में भी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए लीची स्टिंग बग के प्रकोप का आकलन करने के लिए विशेषज्ञ कार्यबल गठित करने की मांग की गई है।

शुभारंभ 5 स्थानों पर शुरू हुई 870 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं

गुजरात देश के अग्रणी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में शामिल

- अहमदाबाद, गांधीनगर, बनासकांठा, पाटन और कच्छ जिलों में 13 नए प्रोजेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन किया गया

एजेंसी (हि.स.)
अहमदाबाद

देश के पहले सोलर विलेज मोढेरा के सफल मॉडल के बाद गुजरात अब बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) यानी बिजली संग्रहण प्रणाली के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। यह जानकारी राज्य सूचना विभाग ने दी। मोढेरा के बाद गुजरात में वर्तमान में कुल 5 स्थानों पर 870 मेगावाट क्षमता वाली बैटरी स्टोरेज परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इसके अलावा अहमदाबाद, गांधीनगर, बनासकांठा, पाटन और कच्छ जिलों में 13 नए प्रोजेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन भी किया गया है। हाल ही में अहमदाबाद जिले के साणंद तालुका के चराल गांव में

फोटोः हि.स.

नई बैटरी स्टोरेज प्रणाली शुरू की गई है। इसके अलावा महेसाणा के मोढेरा और कच्छ के लखपत सहित अन्य स्थानों पर भी यह व्यवस्था कार्य काम कर रही है। राज्य सूचना विभाग के बयान के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सोलर पावर प्लांट के साथ बैटरी स्टोरेज प्रणाली को तेजी से विकसित किया गया है। राज्य सरकार ने गुजरात इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी-2025 में आधुनिक ऊर्जा संग्रहण प्रणालियों को विशेष महत्व दिया है। इसके तहत स्वतंत्र बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स, नए रिन्यूएबल ऊर्जा प्रोजेक्ट्स के साथ एकीकृत बैटरी स्टोरेज और मौजूदा ऊर्जा परियोजनाओं से जुड़े स्टोरेज सिस्टम को मंजूरी दी जा रही है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बिजली को संग्रहित करने का कार्य करता है। सोलर और अन्य रिन्यूएबल स्त्रोतों से दिन में बिजली उत्पादन अधिक होता है, जबकि शाम के समय उत्पादन कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में दिन के अतिरिक्त उत्पादन को बैटरी में संग्रहित कर शाम के पीक लोड के दौरान उपयोग किया जा सकता है। इससे बिजली ग्रिड पर अचानक बढ़ने वाले दबाव को कम करने और सप्लाई को स्थिर बनाए रखने में मदद मिलती है। राज्य सरकार प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से कंपनियों को इस क्षेत्र में निवेश के लिए आमंत्रित कर रही है। बैटरी स्टोरेज सिस्टम को रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स के निकट स्थापित करने की योजना बनाई गई है, ताकि अतिरिक्त ऊर्जा को तुरंत संग्रहित किया जा सके और ट्रांसमिशन लॉस कम हो।

ग्रिड क्षमता के अनुसार स्टोरेज सिस्टम के लिए स्थानों का चयन कर रही हैं। यह प्रणाली न केवल बिजली संग्रहण करेगी, बल्कि ग्रिड को वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी सपोर्ट देकर स्थिर बनाए रखने तथा इमरजेंसी बैकअप उपलब्ध कराने में भी सहायक होगी। राज्य सरकार का मानना है कि इन भविष्य उन्मुख परियोजनाओं के माध्यम से गुजरात वर्ष 2030 तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 500 जीडब्ल्यू गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

प्रिंस यादव की घातक गेंदबाजी से पर्पल कैप की रेस हुई रोमांचक

पर्पल कैप की रेस में तीसरे स्थान पर पहुंचे प्रिंस

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में प्रिंस यादव ने शानदार गेंदबाजी से पर्पल कैप की दौड़ को और रोमांचक बना दिया है। गुरुवार को लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हराया, जिसमें प्रिंस यादव ने अहम भूमिका निभाई। प्रिंस यादव ने मुकाबले में तीन विकेट झटके और सीजन में अपने कुल विकेटों की संख्या 16 तक पहुंचा दी। उन्होंने मैच में सबसे बड़ा झटका विराट कोहली को दिया, जिन्हें उन्होंने दूसरी ही गेंद पर शून्य पर आउट कर दिया।

16 विकेट के साथ प्रिंस अब पर्पल कैप तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। उनके बराबर विकेट कगिसो रबाडा और ईशान मलिंगा के भी हैं, लेकिन बेहतर इकॉनमी रेट के कारण

❍ विराट को शून्य पर निपटाकर लखनऊ ने बेंगलुरु को दी पटखनी

प्रिंस उनसे आगे हैं। प्रिंस की इकॉनमी 8.08 है, जबकि रबाडा की 9.23 और मलिंगा की 9.44 रही है।

पर्पल कैप की रेस में फिलहाल भुवनेश्वर कुमार और अंशुल कंबोज संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं। दोनों के नाम 17-17 विकेट दर्ज हैं। हालांकि लखनऊ के खिलाफ मुकाबले में भुवनेश्वर कोई विकेट नहीं ले सके।

ऑरेंज कैप की रेस में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला। विराट कोहली बिना खाता खोले आउट होने के कारण 379 रन के साथ नौवें स्थान पर बने हुए हैं। वहीं मिचेल मार्श ने शानदार शतक लगाकर लंबी छलांग

फोटोः हि.स.

लगाई। उन्होंने 56 गेंदों में 111 रन की पारी खेली, जिसके बाद उनके कुल रन 367 हो गए और वह 12वें स्थान पर पहुंच गए। ऑरेंज कैप की सूची में फिलहाल हेनरिक क्लासेन 494 रन के साथ शीर्ष पर हैं। उनके बाद अभिषेक शर्मा 475 रन के साथ दूसरे स्थान पर हैं। इसके अलावा केएल राहुल 445 रन के साथ तीसरे, ईशान किशन 409 रन के साथ चौथे और वैभव सूर्यवंशी 404 रन के साथ पांचवें स्थान पर मौजूद हैं।

पर्पल कैप की रेस

भुवनेश्वर कुमारः 17 विकेट (इकॉनमीः 8.40)। **अंशुल कंबोजः** 17 विकेट (इकॉनमीः 8.15)। **प्रिंस यादवः** 16 विकेट (इकॉनमीः 8.08)। **कगिसो रबाडाः** 16 विकेट (इकॉनमीः 9.23)। ईशान मलिंगाः 16 विकेट (इकॉनमीः 9.44)।

ऑरेंज कैप की रेस

हेनरिक क्लासेनः 494 रन
अभिषेक शर्माः 475 रन
केएल राहुलः 445 रन
ईशान किशनः 409 रन
वैभव सूर्यवंशीः 404 रन

इनामी राशि नहीं बढ़ी तो खिलाड़ी कर सकते हैं फ्रेंच ओपन 2026 का बहिष्कार

एजेंसी (हि.स.)
पेरिस

फोटोः हि.स.

फ्रेंच ओपन 2026 की इनामी राशि को लेकर खिलाड़ियों और आयोजकों के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। खिलाड़ियों का कहना है कि टूर्नामेंट की कमाई में उन्हें उचित हिस्सा नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते अब बहिष्कार तक की बात सामने आने लगी है। विश्व नंबर एक यानिक सिनर ने गुरुवार को साफ कहा कि खिलाड़ी खुद को सम्मानित महसूस नहीं कर रहे हैं और यदि इनामी राशि में बढ़ोतरी नहीं हुई तो फ्रेंच ओपन के बहिष्कार पर विचार किया जा सकता है।

महिला टेनिस स्टार आर्यना सबालेंका ने मंगलवार को खिलाड़ियों के पक्ष में खुलकर समर्थन जताते हुए कहा था कि खिलाड़ियों को टूर्नामेंट की कुल कमाई का 15 प्रतिशत से भी कम हिस्सा मिल रहा है, जबकि उनकी मांग 22 प्रतिशत हिस्सेदारी की है।

मौजूदा रोलां गैरों चैंपियन कोको गॉफ ने भी खिलाड़ियों के रुख का समर्थन किया। खिलाड़ियों का मानना है कि टेनिस जैसे बड़े खेल में उनकी मेहनत के मुकाबले आर्थिक हिस्सेदारी काफी कम है। विवाद तब और बढ़ गया जब फ्रेंच ओपन आयोजकों ने कुल इनामी राशि में 9.5 प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए इसे 6 करोड़ 17 लाख यूरो कर दिया। हालांकि खिलाड़ियों ने कहा कि इससे वास्तविक समस्या हल नहीं होती। खिलाड़ियों की ओर से जारी संयुक्त बयान में कहा गया, टूर्नामेंट की कुल आय में खिलाड़ियों की हिस्सेदारी 2024 में 15.5 प्रतिशत थी, जो 2026 में घटकर अनुमानित 14.9 प्रतिशत रह जाएगी। दिग्गज खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने भी इस मुद्दे पर खुलकर खिलाड़ियों का समर्थन किया और खासतौर पर सबालेंका की तारीफ की। जोकोविच ने कहा, मुझे खुशी है कि हमारे खेल के बड़े खिलाड़ी आगे आकर टेनिस की राजनीति और उसकी बारीकियों को समझ रहे हैं। सबालेंका सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि सभी खिलाड़ियों के हित के लिए आवाज उठा रही हैं। उन्होंने कहा, मेरे लिए यही असली नेतृत्व है। मुझे उम्मीद है कि वह इसी तरह खिलाड़ियों की आवाज उठाती रहेंगी। मैं उनके इस कदम को सलाम करता हूं। जोकोविच लंबे समय से खिलाड़ियों के अधिकारों को लेकर मुखर रहे हैं। वह प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर्स एसोसिएशन (पीटीपीए) के संस्थापकों में शामिल हैं। पीटीपीए का मानना है कि फ्रेंच ओपन इनामी राशि विवाद यह साबित करता है कि टेनिस व्यवस्था में बड़े सुधार की जरूरत है।

मैग्नस कार्लसन ने 'टेपे सिगेमैन एंड कंपनी शतरंज टूर्नामेंट 2026' का खिताब जीता

एजेंसी (हि.स.)
माल्मो

फोटोः हि.स.

विश्व नंबर-1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने गुरुवार को भारतीय ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगैसी को सडन डेथ प्लेऑफ में हराकर टेपे सिगेमैन एंड कंपनी शतरंज टूर्नामेंट 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया। मुख्य टूर्नामेंट में अपराजित रहने वाले अर्जुन एरिगैसी ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन खिताबी मुकाबले में उन्हें मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा। टाईब्रेकर की दो बाजियों में दोनों खिलाड़ियों ने एक-एक जीत दर्ज की, जिसके बाद मुकाबला सडन डेथ तक पहुंचा, जहां कार्लसन ने बाजी मार ली।

यह दूसरी बार है जब अर्जुन इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में खिताब जीतने से चूक गए। इससे पहले 2024 में भी वह संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे थे। अर्जुन अंतिम राउंड में 4.5/6 अंकों के साथ एकल बढ़त पर थे, जबकि कार्लसन और यागिज कान एरदोगमुस उनसे आधा अंक पीछे थे। अगर अर्जुन अंतिम राउंड में एंडी वुडवर्ड को हरा देते तो वह सीधे चैंपियन बन जाते, लेकिन मुकाबला ड्रॉ रहने के कारण कार्लसन को बराबरी का मौका मिल गया। दूसरी ओर कार्लसन ने अंतिम राउंड में एरदोगमुस को हराकर अर्जुन की बराबरी कर ली और टूर्नामेंट को प्लेऑफ तक पहुंचा दिया। गौरतलब है कि टूर्नामेंट के पहले राउंड में अर्जुन एरिगैसी ने कार्लसन के खिलाफ मुकाबला ड्रॉ कराया था।

एस्टन विला ने नॉटिंघम फॉरेस्ट को रौंदकर यूरोपा लीग फाइनल में बनाई जगह

बर्मिंघम। एस्टन विला ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गुरुवार को नॉटिंघम फॉरेस्ट को 4-0 से हराकर यूरोपा लीग के फाइनल में प्रवेश कर लिया। दो चरणों के सेमीफाइनल में एस्टन विला ने कुल 4-1 से जीत दर्ज की। अब फाइनल में एस्टन विला का सामना फ्राइबर्ग से 20 मई को इस्तांबुल में होगा। फ्राइबर्ग ने दूसरे सेमीफाइनल में ब्रागा को 3-1 से हराकर कुल 4-3 से मुकाबला अपने नाम किया। पहले चरण में 0-1 से पिछड़ने के बाद कोच उनाई एमरी की टीम ने घरेलू मैदान विला पार्क में आक्रामक शुरूआत की। मैच के 36वें मिनट में ओली वॉटकिंस ने एमिलियानो बुएंदिया के शानदार मूव के बाद आसान गोल कर टीम को बढ़त दिलाई। दूसरे हाफ के 58वें मिनट में एमिलियानो बुएंदिया ने पेनल्टी पर गोल दागकर बढ़त दोगुनी कर दी। नॉटिंघम के खिलाड़ी निकोला मिलेंकोविच द्वारा पाउ टोरेस की जर्सी खींचने पर रेफरी ने पेनल्टी दी थी। इसके बाद कप्तान जॉन मैकगिन ने 77वें और 80वें मिनट में लगातार दो गोल कर मुकाबले को पूरी तरह एकतरफा बना दिया। उनके गोल के बाद स्टेडियम में मौजूद करीब 43 हजार दर्शक खुशी से झूम उठे। मुकाबला देखने पहुंचे ब्रिटेन के प्रिंस विलियम भी एस्टन विला की जीत का जश्न मनाते नजर आए।

क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी प्रो लीग में पूरे किए 100 गोल, अल-नस्त्र की शानदार जीत

एजेंसी (हि.स.)
रियाद

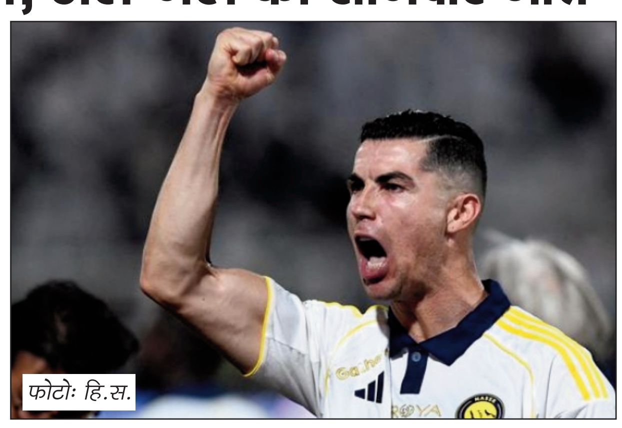
फोटोः हि.स.

दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने वीरवार को सऊदी प्रो लीग में अपना 100वां गोल दागकर एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली। रोनाल्डो के गोल की बदौलत अल-नस्त्र ने अल-शबाब को 4-2 से हराकर अंक तालिका में शीर्ष पर अपनी बढ़त मजबूत कर ली। 41 वर्षीय रोनाल्डो ने मैच के 75वें मिनट में सादियो माने के क्रॉस पर शानदार फिनिश करते हुए यह खास मुकाम हासिल किया। यह उनके पेशेवर करियर का 971वां गोल भी रहा। मौजूदा सत्र में रोनाल्डो अब तक 26 लीग गोल कर चुके हैं।

अल-नस्त्र के मुख्य कोच जॉर्ज जीसस ने मैच के बाद कहा, रोनाल्डो हमेशा आक्रमण में खतरनाक साबित होते हैं और आज भी उन्होंने यह दिखा दिया। इस मुकाबले में जुआओ फेलिक्स ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन गोल दागे। जुलाई में चेल्सी से टीम में शामिल हुए फेलिक्स लगातार बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे हैं। इस जीत के साथ अल-नस्त्र ने 32 मैचों में 82 अंक हासिल कर लिए हैं और वह दूसरे स्थान पर मौजूद अल-हिलाल से पांच अंक आगे निकल गया है। हालांकि अल-हिलाल के पास अभी तीन मैच बाकी हैं। अब अल-नस्त्र का अगला मुकाबला अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी अल-हिलाल के खिलाफ होगा, जिसे लीग खिताब की दौड़ में निर्णायक माना जा रहा है। कोच जॉर्ज जीसस ने कहा, यह डर्बी मुकाबला बेहद अहम है। हम पूरी एकाग्रता के साथ इसकी तैयारी कर रहे हैं क्योंकि छोटे-छोटे पल मैच का परिणाम तय कर सकते हैं। पांच बार के बैलन डी'ऑर विजेता रोनाल्डो दिसंबर 2022 में अल-नस्त्र से जुड़ने के बाद से अभी तक सऊदी अरब में कोई बड़ा खिताब नहीं जीत सके हैं।

फीफा विश्व कप 2030 तक ब्राजील के कोच बने रहेंगे कार्लो एंसेलोटी

एजेंसी (हि.स.)
साओ पाउलो

फोटोः हि.स.

ब्राजील फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कार्लो एंसेलोटी को 2030 फीफा विश्व कप तक पद पर बनाए रखने की तैयारी पूरी हो चुकी है। ब्राजील फुटबॉल महासंघ (सीबीएफ) ने वीरवार को इसकी जानकारी दी। इटली के दिग्गज कोच कार्लो एंसेलोटी ने पिछले वर्ष ब्राजील टीम की कमान संभाली थी। उनके मार्गदर्शन में पांच बार की विश्व चैंपियन ब्राजील ने 2026 फीफा विश्व कप के लिए सफलतापूर्वक क्वालीफाई किया, जिसकी मेजबानी अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको संयुक्त रूप से करेंगे। 66 वर्षीय एंसेलोटी इससे पहले रियल मैड्रिड, एसी मिलान और चेल्सी जैसे बड़े क्लबों को कोचिंग दे चुके हैं। उनके मौजूदा अनुबंध को बढ़ाने को लेकर पिछले कई महीनों से सीबीएफ के साथ बातचीत चल रही थी। सीबीएफ अध्यक्ष समीर शाउद ने फोटार्लेजा में आयोजित फुटप्रो एक्सपो सम्मेलन में कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि विश्व कप से पहले एंसेलोटी के नए अनुबंध की आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सीबीएफ और एंसेलोटी के कानूनी सलाहकार नए अनुबंध की शर्तों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। एंसेलोटी भी कई बार यह संकेत दे चुके हैं कि वह 2026 विश्व कप के बाद भी ब्राजील टीम के साथ बने रहना चाहते हैं। ब्राजील कोच 18 मई को रियो डी जनेरियो में विश्व कप के लिए अपनी अंतिम टीम की घोषणा करेंगे। इसके बाद ब्राजील टीम 31 मई को माराकाना स्टेडियम में पनामा के खिलाफ विदाई मुकाबला खेलेगी। विश्व कप के दौरान ब्राजील टीम न्यू जर्सी में अपना बेस कैंप बनाएगी।

भारत के महान सपूतः महाराणा प्रताप-त्याग वीरता और अखंड स्वाभिमान की अमर गाथा

भारतीय इतिहास की बात जब भी वीरता और मातृभूमि के प्रति समर्पण की आती है, तो एक ही नाम जेहन में सबसे पहले कौंधता है-मेवाड़ के सूर्य महाराणा प्रताप। प्रताप केवल एक राजा का नाम नहीं है, बल्कि वह एक ऐसे विचार का नाम है जिसने शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के सामने झुकने के बजाय घास की रोटी खाना और जंगलों में रहना स्वीकार किया, लेकिन अपनी स्वतंत्रता का सौदा नहीं किया।

जन्म और प्रारंभिक जीवनः एक योद्धा का उदय

महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई, 1540 (विक्रम संवत 1597, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया) को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। उनके पिता मेवाड़ के शासक महाराणा उदयसिंह द्वितीय थे और माता रानी जयवंता बाई थीं। जयवंता बाई स्वयं एक साहसी और धर्मपरायण महिला थीं, जिन्होंने प्रताप को बचपन से ही वीरता और स्वाभिमान के संस्कार दिए। प्रताप का बचपन मेवाड़ की अरावली पहाड़ियों के बीच बीता। वहां रहने वाली भील जनजातियों के साथ उन्होंने शस्त्र संचालन सीखा। भील उन्हें प्यार से 'कीका' कहकर बुलाते थे। बचपन से ही प्रताप की कद-काठी और निडर स्वभाव ने यह संकेत दे दिए थे कि वह भविष्य में मेवाड़ के गौरव को पुनर्स्थापित करेंगे।

राज्याभिषेक और संघर्ष की शुरूआत

महाराणा उदयसिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ की गद्दी को लेकर कुछ आंतरिक कलह हुई। उदयसिंह अपनी प्रिय रानी के पुत्र जगमाल को राजा बनाना चाहते थे, लेकिन मेवाड़ के सामंतों और जनता ने प्रताप की योग्यता को देखते हुए 28 फरवरी, 1572 को गोगुंदा में उनका राज्याभिषेक किया। यह वह दौर था जब मुगल सम्राट अकबर अपनी विस्तारवादी नीति के तहत पूरे भारत को अपने अधीन करना चाहता था। लगभग सभी राजपूत राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन प्रताप ने स्पष्ट कर दिया कि वह मेवाड़ को किसी भी कीमत पर गुलाम नहीं होने देंगे। अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए चार दूत भेजे (जलाल खान, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल), लेकिन प्रताप ने हर बार संधि के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उनका एक ही जवाब था– 'मैं अपने पूर्वजों की धरती का स्वतंत्र शासक हूँ और रहूँगा।'

हल्दीघाटी का युद्धः जब अरावली की मिट्टी लाल हुई

18 जून, 1576 को इतिहास का सबसे भयानक और गौरवशाली युद्ध 'हल्दीघाटी' के मैदान में लड़ा गया। एक ओर अकबर की विशाल सेना थी जिसका नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह कर रहे थे, और दूसरी ओर मुट्ठी भर राजपूत योद्धा और भील सेना, जिसका नेतृत्व स्वयं महाराणा प्रताप कर रहे थे। हल्दीघाटी के युद्ध में प्रताप ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। उन्होंने अपने घोड़े 'चेतक' पर सवार होकर सीधे मान सिंह के हाथी पर आक्रमण कर दिया। यद्यपि मुगल सेना संख्या में बहुत अधिक थी, लेकिन प्रताप के योद्धाओं ने उन्हें दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। इसी युद्ध के दौरान चेतक ने एक नाले को लांघकर प्रताप की जान बचाई और स्वयं वीरगति को प्राप्त हुआ। हल्दीघाटी न कोई जीता, न कोई हारा, लेकिन इसने प्रताप को 'अजेय' बना दिया।

संकट का समय और भामाशाह का साथ

हल्दीघाटी के बाद का समय प्रताप के लिए अत्यंत कठिन था। मुगलों ने उनके किलों पर कब्जा कर लिया था। प्रताप अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जंगलों में भटकने लगे। ऐतिहासिक कहानियों के अनुसार, एक समय ऐसा आया जब उनके परिवार को घास की रोटियां खानी पड़ीं। मुगलों द्वारा दी गई विपुल सुख-सुविधाओं को ठुकराकर उन्होंने जंगलों की खाक छानना बेहतर समझा। इस संकट के समय में मेवाड़ के प्रसिद्ध दानवीर भामाशाह सामने आए। उन्होंने अपनी सारी संचित संपत्ति (20 लाख स्वर्ण मुद्राएं और 25 लाख रुपए) प्रताप के चरणों में रख दी। इस धन से प्रताप ने दोबारा सेना संगठित की और मुगलों के खिलाफ 'छापामार युद्ध' शुरू किया।

दिवेर का युद्ध और विजय अभियान

1582 में 'दिवेर का युद्ध' हुआ, जिसे कर्नल टॉड ने 'मेवाड़ का मैराथन' कहा है। इस युद्ध में प्रताप ने मुगल सेना को करारी शिकस्त दी। इसके बाद उन्होंने एक-एक करके कुंभलगढ़, उदयपुर और गोगुंदा सहित मेवाड़ के 36 ठिकानों को मुगलों से मुक्त करा लिया। उन्होंने 'चावंड' को अपनी नई राजधानी बनाया और वहां शासन व्यवस्था को सुदृढ़ किया।

अंतिम समय और महान विदाई

अपने जीवन के अंतिम वर्षों में महाराणा प्रताप ने मेवाड़ का अधिकांश हिस्सा पुनः जीत लिया था। केवल चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ को छोड़कर शेष मेवाड़ स्वतंत्र था। 19 जनवरी, 1597 को एक शिकार के दौरान गहरी चोट लगने के कारण चावंड में इस महान योद्धा का निधन हो गया। कहते हैं कि जब अकबर को प्रताप की मृत्यु का समाचार मिला, तो उसकी आँखों में भी आंसू आ गए थे। अकबर ने कहा था, 'प्रताप ने कभी अपनी गरिमा नहीं छोड़ी और वह दुनिया का सबसे महान योद्धा था।' महाराणा प्रताप केवल राजस्थान या भारत के नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के स्वतंत्रता प्रेमियों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि साधन कम होने पर भी यदि हौसला बुलंद हो और लक्ष्य पवित्र हो, तो बड़ी से बड़ी शक्ति को भी झुकाया जा सकता है। आज उनकी जयंती पर हम उस महान आत्मा को नमन करते हैं जिसने भारत की मिट्टी को स्वाभिमान से सींचा।

भाई कन्हैया की विरासत रेड क्रॉस की सच्ची भावना को दर्शाती है : कटारिया

विश्व रेड क्रॉस दिवस पर प्रशाक ने मानवता एवं नशा मुक्त समाज के लिए सामूहिक संकल्प का आह्वान किया

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

पंजाब के राज्यपाल, यू.टी. चंडीगढ़ के प्रशासक एवं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, पंजाब के अध्यक्ष श्री गुलाब चंद कटारिया ने आज पंजाब लोक भवन में आयोजित विश्व रेड क्रॉस दिवस के राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता की।

समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने नागरिकों से करुणा, सहयोग और निस्वार्थ सेवा की भावना को सुदृढ़ कर समावेशी समाज के निर्माण का आह्वान किया। इस वर्ष की थीम ह्लऑन द साइड ऑफ ूमैनिटी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह अवसर उन स्वयंसेवकों को सम्मानित करने का है, जो बिना किसी भेदभाव के संकटग्रस्त लोगों की सेवा करते हैं।

राज्यपाल ने विनाशकारी बाढ़ के दौरान पंजाब रेड क्रॉस द्वारा किए गए सराहनीय राहत कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रभावित परिवारों को भोजन, दवाइयां, टेंट तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री उपलब्ध कराई गई। ह्लऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब रेड क्रॉस ने आपदा प्रतिक्रिया प्रशिक्षण, सिविल डिफेंस सहयोग एवं विशाल रक्तदान शिविरों के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

नशे की बढ़ती समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्यपाल ने इसे पंजाब के युवाओं के लिए गंभीर चुनौती बताया। ह्लयुद्ध नशों विरुद्ध अभियान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब के सीमावर्ती जिलों में रेड क्रॉस के माध्यम से आयोजित पदयात्राओं ने युवाओं एवं स्थानीय समुदायों में जागरूकता पैदा की है। उन्होंने लोगों से नशे के खिलाफ इस संघर्ष को जन आंदोलन में बदलने का आह्वान किया, ताकि स्वस्थ, सुरक्षित एवं समृद्ध पंजाब का निर्माण हो सके। गुरु गोबिंद सिंह जी के शिष्य भाई कन्हैया का उदाहरण देते हुए राज्यपाल ने कहा कि पंजाब की निस्वार्थ सेवा एवं करुणा की परंपरा वास्तव में रेड क्रॉस आंदोलन की भावना को प्रतिबिंबित करती है। उन्होंने कहा कि भाई कन्हैया ने युद्ध के दौरान बिना किसी भेदभाव के दोनों पक्षों के घायल सैनिकों की सेवा की थी, जो रेड क्रॉस की स्थापना से सदियों पहले मानवता एवं निस्वार्थ सेवा के मूल्यों का उदाहरण था।

राज्यपाल ने भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, पंजाब राज्य शाखा द्वारा स्वस्थ एवं सशक्त समाज के निर्माण के लिए किए जा रहे विभिन्न मानवीय प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने टीबी मरीजों को पोषण किट वितरित कर ह्लटीबी मुक्त पंजाब अभियान को दिए जा रहे सहयोग का विशेष उल्लेख किया।

कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने हेनरी ड्यूनांट एवं भाई कन्हैया को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सीपीआर एवं प्राथमिक उपचार का प्रदर्शन किया गया, जबकि रेड क्रॉस स्वयंसेवकों ने नशे के दुष्प्रभावों पर आधारित नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। नशामुक्त हो चुके व्यक्तियों ने अपने अनुभव साझा किए तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत भांगड़ा प्रस्तुति भी दी गई। राज्यपाल ने मानवीय योगदान देने वाले दानदाताओं को सम्मानित किया तथा जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीनें एवं टीबी मरीजों को पोषण किट वितरित किए।

इस अवसर पर प्रशासक सलाहकार परिषद के सदस्य संजय टंडन, राज्यपाल के अतिरिक्त मुख्य सचिव विवेक प्रताप सिंह, रेड क्रॉस सोसाइटी पंजाब के सचिव शिवदुलार सिंह ढिल्लों, उपायुक्त चंडीगढ़ निशांत कुमार यादव सहित अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।

कल श्री सोमनाथ मंदिर के प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में साकेतड़ी शिव मंदिर में मनाया जाएगा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

साकेतड़ी से शिव मंदिर तक निकाली जाएगी कलश यात्रा, शिव महिमा से गुंजित होगा पंचकूला

अतिरिक्त उपायुक्त श्रीमती निशा यादव ने बताया कि सोमनाथ मंदिर के प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 11 मई को साकेतड़ी स्थित शिव मंदिर में जिला स्तरीय सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया जाएगा। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में आयोजित राष्ट्रीय समारोह से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का लाइव संबोधन भी प्रसारित किया जाएगा, जिसका लाईव संबोधन साकेतड़ी से शिव मंदिर में श्रद्धालु सुन व देख सकेंगे। साकेतड़ी से शिव मंदिर तक कलश यात्रा निकाली जाएगी।

अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ साकेतड़ी से शिव मंदिर तक निकाली जाने वाली भव्य कलश यात्रा से होगा। यात्रा में श्रद्धालु शिव भक्ति और धार्मिक जयघोषों के साथ भाग लेंगे। पूरे मार्ग पर शिव महिमा का गुणगान होगा और पंचकूला भक्तिमय नारो से गुंजित होगा। शिव मंदिर में पहुंचने पर भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाएगा। उसके बाद विभिन्न धार्मिक व सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होगी।

उन्होंने बताया कि यह पर्व केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की अटूट आस्था और सांस्कृतिक गौरव के पुनर्जागरण का प्रतीक है। इस विशेष दिन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए जिला के प्रमुख साकेतड़ी स्थित शिव मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव का मुख्य आकर्षण गुजरात के सोमनाथ में आयोजित होने वाला राष्ट्रीय कार्यक्रम होगा। इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने के लिए इस अवसर पर भजन-कीर्तन, ओंकार जाप और शिव तांडव जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। अतिरिक्त उपायुक्त श्रीमती निशा यादव ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व कार्यक्रम को लेकर साकेतड़ी स्थित शिव मंदिर का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

एनएचपीसी द्वारा भारत की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना

2000 मेगावाट सुबनसिरी लोअर परियोजना की चौथी यूनिट के वाणिज्यिक संचालन की घोषणा

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

एनएचपीसी लिमिटेड, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के नवरत्न उद्यम ने अरुणाचल प्रदेश एवं असम में स्थित अपनी 2000 मेगावाट (8 ७ 250 मेगावाट) क्षमता वाली सुबनसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना की चौथी यूनिट (यूनिट संख्या # 4, 250 मेगावाट) के सफल वाणिज्यिक संचालन की घोषणा की है। यह यूनिट 8 मई 2026 को 00:00 बजे से वाणिज्यिक संचालन में आ गई, जिससे राष्ट्रीय ग्रिड में 250 मेगावाट स्वच्छ जलविद्युत क्षमता जुड़ गई है। इस अवसर पर श्री भूपेंद्र गुप्ता, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी ने भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय तथा अरुणाचल प्रदेश और असम की सरकारों के निरंतर सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने श्री राजेन्द्र प्रसाद, कार्यपालक निदेशक के नेतृत्व में सुबनसिरी लोअर परियोजना टीम के समर्पित प्रयासों की सराहना की, साथ ही एनएचपीसी के निगम मुख्यालय के विभिन्न विभागों के बहुमूल्य योगदान की भी प्रशंसा की।

उन्होंने कहा कि इस यूनिट की सफल कमीशनिंग एनएचपीसी की मजबूत तकनीकी विशेषज्ञता और परियोजना निष्पादन क्षमता को दशार्ता है तथा भारत सरकार के सतत एवं आत्मनिर्भर ऊर्जा क्षेत्र के दृष्टिकोण के अनुरूप राष्ट्र की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने में एनएचपीसी की महत्वपूर्ण भूमिका को और मजबूत करता है। उन्होंने यह विश्वास भी व्यक्त किया कि परियोजना की शेष यूनिटों की कमीशनिंग निर्धारित समयसीमा के भीतर की जाएगी। इस यूनिट के आरंभ होने के साथ ही, सुबनसिरी लोअर परियोजना ने अपनी नियोजित 2000 मेगावाट क्षमता में से 1000 मेगावाट की कुल परिचालन क्षमता हासिल कर ली है, जो परियोजना के चरणबद्ध संचालन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह परियोजना ग्रिड स्थिरता को सुदृढ़ करने, पीक पावर मांग को पूरा करने तथा राष्ट्रीय ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा के समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वाणिज्यिक संचालन से पूर्व, इस यूनिट का 1 मई 2026 को सफल ट्रायल रन पूरा किया गया था, जो परियोजना के पूर्ण संचालन की दिशा में निरंतर प्रगति को दशार्ता है।

गुरुग्राम में जनगणना तैयारियों की समीक्षा की गई अधिकारियों को कार्य शीघ्र शुरू करने के निर्देश

सिटी दर्पण संवाददाता
गुरुग्राम

हरियाणा के जनगणना निदेशक डॉ. ललित जैन ने गुरुवार को गुरुग्राम में आगामी जनगणना कार्यों की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उपायुक्त गुरुग्राम श्री उत्तम सिंह, आईएएस, सिटी मजिस्ट्रेट गुरुग्राम श्रीमती नागपाल, जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती इंदु बोकेन, जिले के सभी तहसीलदार, चार्ज ऑफिसर तथा नगर निगम गुरुग्राम एवं नगर निगम मानेसर के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. ललित जैन ने निर्देश दिए कि जनगणना का वास्तविक कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जाए। उन्होंने बताया कि जनगणना के लिए मकानों के नक्शे एवं अन्य प्रारम्भिक तैयारियां पहले ही पूरी की जा चुकी हैं और अब फील्ड स्तर पर कार्य में तेजी लाने की आवश्यकता है। उन्होंने सभी प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों से अपील की कि वे अपनी-अपनी ड्यूटी पर समय से रिपोर्ट करें क्योंकि जनगणना राष्ट्र निर्माण का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। उन्होंने कहा कि इस कार्य के निष्पादन में विभाग पूरी तरह से कर्मचारियों के साथ खड़ा है।

डॉ. जैन ने कहा कि वर्तमान मौसम की अनुकूलता को देखते हुए जनगणना कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जाए ताकि निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्य पूर्ण हो सके। उन्होंने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों (फहअ) के प्रतिनिधियों से भी अपील की कि वे जनगणना कर्मियों को अपनी सोसायटी एवं परिसरों में प्रवेश करने दें तथा जनगणना कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

उन्होंने यह भी स्मरण कराया कि जनगणना कर्मियों को सूचना न देना, गलत सूचना देना अथवा जनगणना कार्य में सहयोग न करना कानूनन दंडनीय अपराध है। इस अवसर पर उपायुक्त गुरुग्राम श्री उत्तम सिंह, आईएएस ने भी अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनगणना कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जाए तथा इसकी प्रगति की समीक्षा प्रत्येक सप्ताह की जाएगी ताकि कार्य समयबद्ध एवं प्रभावी ढंग से पूरा हो सके।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी उपायुक्तों को समाधान शिविर में आई समस्याओं का बिना विलंब किए समाधान करने के दिए निर्देश

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

अतिरिक्त उपायुक्त ने एसीएस को समाधान शिविर में आई समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने का दिया आश्वासन

सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण तथा अंत्योदय विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव जी अनुपमा ने चंडीगढ से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी उपायुक्तों के साथ समाधान शिविर की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की व उनकी समीक्षा की। उन्होंने सभी उपायुक्तों को बिना विलंब के समाधान शिविर की सभी तरह की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के निर्देश दिए। अतिरिक्त उपायुक्त श्रीमती निशा यादव ने अतिरिक्त मुख्य सचिव को बताया कि जनता की समस्याओं का समाधान शिविर में प्रमुखता से समाधान किया जा रहा है। शेष बची लंबित समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान कर दिया जाएगा। अतिरिक्त उपायुक्त ने इसके उपरांत लघु सचिवालय के सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होने समाधान शिविर, सीपी ग्राम, जनसंवाद, सीएम विंडो, एसएमजीटी की लंबित शिकायतों की समीक्षा की और अगली बैठक तक सभी विभाग अपनी लंबित समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि समाधान शिविर में आने वाले प्रत्येक नागरिक की समस्या का जल्द से जल्द समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि जिलावासी अपनी समस्या के समाधान के लिए परेशान न हों। इस कार्य में किसी भी प्रकार का अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नही किया जाएगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को लंबित समस्याओं का अगली बैठक तक समाधान करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर एसडीएम चंद्रकांत कटारिया, नगराधीश जागृति, वन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी विशाल कौशिक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के ईओ सुरेंद्र सिंह, पब्लिक हेल्थ के कार्यकारी अभियंता समीर शर्मा, एसीपी अजीत सिंह, जिला विकास एवं पंचायत विभाग, जिला बागवानी विभाग, पुलिस विभाग, नायब तहसीलदार, खेल विभाग, स्वास्थ्य, शिक्षा, वन विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

निपुण हरियाणा मिशन के अंतर्गत फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी सम्पन्न

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

एनसीईआरटी की परख यूनिट तथा एससीईआरटी की आकलन विंग के संयुक्त तत्वावधान में 6, 7 एवं 8 मई 2026 को पंचकूला जिले में एफएलएस परीक्षा 2026 का सफल आयोजन किया गया। यह आयोजन डॉ. इंद्राणी भादुड़ी, सीईओ एवं विभागाध्यक्ष, परख के निर्देशन में सम्पन्न हुआ। पंचकूला जिले में जिला स्तरीय समन्वयक डॉ. मोनिका कुक्कड़ तथा एफएलएन कोऑर्डिनेटर असिन्द्र कुमार द्वारा परीक्षा की सुपरविजन की गई। परीक्षा आयोजन से पूर्व 4 एवं 5 मई को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट), पंचकूला में दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में सात फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स को टैबलेट उपलब्ध करवाए गए तथा उन्हें टैबलेट के माध्यम से सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया, क्योंकि प्रश्नपत्रों का मूल्यांकन टैबलेट पर ही किया जाना था।

पंचकूला जिले के तीनों खंडों से कुल 6 विद्यालयों का चयन एससीईआरटी द्वारा किया गया, जिनमें दो निजी तथा चार सरकारी विद्यालय शामिल थे। प्रत्येक विद्यालय से 12 विद्यार्थियों का आकलन किया जाना निर्धारित था। विद्यार्थियों का चयन सैंपलिंग पद्धति के आधार पर किया गया। इस परीक्षा के सफल एवं सुचारु संचालन हेतु डीपीसी जोगिंन्द्र लाठर, उप जिला शिक्षा अधिकारी रमेश बत्रा एवं नरोत्तम शर्मा, प्रिंसिपल बल्दवाला किरण गुप्ता, डाइट के वरिष्ठ प्रवक्ता श्रीमती रश्मि शर्मा एवं श्रीमती मंजीत कौर द्वारा सतत मॉनिटरिंग की गई।

संक्षिप्त-समाचार

ट्रांसजेंडर आश्रय गृह संचालित करने के लिए आवेदन मांगे

चंडीगढ़। सामाजिक कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली के सहयोग से संचालित SMILE Scheme के अंतर्गत गरिमा गृह (ट्रांसजेंडर व्यक्तियों हेतु आश्रय गृह) स्थापित एवं संचालित करने के लिए यू.टी. चंडीगढ़ में पात्र सामुदायिक आधारित संगठनों /गैर-सरकारी संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक सामुदायिक आधारित संगठन /गैर-सरकारी संगठन गरिमा गृह की स्थापना हेतु विस्तृत औचित्य सहित निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं: विस्तृत परियोजना प्रस्ताव एवं औचित्य, पंजीकरण प्रमाण पत्र, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पिछले तीन वित्तीय वर्षों की वार्षिक रिपोर्टें, पिछले तीन वर्षों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, संस्था की परिसंपत्तियों की सूची, अन्य गृहों/परियोजनाओं के संचालन का अनुभव (यदि कोई हो), सरकार/अन्य एजेंसियों के साथ पूर्व में क्रियान्वित परियोजनाओं का विवरण, यू.टी. चंडीगढ़ में गरिमा गृह संचालित करने हेतु प्रस्तावित परिसर का विवरण और अन्य संबंधित/अनिवार्य दस्तावेज। पूर्ण प्रस्ताव निदेशक, सामाजिक कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, यू.टी. चंडीगढ़ के कार्यालय में दिनांक 31.05.2026 सायं 5:00 बजे तक अवश्य पहुंच जाने चाहिए।

पंचकूला जिले की मंडियों में सुचारू रूप से चल रहा है गेंहू की खरीद और उठान का कार्य

पंचकूला। जिला में रबी सीजन 2026-27 के दौरान गेंहू की खरीद एवं उठान का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा जिला की मंडियों में से अब तक 36165 मीट्रिक टन गेंहू की खरीद की गई और 32498 मीट्रिक टन गेंहू का उठान किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि सरकारी खरीद एजेंसियों हैफेड और हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा रायपुररानी, बरवाला और पंचकूला स्थित अनाज मंडियों में गेहूं की खरीद की जा रही है। उन्होंने बताया कि रायपुररानी अनाज मंडी से हैफेड द्वारा 4744 मीट्रिक टन गेंहू और हरियाणा वेयर हाउसिंग कोरपोरेशन द्वारा 13083 मीट्रिक टन गेंहू की खरीद की गई। इसी प्रकार बरवाला अनाज मंडी से हैफेड द्वारा 7850 मीट्रिक टन गेंहू और हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोशन द्वारा 8638 मीट्रिक टन गेंहू की खरीद की गई। इसके अलावा पंचकूला अनाज मंडी से हैफेड द्वारा 1850 मीट्रिक टन गेंहू की खरीद की गई। उन्होने बताया कि मंडियों में खरीद के साथ साथ उठान का कार्य भी सुचारू रूप से चल रहा है। रायपुररानी अनाज मंडी से हैफेड द्वारा 4374 मीट्रिक टन गेंहू और हरियाणा वेयर हाउसिंग कोरपोरेशन द्वारा 10307 मीट्रिक टन गेंहू का उठान किया गया। इसी प्रकार बरवाला अनाज मंडी से हैफेड द्वारा 7850 मीट्रिक टन गेंहू और हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोशन द्वारा 8638 मीट्रिक टन गेंहू का उठान किया गया। पंचकूला अनाज मंडी से हैफेड द्वारा 1329 मीट्रिक टन गेंहू का उठान किया गया।

श्री माता मनसा देवी मंदिर में चोला अर्पित करने की ऑनलाइन प्रक्रिया 17 मई 2026 से शुरू

पंचकूला। उपायुक्त एवं श्री माता मनसा देवी पूजास्थल बोर्ड के मुख्य प्रशासक श्री सतपाल शर्मा ने बताया कि श्री माता मनसा देवी (मुख्य मन्दिर, पटियाला मन्दिर व सती मन्दिर), पंचकूला, श्री काली माता मन्दिर, कालका व श्री चण्डीमाता मन्दिर, चण्डीमन्दिर में देवी को चोला अर्पित करने के लिये ऑनलाईन बुकिंग प्रक्रिया शुरू की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया के माध्यम से माता को 25 मई 2026 से 3 जुलाई 2026 की अवधि के दौरान चोला अर्पित करने के लिये ऑनलाइन बुकिंग 17 मई 2026 प्रातः 10 बजे से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आरम्भ होगी। सभी इच्छुक श्रदालु लाभ उठाने के लिए पूजास्थल बोर्ड की वैबसाईट पर रजिस्ट्रेशन कर प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं।

डॉ. रिमेश पाल को प्रतिष्ठित एएसीई राइजिंग स्टार इन एंडोक्रिनोलॉजी अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया

चंडीगढ़। पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (पीजीआईएमईआर), चंडीगढ़ के एंडोक्रिनोलॉजी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. रिमेश पाल को अप्रैल 2026 में अमेरिका के लास वेगास में आयोजित अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजी की वार्षिक बैठक में प्रतिष्ठित राइजिंग स्टार इन एंडोक्रिनोलॉजी अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। अअउए राइजिंग स्टार इन एंडोक्रिनोलॉजी अवार्ड एक अंतरराष्ट्रीय सम्मान है, जो प्रारंभिक करियर के प्रतिभाशाली एंडोक्रिनोलॉजिस्ट्स को क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजी, अकादमिक उत्कृष्टता तथा अनुसंधान में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। विशेष रूप से, डॉ. पाल अब तक किसी भारतीय संस्थान से इस सम्मान को प्राप्त करने वाले एकमात्र पुरस्कार विजेता हैं, जो भारत से एंडोक्रिनोलॉजी अनुसंधान के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दशार्ता है। डॉ. पाल का अकादमिक एवं क्लिनिकल कार्य एंडोक्रिनोलॉजी के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे मेटाबोलिक बोन डिजीज, ऑस्टियोपोरोसिस, सारकोपीनिया तथा टाइप-2 डायबिटीज मेलिटस, में विस्तृत है। उन्होंने प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक पत्रिकाओं में अनेक शोध-पत्र प्रकाशित किए हैं तथा एंडोक्राइन शिक्षा और अनुसंधान में सक्रिय योगदान दिया है। इसी वर्ष डॉ. पाल को ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडियन ओरिजिन द्वारा डॉ. आई.ए. मोदी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था।

पंचकूला नगर निगम चुनाव-2026 की सभी तैयारियां पूरीः उपायुक्त

पंचकूला। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सतपाल शर्मा ने बताया कि हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग के निदेर्शानुसार पंचकूला नगर निगम चुनाव-2026 की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मेयर तथा सभी 20 वार्डों के पार्षद पदों के लिए मतदान 10 मई को निर्धारित मतदान केंद्रों पर प्रातः 8 बजे से सायं 6 बजे तक होगा। उन्होंने बताया कि सभी वार्डों में 2 लाख 7 हजार 379 मतदाता है, जिसमें 1 लाख 8 हजार 227 पुरूष व 98 हजार 447 महिलाएं और 5 ट्रांसजेंडर शामिल है। वार्ड नंबर 1 में 5 हजार 713 पुरूष और 4 हजार 977 महिलाएं और 1 अन्य, वार्ड नंबर 2 में 5 हजार 658 पुरूष और 5 हजार 442 महिलाएं, वार्ड नंबर 3 में 4 हजार 857 पुरूष और 4 हजार 645 महिलाएं, वार्ड नंबर 4 में 5 हजार 258 पुरूष और 5 हजार 215 महिलाएं, वार्ड नंबर 5 में 5 हजार 454 पुरूष और 5 हजार 421 महिलाएं, वार्ड नंबर 6 में 4 हजार 359 पुरूष और 4 हजार 349 महिलाएं, वार्ड नंबर 7 में 5 हजार 786 पुरूष और 4 हजार 713 महिलाएं हैं।

समारोह में अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी, संस्थान पदाधिकारी एवं उनके परिवारजन भी साक्षी रहे

प्राथमिक प्रशिक्षण केन्द्र, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल भानू पंचकूला में 9 हिमवीर मुख्य धारा में शामिल, चयनित अभ्यर्थियों में दिखा उत्साह

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

प्राथमिक प्रशिक्षण केन्द्र, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल भानू, पंचकूला में आज 29वें स्पोर्टस कण्डेंस बैच के 4 राज्यों के 9 प्रशिक्षणार्थियों के दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। श्री राणा युद्धवीर सिंह, उप महानिरीक्षक, (एनटीसीडी एंड ए), भातिसी पुलिस इस समारोह के मुख्य अतिथि रहे।

श्री अवधेष नारायण, द्वितीय कमान एवं श्री हरबंस लाल, उप सेनानी द्वारा मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया। इस भव्य समारोह में अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी, संस्थान पदाधिकारी एवं उनके परिवारजन भी साक्षी रहे। इस परेड की कमान कान्स्टेबल/जीडी(रिक्रू०) रुपल यादव ने संभाली।

मुख्य अतिथि श्री राणा युद्धवीर सिंह, उपमहानिरीक्षक द्वारा सभी प्रशिक्षणार्थियों को बेसिक प्रषिक्षण पूर्ण करने के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी और कहा कि आज आप सभी प्रशिक्षणार्थी अपनी बेसिक ट्रेनिंग पूर्ण करने के उपरांत इस बल के हिमवीर परिवार में एक प्रशिक्षित सदस्य के रुप में शामिल हो गये हैं। आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको देश सेवा का अवसर आई०टी०बी०पी० जैसे अनुशासित बल में प्राप्त हुआ है।

उन्होने कहा कि आज पास आउट होने वाले सभी रिकरुट स्पोर्टस पृष्ठभूमि से हैं और सभी राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेलों में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं जो कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस के लिए गर्व की बात है। श्री राणा युद्धवीर सिंह, उप महानिरीक्षक ने कहा कि वह आशा करते हैं कि आप भा०ति०सी० पुलिस की विभिन्न केन्द्रीय टीमों का हिस्सा बनकर उत्कृष्ठ प्रदर्शन कर बल एवं देश का नाम रोशन करेंगे। अपने संबोधन में श्री राणा युद्धवीर सिंह ने कहा कि आपने जो इस केन्द्र में ज्ञान अर्जित किया है उसे कायम रखते हुये अपने जीवन में और अधिक सीखने का प्रयास करेंगे।

अंत में श्री राणा युद्धवीर सिंह, उप महानिरीक्षक द्वारा श्री अवधेश नारायण, द्वितीय कमान एवं श्री हरबंस लाल, उप सेनानी तथा उनकी प्रशिक्षकों की टीम को प्रशिक्षण सफलतापूर्वक करवानें पर बधाई तथा सभी प्रशिक्षणार्थियों को एवं उनके परिवारजनों को शुभकामनाएं दी।